[2023] 15 एस सी आर **621:2023** आईएनएससी **1051**

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.

सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

(2020 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 38) 06 दिसंबर, 2023

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,**

ऋषिकेश रॉय**,** पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** बी**.** पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्देः

पाँच न्यायाधीशों की वर्तमान संविधान पीठ के विचार के लिए प्राथमिक मुद्दा भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में 'कंपनी समूह सिद्धांत' की वैधता का निर्धारण और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत कार्यवाही के लिए इसकी प्रयोज्यता था।इससे पहले, क्लोरो नियंत्रण मामले में भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कंपनी समूह सिद्धांत को अपनाया और लागू किया गया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त सिद्धांत को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 45 में "दावे के माध्यम से या उसके तहत" वाक्यांश में पढ़ा था।'ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन' में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनियों के एक समूह के भीतर एक कंपनी द्वारा किया गया मध्यस्थता समझौता गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबद्धों को बाध्य कर सकता है, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जो हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बाध्य करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करती हैं।इस सिद्धांत पर कथित तौर पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि यह पार्टी की स्वायत्तता, अनुबंध की गोपनीयता और अलग कानूनी व्यक्तित्व जैसे स्थापित कानूनी सिद्धांतों में हस्तक्षेप करता है।

इसके अलावा, सहायक मुद्दे भी थे जैसे किः(i) क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के रूप में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की अनुमति देता है; (ii) क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 पक्षों के आचरण के आधार पर मध्यस्थता करने के इरादे के निर्धारण की अनुमति देती है; और (iii) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8,35 और 45 के तहत आने वाले वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा" की व्याख्या।

एड। ध्यान देंःसीजेआई, माननीय डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने अपने लॉर्डशिप, माननीय न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, माननीय न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसला सुनाया।माननीय न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा ने एक अलग सहमति वाला फैसला सुनाया।

621

622

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

मध्यस्थता-मध्यस्थता समझौता-मध्यस्थता के आधार के रूप में सहमतिः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):सर्वसम्मति विज्ञापन आईडीएम

एक वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए पक्षों के बीच आवश्यक आधार बनता है-चूंकि सहमति मध्यस्थता की आधारशिला है, इसलिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को जबरन मध्यस्थता समझौते का "पक्ष" नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से अनुबंध की गोपनीयता और पक्ष की स्वायत्तता के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।[पैरा 60,63]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** -एस. **2 (1)** (एच) आर/डब्ल्यूएस।**7** – "दलों" की परिभाषाः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):की परिभाषा

"मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (1) (एच) के तहत पक्षों में हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष दोनों शामिल हैं।[पैरा 165]

मध्यस्थता-एक मध्यस्थता समझौते के पक्षकार-निर्णय लेने की विधिः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):ए के हस्ताक्षर

समझौते पर पक्षकार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था की सहमति की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है-हालाँकि, यह परिणाम कि जिन व्यक्तियों या संस्थाओं ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे हमेशा सही नहीं हो सकते हैं-मध्यस्थता समझौते के लिए "पक्षकार" कौन है, यह मुद्दा मुख्य रूप से सहमति का मुद्दा है।[पैरा 66]

शब्द और वाक्यांश-मध्यस्थता समझौता-शब्द "गैर-हस्ताक्षरकर्ता"-का अर्थः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):शब्द "गैर -

हस्ताक्षरकर्ता, पारंपरिक "तीसरे पक्ष" के बजाय, उन स्थितियों का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं जहां मध्यस्थता के लिए सहमति हस्ताक्षर के अलावा अन्य साधनों के माध्यम से व्यक्त की जाती है-एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक व्यक्ति या संस्था है जो एक विवाद में फंस गया है जो एक मध्यस्थता का विषय है, हालांकि यह औपचारिक रूप से एक मध्यस्थता समझौते में प्रवेश नहीं किया है-गैर-623

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

हस्ताक्षरकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ अपने संबंधों और वाणिज्यिक दायित्वों के प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी के आधार पर, जो विषय वस्तु से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, वास्तव में हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच विवाद के लिए अजनबी नहीं हैं।[पारस 66,127]

मध्यस्थता-भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कंपनियों के समूह का सिद्धांत-प्रासंगिकता-सिद्धांत/सिद्धांतः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):समूह का

कंपनी सिद्धांत एक सहमति-आधारित सिद्धांत है जिसे एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बांधने के लिए पक्षों के वास्तविक इरादे की पहचान करने के लिए लागू किया गया है-कंपनियों के समूह के सिद्धांत को भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कई पक्षों और कई समझौतों से जुड़े जटिल लेनदेन के संदर्भ में पक्षों के इरादे को निर्धारित करने में इसकी उपयोगिता पर विचार करते हुए बनाए रखा जाना चाहिए।[पारस 81,165]

निगमित कानून-निगमित अलगाव का सिद्धांत-अलग कानूनी व्यक्तित्वः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):भीतर की इकाइयाँ

एक निगमित समूह का अलग कानूनी व्यक्तित्व होता है, जिसे धोखाधड़ी जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-एक मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के बीच का अंतर मौलिक है, और आर्थिक सुविधा का सहारा लेकर आसानी से संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है-कानूनी रूप से, एक मूल कंपनी के अधिकार और देनदारियों को सहायक कंपनी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, और इसके विपरीत, जब तक कि ऐसा करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार न हो-कंपनियों के समूह के सिद्धांत के आवेदन के लिए अंतर्निहित आधार समूह कंपनियों की निगमित अलगाव को बनाए रखने पर निर्भर करता है, जबकि मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को बांधने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे को निर्धारित करता है।[पारस 89,165]

मध्यस्थता-कंपनियों के समूह का सिद्धांत-सहमति के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनानाः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):निगमित संरचनाएँ

इक्विटी, संयुक्त उद्यम और अनौपचारिक गठबंधनों के आधार पर समूहों का रूप ले सकते हैं-मध्यस्थता कानून के संदर्भ में, चुनौती तब उत्पन्न होती है जब

समूह का केवल एक सदस्य मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करता है, अन्य सदस्यों के बहिष्कार के लिए-क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता कार्यवाही से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही वे उस विवाद में फंस गए हों जो मध्यस्थता का विषय है?– इस चुनौती की प्रतिक्रिया के रूप में, मध्यस्थता कानून ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को विकसित और अपनाया है, ताकि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने की अनुमति या मजबूर किया जा सके-कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अनुबंध व्यवस्था के आसपास की तथ्यात्मक परिस्थितियों का विश्लेषण करके पक्षों के इरादों का पता लगाने के लिए लागू किया जाता है।[पारस 96 और 97]

मध्यस्थता**-**कंपनियों के समूह का सिद्धांत**-**अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण**-**फ्रांस**,** इंग्लैंड**,** स्विट्जरलैंड**,** सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका में सिद्धांत की प्रयोज्यता पर पूर्ववर्ती**-**चर्चा की गई:

आयोजित **(**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** ऋषिकेश रॉय**,** जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.):**द**.**

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, किसी न किसी रूप में, एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए सहमति की औपचारिक आवश्यकता से परे चले गए हैं-एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने का मुद्दा एक तथ्य-विशिष्ट सी पहलू है-फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे क्षेत्राधिकारों में, एक व्यापक सहमति है कि मध्यस्थता के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की सहमति या व्यक्तिपरक इरादे को आचरण द्वारा साबित किया जा सकता है-इस तरह के व्यक्तिपरक इरादे को मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन या समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी के रूप में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य से प्राप्त किया जा सकता है-हालाँकि, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को सभी क्षेत्राधिकारों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है-क्षेत्राधिकार में[पैरा 58]

मध्यस्थता**-**कंपनियों के समूह का सिद्धांत**,** एक तथ्य आधारित सिद्धांत:

आयोजित **(**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** ऋषिकेश रॉय**,** जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.):**अस्तित्व।

कंपनियों के समूह का एक तथ्यात्मक तत्व है जो अदालत या न्यायाधिकरण के पास 625 है।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

पक्षों की सहमति का विश्लेषण करते समय विचार करना-यह अनिवार्य रूप से एक अभ्यास में मानदंडों की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है जो कई पक्षों और समझौतों से जुड़े जटिल लेनदेन के मामले में पक्षों की सहमति निर्धारित करने में प्रमुख है।[पैरा 102]

मध्यस्थता-कंपनियों के समूह का सिद्धांत-मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले को बांधने के लिए सभी पक्षों का आपसी इरादा-आपसी इरादे का निर्धारणः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):प्राथमिक परीक्षण

कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करना अंतर्निहित तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर पक्षों के इरादे का निर्धारण करना है-कंपनियों के समूह के सिद्धांत का उपयोग कॉर्पोरेट समूह के गैर-हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों द्वारा उपग्रह मुकदमेबाजी को रोकने का काम करेगा, जिससे पक्षों के बीच समझौते की प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी-कार्यवाही की बहुलता और विवादों के विखंडन से बचना निश्चित रूप से न्याय के हित में है-हालाँकि, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करना कभी भी एकमात्र विचार नहीं हो सकता है।[पैरा 109]

मध्यस्थता-कंपनियों के समूह का सिद्धांत-प्रयोज्यता-साक्ष्य का सीमा मानकः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):खोज में

उद्यमों के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संचयी कारकों को संशोधित और स्पष्ट किया कि अदालतों और न्यायाधिकरणों को यह तय करने में विचार करना चाहिए कि क्या कंपनियों के समूह के भीतर एक कंपनी मध्यस्थता समझौते से बाध्य है-डिस्कवरी एंटरप्राइजेज मामले में निर्धारित सभी संचयी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जब कंपनियों के समूह की प्रयोज्यता का निर्धारण किया जाए सिद्धांत-हालांकि, उपरोक्त कारकों का अनुप्रयोग तथ्य-निर्दिष्ट सी होना चाहिए, और एक यह निर्धारित करके अदालतों या न्यायाधिकरणों के हाथों को बांध नहीं सकता है कि उन्हें उपरोक्त कारकों को कितना महत्व देना चाहिए-एकल आर्थिक इकाई का सिद्धांत कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।[पैरा 110,128 और 165]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996**।**8** और **45-**एस. एस. के तहत प्रकट होने के रूप में वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना"।**8** और मध्यस्थता अधिनियम के **45-**मध्यस्थता समझौते के पक्षकार और व्यक्ति

"मध्यस्थता समझौते के किसी पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करना अलग-अलग हैः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):एक व्यक्ति का दावा

"के माध्यम से या उसके तहत" एक मध्यवर्ती या व्युत्पन्न क्षमता में अपनी कानूनी मांग या कार्रवाई के कारण का दावा कर रहा है-एक व्यक्ति "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला" उस पक्ष की तुलना में हीन या अधीनस्थ अधिकार रखता है जिससे वह अपना दावा या अधिकार प्राप्त कर रहा है-इसलिए, एक व्यक्ति "जिसके माध्यम से या उसके तहत दावा कर रहा है" अपनी शर्तों पर मध्यस्थता समझौते का "पक्ष" नहीं हो सकता है क्योंकि यह केवल मूल हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के स्थान पर है-मध्यस्थता अधिनियम के तहत, "पक्ष" की अवधारणा "मध्यस्थता समझौते के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों" की अवधारणा से अलग और अलग है-"के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" केवल व्युत्पन्न क्षमता में एक अधिकार का दावा कर सकते हैं। [पैरा 137,165]

शब्द और वाक्यांश-"के माध्यम से या के तहत दावा करना"; "दावा"; "के माध्यम से" और "के तहत दावा करना"।[पैरा 137]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 9-न्यायालयों की यू/एस द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति।9:

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):समूह का

कंपनी सिद्धांत मध्यस्थता समझौते के लिए एक "वास्तविक" पक्ष के रूप में गैर-हस्ताक्षरकर्ता में शामिल होने के आपसी इरादे को निर्धारित करने पर आधारित है-एक बार जब एक न्यायाधिकरण इस निर्धारण पर आ जाता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है, तो ऐसा गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष एस के तहत अंतरिम उपायों के लिए आवेदन कर सकता है।9 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।[पैरा 153]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।8 और 11-निर्देश स्तर पर निर्धारण का मानक-मध्यस्थता अधिनियम के तहत कंपनियों के समूह के सिद्धांत की प्रयोज्यता का चरणः

आयोजित (डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार) (अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.):जब एक गैर -

हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति या संस्था को धारा 8 या धारा 11 के चरण में एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, रेफरल अदालत को प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते की वैधता या अस्तित्व का निर्धारण करना चाहिए, जैसा भी मामला हो, और यह तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता 627 द्वारा बाध्य है।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

मध्यस्थता समझौता-रेफरल चरण में, रेफरल अदालत को यह तय करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते से बाध्य है। [पैरा 163,165]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996 -**एस**. 7-**लिखित मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता यू/एस।**7 –** इफ़ेक्ट इक्टः

आयोजित **(**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** ऋषिकेश रॉय**,** जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.):**आवश्यकताएं

एक लिखित मध्यस्थता समझौते का यू/एस।7 गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बाध्य करने की संभावना को बाहर नहीं करता है।[पैरा 165]

मध्यस्थता**-**कंपनियों के समूह का सिद्धांत**-**क्या अहंकार को बदलने या कॉर्पोरेट पर्दा को भेदने का सिद्धांत कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग का आधार हो सकता हैः

आयोजित **(**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** ऋषिकेश रॉय**,** जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.):**का सिद्धांत

आल्टर इगो इक्विटी और सद्भावना के प्रमुख विचारों को ध्यान में रखते हुए निगमित अलगाव और पक्षों के इरादों की अवहेलना करता है-इसके विपरीत, कंपनियों के समूह का सिद्धांत विचाराधीन इकाई के कानूनी व्यक्तित्व को परेशान किए बिना मध्यस्थता समझौते के लिए सही पक्षों को निर्धारित करने के लिए पक्षों के इरादे की पहचान की सुविधा प्रदान करता है-अहंकार को बदलने या निगमित घूंघट को भेदने का सिद्धांत कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग का आधार नहीं हो सकता है।[पैरा 104,165]

मध्यस्थता**-**कंपनियों के समूह का सिद्धांत**-**सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए विचार किए जाने वाले कारक**-**गैर**-**हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का आचरण**-**प्रासंगिकताः

आयोजित **(**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** ऋषिकेश रॉय**,** जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.):**भागीदारी

अंतर्निहित अनुबंध के प्रदर्शन में गैर-हस्ताक्षरकर्ता का होना अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा विचार किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है-मध्यस्थता समझौते से बंधे होने के लिए पक्षों के इरादे का अंदाजा उन परिस्थितियों से लगाया जा सकता है जो बातचीत, प्रदर्शन और इस तरह के समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध की समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष की भागीदारी को घेरती हैं-बातचीत, प्रदर्शन या अनुबंध की समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी अनुबंध से बंधी होने की निहित सहमति को जन्म दे सकती है-अनुबंध का संचालन

गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष मध्यस्थता समझौते द्वारा बाध्य होने के लिए उनकी सहमति का एक संकेतक हो सकते हैं।[पारस 118,125 और 165]

मध्यस्थता-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** -एस. **2 (1) (**एच**)** और एस.**7** – कंपनियों के समूह का सिद्धांत-स्वतंत्र अस्तित्व हैः

आयोजित **(**डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.**):**समूह का

कंपनी सिद्धांत का कानून के सिद्धांत के रूप में एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो एस के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से उत्पन्न होता है।2(1)(ज) एस के साथ।7 मध्यस्थता अधिनियम। [पैरा 165]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996**-कंपनियों के समूह का सिद्धांत-क्लोरो नियंत्रण मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त सिद्धांत को एस में "दावे के माध्यम से या उसके तहत" वाक्यांश में पढ़ा।**45** मध्यस्थता अधिनियम-चुनौती।

आयोजित **(**डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए, ऋषिकेश रॉय, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.**):**का दृष्टिकोण

क्लोरो कंट्रोल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस हद तक कि उसने कंपनियों के समूह के सिद्धांत का पता "माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश से लगाया, गलत है और अनुबंध कानून और निगमित कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।[पैरा 165]

मध्यस्थता-कंपनियों का समूह सिद्धांत-प्रयोज्यता-गैर-हस्ताक्षरकर्ता, यदि मध्यस्थता समझौते का पक्षकार है-निर्धारण-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** -एस. **7 (4) (**बी**)**।

आयोजित **(**पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. के अनुसार**) (**डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के साथ सहमति व्यक्त करते हुए**):**विवादों को संदर्भित करने के लिए एक समझौता

मध्यस्थता के लिए एक लिखित रूप में होना चाहिए, जैसा कि एक मौखिक समझौते के खिलाफ है, लेकिन पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है।7(4)(बी), एक अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण यह निर्धारित करेगा कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता समझौते के रिकॉर्ड में पक्षों द्वारा नियोजित स्पष्ट भाषा की व्याख्या करके, अनुबंध के गठन, प्रदर्शन और निर्वहन की आसपास की परिस्थितियों के साथ मिलकर मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है-अनुबंध की व्याख्या और निर्माण करते समय, अदालतें या न्यायाधिकरण अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को अपना सकते हैं, जो उचित निर्णय और निर्धारण में सहायता और सहायता करते हैं-कंपनियों के समूह का सिद्धांत ऐसा ही एक सिद्धांत है।[पैरा 56] 629

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

मध्यस्थता-कंपनियों के समूह का सिद्धांत-मध्यस्थता समझौता-गैर-हस्ताक्षरकर्ता के इरादे को प्रमाणित करना।

आयोजित **(**पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. के अनुसार**) (**डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई के साथ सहमति व्यक्त करते हुए**):**कंपनी समूह का सिद्धांत

मध्यस्थता समझौते में पक्षकार बनने के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता के इरादे का पता लगाने पर भी आधारित है-इस सिद्धांत के लिए हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ प्रत्यक्ष संबंध, विषय-वस्तु की समानता, लेन-देन की समग्र प्रकृति और अनुबंध के प्रदर्शन जैसे अतिरिक्त कारकों से इरादे को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है।[पैरा 56]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996 -**एस**. 7 (4) (**बी**)-**एस**.** के तहत एक अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जांच।**7(4)(**ख**)** और कंपनियों के समूह का सिद्धांत।

आयोजित **(**पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** के अनुसार**) (**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई के साथ सहमति व्यक्त करते हुए**):**ए द्वारा जाँच के उद्देश्य से

न्यायालय या मध्यस्थता न्यायाधिकरण यू/एस।7(4)(ख) और कंपनियों के समूह का सिद्धांत समान है, सिद्धांत को एस के भीतर शामिल किया जा सकता है।7(4)(बी) एक अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों की सही मंशा और सहमति निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए-सिद्धांत एस की वैधानिक व्यवस्था के भीतर समाहित किया जाता है।7(4)(ख) निश्चितता और कानून के व्यवस्थित विकास के उद्देश्य से। [पैरा 56]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996**।**2(1)(**ज**), 7,8** और **45-**एस**.** एस**.** में **"**दावा करने के माध्यम से या उसके तहत**"** अभिव्यक्ति।**8** और **45-**एस में अभिव्यक्ति **'**पार्टी**'** से अलग अभिव्यक्ति।**2(1)(**ज**)** और **7**।

आयोजित **(**पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** के अनुसार**) (**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई के साथ सहमति व्यक्त करते हुए**):**अभिव्यक्ति **"**दावा**"**

एसएस में "के माध्यम से या उसके नीचे।8 और 45 का उद्देश्य एक व्युत्पन्न अधिकार प्रदान करना है; और यह एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष बनने में सक्षम नहीं बनाता है-क्लोरो कंट्रोल्स में निर्णय एस. एस. में "के माध्यम से या उसके तहत दावा" वाक्यांश के माध्यम से कंपनी समूह के सिद्धांत का पता लगाता है।8 और 45 गलत है-एस में अभिव्यक्ति 'पार्टी'।2(1) (ज) और एस।7 "उनके माध्यम से या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों" से अलग है।[पैरा 56]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ के फैसले में**,** सीजेआई

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफी कैशन इंक

(2013) 1 एससीसी 641:[2012] 13 एस. सी. आर. 402-आयोजित, कुछ हद तक गलत।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड, (2022) 8 एससीसी 42:[2022] 4 एस. सी. आर. 926-एफ़ी आर. एम. डी.

चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तूरी एंड संस लिमिटेड (2018) 16 एस. सी. सी. 413: [2018] 4 एस. सी. आर. 1063; महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनामकेनरा बैंक

(2020) 12 एससीसी 767:[2019] 11 एस. सी. आर. 660; सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पांड्या (2003) 5 एस. सी. सी. 531:[2003] 3 एस. सी. आर. 558; इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम वेसकेयर (आई) लिमिटेड (2010) 5 एस. सी. सी. 305:[2010] 5 एस. सी. आर. 284; भावेन निर्माण

v. कार्यकारी अभियंता, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (2022) 1 एस. सी. सी. 75; सुमितोमो निगम बनाम सी. डी. सी. वित्तीय सेवा (मॉरीशस) लिमिटेड,

(2008) 4 एससीसी 91:[2008] 3 एससीआर 309; एस. एन. प्रसाद बनाम मोनेट फाइनेंस लिमिटेड (2011) 1 एससीसी 320:[2010] 13 एस. सी. आर. 207; अमित लालचंद शाह बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज, (2018) 15 एस. सी. सी. 678:[2018] 6 एस. सी. आर. 1001; रेकिट बेंकिजर

(भारत) प्राइवेट लिमिटेड बनाम रेंडर्स लेबल प्रिंटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2019) 7 एस. सी. सी. 62:[2019] 8 एस. सी. आर. 966; भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर

एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा (2016) 4 एस. सी. सी. 126:[2016] 1 एससीआर 364;

सतीश कुमार बनाम सुरिंदर कुमार [1969] 2 एससीआर 244; बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (2003) 7 एससीसी 418: [2003] 2 पूरक।एस. सी. आर. 81; धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1968] 3 एस. सी. आर. 662; विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1: [2020] 11 एससीआर 1001; एमसी चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (1969) 2 एससीसी 343:[1970] 1 एससीआर 658; हाजी मोहम्मद इशाक बनाम मोहम्मद इकबाल

(1978) 2 एससीसी 493:[1978] 3 एससीआर 571; शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड बनाम कोला शिपिंग लिमिटेड (2009) 2 एससीसी 134:[2008] 13 एस. सी. आर. 925; ट्राइमेक्स इंटरनेशनल

एफ. जेड. ई. लिमिटेड बनाम वेदांत [2022] 4 एस. सी. आर. 926; एल्यूमीनियम लिमिटेड (2010) 3 एस. सी. सी. 1:[2010] 1 एससीआर 820; ग्रेट ऑफ शोर लिमिटेड बनाम। ईरानी अपतटीय इंजीनियरिंग

और निर्माण कंपनी, (2008) 14 एस. सी. सी. 240:[2008] 12 एस. सी. आर. 515; एस. एन. प्रसाद बनाम मोनेट फाइनेंस लिमिटेड (2011) 1 एस. सी. सी 320:[2010] 13 एससीआर 207;

गोविंद रबर लिमिटेड बनाम मेसर्स लुई ड्रेफस कमोडिटीज, (2015) 13 एससीसी 477: [2014] 12 एससीआर 488; सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (1999) 2 एससीसी 479:[1999] 1 एस. सी. आर. 89; पी. मनोहर रेड्डी और ब्रदर्स बनाम महाराष्ट्र 631

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

कृष्णा घाटी विकास निगम (2009) 2 एस. सी. सी. 494:[2008] 17 एस. सी. आर. 1217; टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनामबिहार राज्य

[1964] 6 एस. सी. आर 885; एल. आई. सी. बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड (1986) 1 एस. सी. सी. 264:[1985] 3 पूरक।

एससीआर 909; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड।

(1996) 4 एससीसी 662:[1996] 2 पूरक।एससीआर 295; कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य (2003) 6 एससीसी 1:[2003] 1 पूरक।एससीआर 175; बलवंत राय सलूजा बनाम एयर इंडिया (2014) 9 एससीसी 407:[2014] 14 एससीआर 1512; वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी बनाम भारत संघ (2012) 6 एससीसी 613:[2012] 1 एससीआर 573; कमला देवी बनाम तख्तमल लैंड, एआईआर 1964 एससी 859:[1964] 2 एससीआर 152; बैंगलोर

विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम ई. एस. सोलर पावर (पी) लिमिटेड (2021) 6 एस. सी. सी. 718:[2021] 1 एससीआर 453; बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास (2009) 5 एससीसी 313:[2009] 1 एस. सी. आर. 1045; एम. दयानंद रेड्डी बनाम ए. पी. औद्योगिक अवसंरचना

निगम लिमिटेड (1993) 3 एस. सी. सी. 137:[1993] 2 एस. सी. आर. 629; ए अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम, (2016) 10 एस. सी. सी. 386:[2016] 11 एस. सी. आर. 521; भारत संघ बनाम डी. एन. रेवरी, (1976) 4 एस. सी. सी. 147:[1977] 1 एससीआर 483; रूप कुमार बनाम मोहन थेदानी, (2003) 6 एससीसी 595:[2003] 3 एससीआर 292; ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम मीना विजय खेतान, (1999) 5 एससीसी 651:[1999] 3 एससीआर 490;

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2014) 7 एस. सी. सी. 603:[2014] 6 एससीआर 456; एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1:[2014] 2 एस. सी. आर. 855; एग्री गोल्ड एक्जिम्स लिमिटेड बनाम श्री लक्ष्मी निट्स एंड वोवेन्स, (2007) 3 एस. सी. सी. 686:[2007] 1 एस. सी. आर. 1161; एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005)

8 एससीसी 618:[2005] 4 पूरक।एस. सी. आर. 688; उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण

निगम लिमिटेड बनाम.उत्तरी कोयला क्षेत्र, (2020) 2 एस. सी. सी. 455; प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (2021) 5 एस. सी. सी. 671:[2021] 1 एस. सी. आर. 1162; शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम.अक्ष ऑप्टिफी ब्रे लिमिटेड (2005) 7

एससीसी 234:[2005] 2 पूरक।एससीआर 699 और डॉयचे पोस्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड बनाम.तडूरी श्रीधर (2011) 11 एस. सी. सी. 375:[2011] 5 एस. सी. आर. 674-संदर्भित।

डाउ केमिकल बनाम इसोवर सेंट गोबेन, अंतरिम पुरस्कार, आई. सी. सी. केस नं. 4131, 23 सितंबर 1982; पेरिस कोर्ट ऑफ अपील, 7 दिसंबर 1994, वी 2000 (पूर्व में जगुआर फ्रांस) बनाम प्रोजेक्ट एक्सएस, रेव। अरब। (1996) 67; ए, बी, सी बनाम डी और लीबिया राज्य, 4 ए 636/2018; 5 सऊदी ब्यूटेक लिमिटेड एट अल फौज ट्रेडिंग बनाम सऊदी अरब साइपेम लिमिटेड, 25 अक्टूबर 1994 का अप्रकाशित आईसीसी अंतरिम पुरस्कार, 29 जनवरी 1996 को डीएफटी द्वारा घोषित, एएसए बुलेटिन (1996) खंड 3 पी 496; एक्स बनाम वाई इंजीनियरिंग एस. पी.ए. और वाई. एसपी.ए., 4 ए. 450/2013, एएसए बुल।, 160 (2015); पीटरसन फ़ार्म्स आई. एन. सी. बनाम सी. एंड एम. फ़ार्मिंग लिमिटेड, [2004] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 121; रूसल-उक्लाफ़ बनाम जी. डी. सियरले एंड कंपनी लिमिटेड [1978] 1 लॉयड का प्रतिनिधि; द

मेयरलिटी एंड कॉमनलिटी एंड सिटिजन्स ऑफ द सिटी ऑफ लंदन बनाम अशोक संचेती, [2008] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1283; ब्लैकपूल एंड फिल्डे एयरो क्लब लिमिटेड बनाम।ब्लैकपूल बरो काउंसिल, [1990] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1195; डल्ला रियल एस्टेट एंड टूरिज्म होल्डिंग कंपनी बनाम धार्मिक मामलों के मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार [2010] यूकेएससी 46; मनुचर स्टील हांगकांग लिमिटेड बनाम स्टार पैसिफी सी लाइन पीटीई लिमिटेड [2014] एसजीएचसी 181; जी. ई. एनर्जी पावर कन्वर्जन फ्रांस एसएएस बनाम आउटोकुम्पू स्टेनलेस, 140 एस. सी. टी. 1637 (2020); अमेरिकन फ्यूल कॉर्प बनाम यूटा एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, इंक, 122 एफ. 3 डी 130,134 (2 डी सिर 1997); अमेरिकन ब्यूरो, शिपिंग बनाम टेनकारा शिपयार्ड, 170 एफ. 3 डी 349,353 (2 डी सिर 1999); सनएलियांज स्पा, [2012] ईडब्ल्यूसीए सीवी 27; टैनिंग रिसर्च लैबोरेटरीज इंक बनाम ओ 'ब्रायन, [1990] एचसीए 8; राइनहार्ट बनाम हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग पीटीवाई लिमिटेड।

[2019] एच. सी. ए. 13-संदर्भित।

भारतीय विधि आयोग, 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन', रिपोर्ट सं। 246 (अगस्त 2014); बर्नार्ड हनोटियाउ और लियोनार्डो ओहलरॉग, 'डाउ केमिकल अवार्ड की 40 वीं वर्षगांठ' 40 (2) एएसए बुलेटिन 300-308; यवेस डेरेंस, 'क्या कंपनियों के सिद्धांत का एक समूह है?' आईसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड बिजनेस लॉ के डोजियर में बर्नार्ड हनोटियाउ और एरिक श्वाट्र्ज (संस्करण), खंड 7,131-145; ऑडली विलियम शेपर्ड, 'अंग्रेजी मध्यस्थता कानून में तीसरे पक्ष के गैर-हस्ताक्षरकर्ता' में स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, जूलियन ल्यू, एट अल (संस्करण) द इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 2016) 183-198; चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ह्यूग बील (संस्करण), (32 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, 2015) पैरा 2-169 और पैरा 1-104; एंड्रिजाना मिसोविक, 'बाइंडिंग नॉन-सिग्नेटरीज टू आर्बिट्रेट'संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण '(2021) 37 (3) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 749-768; बर्नार्ड हनोटियाउ,' एक मध्यस्थता खंड को गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं तक बढ़ाया जा सकता है:व्यक्ति, राज्य या समूह की अन्य कंपनियाँ?

' 633

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

जटिल मध्यस्थताओं में:बहु-पक्षीय, बहु-अनुबंध, बहु-मुद्दा-एक तुलनात्मक अध्ययन 'बर्नार्ड हनोटियाउ (संस्करण) (दूसरा संस्करण, 2020) 95,194; गैरी बोर्न, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कानून और अभ्यास (तीसरा संस्करण, 2021); पोलॉक और मुल्ला, भारतीय अनुबंध और विशिष्टता सी राहत अधिनियम (14 वां संस्करण, 2016) 235; स्टावरोस ब्रेकोलाकिस,' अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में पुनर्विचार सहमति:ए जनरल थ्योरी फॉर नॉन-सिग्नेटरीज (2017) 8 जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट 610,621; इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पर UNCITRAL मॉडल लॉ, 10 जून 1958 को न्यूयॉर्क में किए गए विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन के अनुच्छेद II, पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद VII, पैराग्राफ 1 की व्याख्या के बारे में सिफारिश, (7 जुलाई 2006 को UNCITRAL द्वारा अपनाया गया) 39; रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (7 वीं संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2023) पैरा 2.23; जयती सरकार, अस्ली कोपलान, ताकाशी हिकिनो और जेम्स लिंकन में 'बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया' (संस्करण)क्या हम एक समान दृष्टि साझा करते हैं?' (2011) 27(4) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 539,554; स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, 'इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पार्टियाँ:'द इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन' (2016) 119,120 में स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, जूलियन डी. एम. ल्यू और अन्य (संस्करण) में सहमति बनाम वाणिज्यिक वास्तविकता; UNCITRAL, 'वाणिज्यिक विवादों का निपटान:वाणिज्यिक विवादों के निपटारे से संबंधित कुछ मुद्दों पर संभावित समान नियम:सुलह, संरक्षण के अंतरिम उपाय, मध्यस्थता समझौते का लिखित रूप:महासचिव की रिपोर्ट 'ए/सी. एन. 9/WG.II/WP.108/Add.1 (26 जनवरी 2000); स्टावरोस ब्रेकोलाकिस,' अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पार्टियाँ:स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, जूलियन डी. एम. ल्यू, एट अल में सहमति बनाम वाणिज्यिक वास्तविकता (संस्करण) 'अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का विकास और

भविष्य' (2016) 119,137,148; अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों के UNIDROIT सिद्धांत, 2016, अनुच्छेद 4.3; स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में पुनर्विचार सहमतिःगैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए एक सामान्य सिद्धांत (2017) 8 जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट 610,621; करीम यूसुफ, 'सहमति की सीमाएँःबहु-पक्षीय मध्यस्थता में कंपनियों के समूह में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के मध्यस्थता का अधिकार या दायित्वःआई. सी. सी. विश्व व्यापार कानून संस्थान के दस्तावेज, खंड 7 (2010) 71,79; मध्यस्थता पर रसेल (23 वां संस्करण, 2007) 99 पैरा 3-018; विक्की प्रिस्किच, 'मध्यस्थता समझौतों के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करना-एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति कौन हैं?' (2019) 35(3)

आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 375-386; ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण, 1979) 224; पी रामनाथ अय्यर, द लॉ लेक्सिकन (1997) 330,331; ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण, 1979) 1328; रोनाल्ड ड्वोर्किन, लॉ एम्पायर (बेल्कनैप प्रेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1986) 229-संदर्भित।

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा के निर्णय में**,** जे**.**

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनामसेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफाई कैटायन

, (2013) 1 एस. सी. सी. 641:[2013] 1 एस. सी. आर. 698-गलत माना गया।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2022) 8 एससीसी 1; विद्या द्रोलिया

बनाम दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1:[2020] 11 एससीआर 1001;

जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड (2022) 1 एससीसी 753; जुगल किशोर रामेश्वरदास बनाम गुलबाई होरमुसजी [1955] 2 एससीआर 857; कारवेल शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम प्रीमियर सी फूड्स एक्जिम

(पी) लिमिटेड (2019) 11 एस. सी. सी. 461:[2018] 14 एस. सी. आर. 289; रिकमर्स वेरवाल्टंग

जीएमबीएच बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1999) 1 एससीसी 1:[1998] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 42; एम. टी. एन. एल. बनाम केनरा बैंक, (2020) 12 एस. सी. सी. 767:[2019] 11 एससीआर 660;

बाबनराव राजाराम पुंड बनाम समर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, (2022) 9

एससीसी 691; के. के. मोदी बनाम के. एन. मोदी, (1998) 3 एससीसी 573:[1998] 1 एससीआर 601;

बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड

लिमिटेड (2003) 7 एससीसी 418:[2003] 2 पूरक।एससीआर 812; शक्ति भोग फूड्स बनाम कोला शिपिंग लिमिटेड (2009) 2 एससीसी 134:[2008] 13 एस. सी. आर. 925; स्मिता कंडक्टर बनाम यूरो मिश्र धातु, (2001) 7 एस. सी. सी. 728:[2001] 2 पूरक।एससीआर 477;

यूनिसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन

और अनुसंधान (2009) 1 एस. सी. सी. 107:[2008] 14 एस. सी. आर. 108; पावरटेक वर्ल्ड

वाइड लिमिटेड बनाम डेल्विन इंटरनेशनल जनरल ट्रेडिंग एल. एल. सी. (2012) 1 एस. सी. सी. 361:[2011] 13 एस. सी. आर. 122; गोविंद रबर बनाम लुईड्स ड्रेफस कमोडिटीज

एशिया प्राइवेट लिमिटेड (2015) 13 एस. सी. सी. 477:[2014] 12 एस. सी. आर. 488; निमेट संसाधन

आई. एन. सी. बनाम एस्सार स्टील्स लिमिटेड (2000) 7 एस. सी. सी. 497; बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बी. ई. एस. सी. ओ. एम.) बनाम ई. एस. सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (2021) 6 एस. सी. सी. 718; भारतीय खाद्य निगम बनाम अभिजीत पॉल 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1605;

बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास (2009) 5 एससीसी 313:[2009] 5 एससीआर 118;

गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 199: [1975] 2 एससीआर 42; मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006)

11 एससीसी 181:[2006] 2 पूरक।एससीआर 409; ओएनजीसी बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705:[2003] 3 एस. सी. आर. 691; रूप कुमार बनाम मोहन थेदानी (2003)

6 एससीसी 595:[2003] 3 एस. सी. आर. 292; सुकन्या होल्डिंग्स बनाम जयेश एच. पांड्या 635

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2003) 5 एससीसी 531:[2003] 3 एस. सी. आर. 558; इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम वेसकेयर (इंडिया) लिमिटेड (2010) 5 एस. सी. सी. 305:[2010] 5 एस. सी. आर. 284; ड्यूरो फेलगुएरा,

एस. ए. बनाम.गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एससीसी 729:[2017] 10 एस. सी. आर. 285; चेरन

प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तूरी एंड संस लिमिटेड (2018) 16 एस. सी. सी. 413: [2018] 4 एस. सी. आर. 1063; अमित लालचंद शाह बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज (2018) 15 एस. सी. सी. 678:[2018] 6 एससीआर 1001; ओएनजीसी बनाम डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (2022) 8 एससीसी 42; रेकिट बेंकिजर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम रेंडर्स लेबल प्रिंटिंग

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2019) 7 एससीसी 62:[2019] 8 एससीआर 966; एमटीएनएल बनाम केनरा बैंक (2020) 12 एससीसी 767:[2019] 11 एस. सी. आर. 660-संदर्भित।

डाउ केमिकल बनाम इसोवर सेंट गोबेन।आईसीसी मामला संख्या 4,131,23 सितंबर 1982; डल्ला रियल एस्टेट एंड टूरिज्म होल्डिंग कं. बनामधार्मिक मामलों के मंत्रालय का प्रसारण, पाकिस्तान सरकार का मामला सं. 9-28533, दिनांक 17 फरवरी 2011 (पेरिस कोर्ट डी 'एप्पेल), [2010] UKSC 46; मालाकॉफ कॉर्पोरेशन बरहाद और टी. एल. ई. एम. सी. ई. एन. विलवणीकरण निवेश कंपनी बनाम अल्जीरियाई ऊर्जा कंपनी एस. ए. और हाइफल यू. एक्स. लिमिटेड, मामला सं.

दिनांक 13 जून 2023 (पेरिस कोर डी 'एप्पेल); पीटरसन फ़ार्म्स इंक बनाम सी एंड एम फ़ार्मिंग लिमिटेड [2004] ईडब्ल्यूएचसी 121 (कॉम); मेयर और कॉमनलिटी एंड

लंदन शहर के नागरिक बनाम अशोक संचेती, [2008] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1283; बैंक ऑफ टोक्यो लिमिटेड बनाम करूण, [1987] ए. सी. 45; कबाब-जी एस. ए. एल. (लेबनान) बनाम कौत फूड ग्रुप (कुवैत), [2021] यू. के. एस. सी. 48; मनुचर स्टील हांगकांग लिमिटेड बनाम स्टार पैसिफी सी लाइन पीटीई लिमिटेड. [2014] एस. जी. एच. सी. 181; जी. ई. एनर्जी पावर कन्वर्जन फ्रांस एस. ए. एस. कॉर्प।, एफ. के. ए. कन्वर्टिम एस. ए. एस. बनाम आउटकुम्पू

स्टेइनलेस यूएसए, एल. एल. सी., आदि।, मामला सं. 18-1048 (1 जून 2020); मैकब्रो

नियोजन और देव। को. वी.त्रिभुज एलेक।कंस्ट्रक्टर।कं. इंक., 741 एफ. 2 डी 342 (11 वां सिर। 1984); नौरू फॉस्फेट रॉयल्टीज, इंक. बनाम।ड्रैगो डाइक इंटरेस्ट्स, इंक. 138 एफ. 3 डी 160 (5 वां सिर। 1998); सार्थक ग्रुप बनाम ओरेकल कॉर्प, 404 एफ. 3 डी

657 (2 एन. डी. सर। 2005)-संदर्भित।

लेविसन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स (छठा संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल 2016) पैरा 2,21,27; गैरी बॉर्न, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वॉल्यूम 1 (तीसरा संस्करण, क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2021) 1531; बर्नार्ड हनोटियाउ, 'चैप्टर 14:लुकास ए. मिस्टेलिस और जूलियन डी. एम. ल्यू (संस्करण) में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में कंपनियों का समूह, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में व्यापक समस्याएं, खंड 15 (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2006), 286; बर्नार्ड

हनोटियाउ, 'मध्यस्थता के लिए सहमतिः क्या हम एक समान दृष्टि साझा करते हैं?' (2011) 27(4) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 539-संदर्भित।

636

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 38।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6), धारा 11 (12) (ए) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए याचिका।

के साथ

2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8607 और 5833।

रूपः

नकुल दीवान, संजय घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता।, हीरू आडवाणी, दिव्यकांत लाहोटी, सुश्री मधुर झावर, सुश्री विंध्य मेहरा, परीक्षित आहूजा, सुश्री प्रवीणा बिष्ट, कार्तिक लाहोटी, सुश्री गरिमा वर्मा, राहुल माहेश्वरी, सुश्री शिवांगी मल्होत्रा, नवदीप दहिया, सुश्री संजना खत्री, सुश्री रिया गर्ग, मानव नागपाल, करनदीप दहिया, जीवन बल्लव पांडा, सुश्री शालिनी सती प्रसाद, सतीश पाधी, सुश्री मेहर टंडन, गौरव शर्मा, सुश्री धृति मेहता, रोहन नाइक, सुश्री नूरीन सरना, नील चटर्जी, सुश्री तानसी फोतेदार, सतविक चंद्रशेखर, रोहन मंडल, एम/एस।याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., डेरियस जे. खंबाटा, रितिन राय, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रजत नायर, कार्तिकेय अग्रवाल, परांतप सिंह, रोहित, रोहन बत्रा, सुश्री सोनाली मलिक, हर्षवर्धन अरोड़ा, तुषार हाथीरामानी, ऋषभ भार्गव, ध्रुव सेठी, सुश्री विधि शाह, फरहाद सोराबजी, धीरज नायर, मनीष झा, कुमार किस्ले, प्रतीक पवार, सिद्धेश प्रधान, सुश्री शनाया साइरस ईरानी, सुश्री ऐश्वा जैन, यशवर्धन, सुश्री स्मिता कांत, अपूर्व शुक्ला, पुनीत चाहर, सुश्री प्रभलीन ए. शुक्ला, सुश्री इशिता फरसैया, सुश्री कृतिका नागपाल, चंद्रताय चौबे, तुषार अरोड़ा, अनिरुद्ध कृष्णन, बालाजी श्रीनिवासन।उत्तरदाताओं के लिए।

कपिल सिब्बल, डॉ. ए. एम. सिंघवी, ए. एन. हक्सर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अजय भार्गव, श्रीमती वनिता भार्गव, असीम चतुर्वेदी, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, मिलिंद शर्मा, सुश्री मनीषा सिंह, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, उज्ज्वल ए. राणा, मेसर्स गगरत एंड कंपनी के लिए हिमांशु मेहता, पल्लव मोंगिया, देबेश पांडा, प्रत्यूष मिगलानी, उमर अहमद, प्रणव मागो, उदभव गाडी, सुश्री।

637

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

चंद्रिका शर्मा, श्री आदित्य कुमार, कनिष्क अग्रवाल, वास देव वर्मा, जॉर्ज पोथन पूथिकोट, सुश्री मनीषा सिंह, सुश्री ज्योति सिंह, आशु पाठक, अरुणव मुखर्जी, अधिवक्ता।हस्तक्षेप करने वालों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई टेबल ऑफ कंटेंट *

ए. संदर्भ. 4 बी. प्रस्तुतियाँ. 7 सी. कानूनी पृष्ठभूमि. 16 i.भारत.. 16 ए.क्लोरो नियंत्रण. 20 बी।क्लोरो नियंत्रण के बाद कानून का विकास। 24 ii.फ्रांस-डाउ केमिकल्स मामला। 29 iii.स्विट्जरलैंड. 33 iv.इंग्लैंड. 34 बनाम सिंगापुर. 37 vi.संयुक्त राज्य अमेरिका. 38 डी. मध्यस्थता समझौता. 41 i.मध्यस्थता के आधार के रूप में सहमति. 41 ii.मध्यस्थता समझौते के पक्षकार. 45 ई. कंपनियों का समूह सिद्धांत. 56 i.अलग कानूनी व्यक्तित्व. 56 ii.सहमति के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना। 61 iii.कंपनियों के समूह का सिद्धांत-एक तथ्य आधारित सिद्धांत।

*एड। ध्यान दें:मूल निर्णय के अनुसार पृष्ठांकन।

638

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

iv.आपसी इरादे का निर्धारण. 70 बनाम सीमा मानक. 80 एफ. कंपनियों के समूह का सिद्धांत स्वतंत्र है।

अस्तित्व. 85 i.पार्टी और व्यक्ति "के माध्यम से या उसके तहत दावा कर रहे हैं"

88 ii.क्लोरो में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण

नियंत्रण गलत है। 92 iii.न्यायालयों की निम्नानुसार निर्देश जारी करने की शक्ति

धारा. 97 जी. निर्देश स्तर पर निर्धारण का मानक -

धारा 8 और 11.98 एच. निष्कर्ष. 104

A. संदर्भ

1. एक सदी से भी पहले जेम्स जॉयस ने यूलिसिस प्रकाशित किया था।जॉयस ने चेतना की एक धारा का व्यापक रूप से उपयोग करके कथा तकनीक के साथ प्रयोग किया।अपनी आधुनिकतावादी कथा तकनीक में, युलिसिस को साहित्यिक आलोचकों और उपन्यासकारों द्वारा एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति के रूप में सम्मानित किया जाता है।व्लादिमीर नाबोकोव और टी. एस. इलियट जैसे उपन्यासकारों ने इसे कला की एक दिव्य कृति के रूप में सराहा।हालांकि, वर्जीनिया वूल्फ और एल्डस हक्सले जैसे अन्य लोगों ने उपन्यास की तकनीकी और उबाऊ होने के लिए आलोचना की। विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद, यूलिसिस की विरासत विशेष रूप से बनी हुई है क्योंकि इसकी प्रयोगात्मक कथा तकनीक ने पारंपरिक साहित्यिक शैली को चुनौती दी थी।इसी तरह का मामला कंपनियों के समूह के सिद्धांत का है-एक आधुनिक सिद्धांत जो मध्यस्थता कानून की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है।यह कुछ लोगों द्वारा मनाया जाता है, कई अन्य लोगों द्वारा इसकी निंदा की जाती है।फिर भी, इसकी विरासत जारी है।

2. इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों से भारतीय मध्यस्थता के न्यायशास्त्र में 'कंपनियों के समूह' सिद्धांत की वैधता निर्धारित करने के लिए कहा जाता है।

*एड। ध्यान दें:मूल निर्णय के अनुसार पृष्ठांकन।

639

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 640

इस सिद्धांत में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनियों के एक समूह के भीतर एक कंपनी द्वारा किया गया एक मध्यस्थता समझौता गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबद्धों को बाध्य कर सकता है, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जो हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बाध्य करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करती हैं।इस सिद्धांत पर कथित तौर पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह पार्टी की स्वायत्तता, अनुबंध की गोपनीयता और अलग कानूनी व्यक्तित्व जैसे स्थापित कानूनी सिद्धांतों में हस्तक्षेप करता है।इस न्यायालय के समक्ष चुनौती यह पता लगाने की है कि क्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत और निगमित कानून और अनुबंध कानून के अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिद्धांतों के बीच सुलह हो सकती है।

3. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम और सुलह 1996 1 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए भारतीय संदर्भ में कंपनियों के समूह के सिद्धांत की वैधता की इस आधार पर पुनः जांच करने की मांग की कि यह कानून के बजाय आर्थिक प्रभावशीलता पर अधिक आधारित है।तीन न्यायाधीशों की पीठ (मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा लिखित बहुमत की राय और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की सहमति वाली राय के माध्यम से बोलते हुए) ने भारतीय अदालतों द्वारा सिद्धांत के अनुप्रयोग की शुद्धता पर संदेह किया।

4. मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के दृष्टिकोण की आलोचना की

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर में इस न्यायालय का

कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अपनाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 में "दावे के माध्यम से या उसके तहत" वाक्यांश पर भरोसा करना।उन्होंने कहा कि इस न्यायालय के बाद के निर्णयों ने उन प्रावधानों में दिखाई देने वाले वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा" की व्याख्या की पर्याप्त जांच किए बिना धारा 8 और 35 में सिद्धांत को स्थापित किया।

इन फैसलों में शामिल हैं:चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तूरी एंड संस लिमिटेड 3, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाम।केनरा बैंक 4, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। 5 वह

यह भी देखा गया कि तंग समूह संरचना और अकेले एकल आर्थिक इकाई जैसी आर्थिक अवधारणाओं का उपयोग एक स्पष्ट सहमति के अभाव में एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए नहीं किया जा सकता है।नतीजतन, उन्होंने

1 “मध्यस्थता अधिनियम 2 (2013) 1 एस. सी. सी. 641 3 (2018) 16 एस. सी. सी. 413 4 (2020) 12 एस. सी. सी. 767 5 (2022) 8 एस. सी. सी. 42

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8,35 और 45 के तहत आने वाले "दावे के माध्यम से या उसके तहत" वाक्यांश की व्याख्या पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए मामले को वृहद पीठ को निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार करके भेजा गया:ए। क्या धारा 8 और धारा 11 में 'दावे के माध्यम से या उसके तहत' वाक्यांश की व्याख्या 'कंपनियों के समूह' सिद्धांत को शामिल करने के लिए की जा सकती है; और

बी। क्या क्लोरो कंट्रोल्स केस (उपरोक्त) और उसके बाद के निर्णयों द्वारा समझाया गया 'ग्रुप ऑफ कंपनीज' सिद्धांत कानून में मान्य है।

5. एक सहमति वाली राय में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) के समक्ष इस न्यायालय के निर्णय, में प्रस्तुत किए गए हैं

सुकन्या होल्डिंग्स **(**पी**)** लिमिटेड बनाम जयेश एच पांड्या **7** और इंडोविंड एनर्जी

लिमिटेड बनाम वेसकेयर (आई) लिमिटेड, 8 ने औपचारिक सहमति पर अनुचित जोर देकर एक "कठोर" और "प्रतिबंधात्मक" दृष्टिकोण अपनाया।न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत के विकास का पता लगाया और कहा कि इसने भारतीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण पायदान हासिल किया है।हालाँकि, उन्होंने राय दी कि इस न्यायालय ने भारत में इस सिद्धांत को लागू करते समय असंगत दृष्टिकोण अपनाया, जिसे एक बड़ी पीठ द्वारा स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।तदनुसार, उन्होंने वृहद पीठ द्वारा निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर

प्रकाश डालाःए। क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को अधिनियम की धारा 8 में पढ़ा जाना चाहिए या क्या यह किसी भी वैधानिक प्रावधान से स्वतंत्र भारतीय न्यायशास्त्र में मौजूद हो सकता है;

बी। क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को 'एकल आर्थिक वास्तविकता' के सिद्धांत के आधार पर लागू किया जाना चाहिए;ग. क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को पक्षों के बीच निहित सहमति या मध्यस्थता के इरादे की व्याख्या करने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए; और

6 धारा 11 का संदर्भ अनजाने में प्रतीत होता है क्योंकि उक्त प्रावधान में "के माध्यम से या उसके तहत दावा" वाक्यांश नहीं पाया गया है।बल्कि, धारा 11 को धारा 45 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जहां वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" दिखाई देता है।

7 (2003) 5 एस. सी. सी. 531

8 (2010) 5 एस. सी. सी. 303 641

घ. क्या अहंकार को बदलने और/या निगमित आवरण को भेदने के सिद्धांत ही निहित सहमति के अभाव में भी कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए दबाव डालने को उचित ठहरा सकते हैं।

6. हम मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें संदर्भ में उठाए गए व्यापक कानूनी मुद्दों को निपटाने के लिए कहा गया है।इस प्रक्रिया में, हम उपरोक्त कानूनी मुद्दों के साथ-साथ अन्य सहायक मुद्दों का जवाब देंगे जो वकील द्वारा हमारे सामने उठाए गए हैं।

B. प्रस्तुतियाँ

7. 2020 की मध्यस्थता याचिका संख्या 38 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री हीरू आडवाणी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दींःए। कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग का आधार मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौन या निहित सहमति है;

बी। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) के तहत "पक्ष" की अवज्ञा मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं तक ही सीमित नहीं हो सकती है।तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को भी शामिल करने के लिए परिभाषा को विस्तार से पढ़ा जाना चाहिए।

ग. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि पक्षों के बीच कानूनी संबंध गैर-संविदात्मक भी हो सकते हैं।इसके अलावा, धारा 7 (4) (बी) इंगित करती है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है यदि एक लिखित संचार के दौरान, उसने समझौते से बाध्य होने का इरादा प्रदर्शित किया है; और

घ. कंपनियों के समूह के सिद्धांत को आदर्श रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लागू किया जाना चाहिए।रेफरल के स्तर पर, अदालत को केवल प्रथम दृष्टया विचार करना चाहिए और मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए।

8. 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 8607 में उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डेरियस जे खंबाटा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:ए। कंपनियों के समूह के सिद्धांत की प्रयोज्यता की जांच इस कसौटी से की जानी चाहिए कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता हो सकता है

मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष बनाया।"किसी पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" अभिव्यक्ति इस सिद्धांत को लागू करने का आधार नहीं हो सकती है।बी। यह सिद्धांत एक सहमति वाला सिद्धांत है जो एक अवज्ञापूर्ण कानूनी संबंध और मध्यस्थता समझौते से बंधे पक्षों के आपसी इरादे से उत्पन्न होने वाले विवाद के अस्तित्व पर आधारित है।गैर-हस्ताक्षरकर्ता के इरादे का पता क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) में निर्धारित संचयी कारकों से लगाया जाना चाहिए।ग. गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते के लिए एक "वास्तविक" पक्ष के रूप में बाध्य करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

i. सभी पक्षों, दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं का पारस्परिक इरादा, मध्यस्थता समझौते से बाध्य होना;

ii.मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष द्वारा पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति; और

iii.ऐसी स्वीकृति या तो व्यक्त की जानी चाहिए या निहित होनी चाहिए।गैर-हस्ताक्षरकर्ता के संदर्भ में, ऐसी स्वीकृति निहित होगी और अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन या समाप्ति में प्रकट होगी;

घ. कानूनी संबंधों की अवहेलना से उत्पन्न विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पक्षों की आपसी सहमति एक मध्यस्थता समझौते का आवश्यक घटक है।किसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता को उनकी सहमति का पता लगाए बिना मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करना पक्ष की स्वायत्तता की अवधारणा के खिलाफ होगा।

ई. एक मध्यस्थता समझौते के लिए "पक्ष" की अवधारणा एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति की अवधारणा से अलग है।बाद की अभिव्यक्ति कार्रवाई के एक व्युत्पन्न कारण की धारणा को व्यक्त करती है जहां गैर-हस्ताक्षरकर्ता समझौते के तहत एक स्वतंत्र अधिकार का दावा करने के बजाय पार्टी के जूते में कदम रखता है।विशिष्ट परिदृश्य जहाँ कोई व्यक्ति किसी पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करता है, वे हैं कार्य, अधीनता और नवीनता; और

च. 'तंग समूह संरचना' और 'एकल आर्थिक इकाई' जैसी अवधारणाएं कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती हैं।इस सिद्धांत को गैर-हस्ताक्षरकर्ता 643 को बांधने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 644

केवल इस कारण से कि यह हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन है;

9. 2022 के आई. ए. सं. 92757 में हस्तक्षेप करने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:ए। कंपनियों के समूह का सिद्धांत हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों को मध्यस्थता समझौते के अधीन करने के लिए पक्षों के वास्तविक इरादे का एक सच्चा और वास्तविक प्रभाव बनाता है;

बी। यह सिद्धांत कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने के सिद्धांत का एक उचित और स्वाभाविक विस्तार है।जब सामान्य स्वामित्व और नियंत्रण की आवश्यक और पर्याप्त डिग्री मौजूद हो, तो इस सिद्धांत के अनुप्रयोग को जिम्मेदारी के रूप में भी उचित ठहराया जाता है।

ग. मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष में शामिल होने के लिए पक्षों का इरादा एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।अदालत गैर-सहमति वाले सिद्धांतों पर भी विचार कर सकती है जैसे कि कॉर्पोरेट पर्दा को भेदना, अहंकार को बदलना, या तंग समूह संरचना; और

घ. मध्यस्थता अधिनियम भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अपनाने को प्रतिबंधित या बाधित नहीं करता है।इसके विपरीत, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 मध्यस्थता समझौते की एक विस्तृत अवधारणा प्रदान करती है।इसके अलावा, विधायिका ने हस्ताक्षरकर्ता दलों के माध्यम से या उनके तहत काम करने वाले गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं की वास्तविकता को पहचानने और संहिताबद्ध करने के लिए "किसी भी व्यक्ति के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले" शब्दों को सम्मिलित करके मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 में संशोधन किया।

10. 2023 के आई. ए. सं. 56615 में मध्यस्थ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि:(i) गैर-हस्ताक्षरकर्ता और मध्यस्थता समझौते के पक्षों के बीच एक स्पष्ट कानूनी संबंध है; और (ii) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए सहमति देने वाला गैर-हस्ताक्षरकर्ता;

बी। गैर-हस्ताक्षरकर्ता के मध्यस्थता समझौते से बंधे होने के इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी उस पक्ष पर है जो गैर-हस्ताक्षरकर्ता को शामिल करना चाहता है;

ग. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के तहत आवश्यकता को देखते हुए, एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और मध्यस्थता के लिए मौखिक समझौता नहीं हो सकता है। इसके बावजूद, मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता का इरादा आचरण से एकत्र किया जा सकता है;घ. मध्यस्थता निजी कानून के दायरे में है, और पक्षकारों की पसंद और इरादे का मामला है।इसलिए, आर्थिक सुविधा, न्याय या समानता जैसे कारक गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने का आधार नहीं हो सकते हैं; और

ई. डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित संचयी कारकों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, और किसी दिए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स में कंपनियों के समूह के सिद्धांत की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए समग्र रूप से लागू किया जाना चाहिए।

11. 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 8607 में प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:ए। कंपनियों के समूह का सिद्धांत और एकल आर्थिक इकाई सिद्धांत विशुद्ध रूप से आर्थिक अवधारणाएं हैं जिनका अनुबंध कानून या कंपनी कानून में कोई आधार नहीं है।इसलिए, उन्हें गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के इरादे को निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है;

बी। मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने का किसी पक्ष का निर्णय इसके द्वारा बाध्य नहीं होने के इरादे को प्रदर्शित करने का आधार बन सकता है;ग. कई समझौतों का मात्र तथ्य या यह कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता अनुबंध की बातचीत में शामिल था, इसे मध्यस्थता समझौते से बांधने का आधार नहीं बना सकता है।

घ. "माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश जिसका उल्लेख मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 45 के तहत किया गया है, कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है।एक अनुबंध के लिए पक्षों के इरादे का निर्धारण केवल अनुबंध में प्रवेश करने के समय आयोजित इरादे से संबंधित होना चाहिए, जिसे अनुबंध के पाठ से वस्तुनिष्ठ रूप से एकत्र किया जा सकता है।हालांकि, क्लोरो कंट्रोल्स (सुप्रा) जो पक्षों के आपसी इरादे को निर्धारित करने के लिए परिणामी या बाद के समझौतों पर विचार करता है, गलत है।

12. 2020 की मध्यस्थता याचिका संख्या 38 में प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रितिन राय ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:ए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में मध्यस्थता

समझौते को लिखित रूप में होने की आवश्यकता है।इसलिए, गैर-हस्ताक्षरकर्ता की निहित सहमति के आधार पर एक मध्यस्थता समझौता नहीं बनाया जा सकता है।

बी। जटिल बहु-पक्षीय अनुबंध पार्टियों द्वारा अपने दिमाग को पूरी तरह से लागू करने के बाद की गई विस्तृत बातचीत के परिणाम हैं।समझौते की स्पष्ट शर्तों के विपरीत पक्षों पर इरादे का आरोप लगाने से बातचीत, लिखित दस्तावेज़ में पार्टियों द्वारा अपनी समझ को याद रखने के उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा।

ग. एक मध्यस्थता समझौता जो निष्पादन पक्षों को निर्धारित करता है और उनके बीच सहमत मध्यस्थता प्रक्रिया को तीसरे पक्ष तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है।

घ. कंपनियों के समूह के सिद्धांत का पता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 45 के तहत दिए गए वाक्यांश "दावे के माध्यम से या उसके तहत" से नहीं लगाया जा सकता है; और

ई. क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) गलती से इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के आचरण से प्राप्त एक निहित सहमति मध्यस्थता के लिए एक स्पष्ट इरादे की आवश्यकता को संतुष्ट करती है।इसके अलावा, क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) ने गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया कि अदालतों को असाधारण मामलों में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 45 के तहत गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का विवेकाधिकार है।इस तरह के विवेकाधिकार की शुरुआत भारत में मध्यस्थता व्यवहार में अनिश्चितता लाती है।

13. भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। चूँकि भारत UNCITRAL मॉडल कानून का पालन करता है, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय 'वाणिज्यिक तत्व' और 'व्यावसायिक विवेक' की अवधारणाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

बी। कंपनियों के समूह का सिद्धांत मध्यस्थता अधिनियम की समग्र योजना में अंतर्निहित है। धारा 7 में व्यापक वाक्यांश का उपयोग किया गया है "संबंध चाहे संविदात्मक हो या अन्यथा" यह बताने के लिए कि एक मध्यस्थता समझौता एक पारंपरिक समझौते तक ही सीमित नहीं है;

ग. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले शब्दों को सम्मिलित करना केवल व्यक्तियों की एक अन्य श्रेणी को इस बात पर जोर देने के लिए अधिकार प्रदान करने के विधायी इरादे को आगे बढ़ाने के लिए है कि न्यायिक प्राधिकरण को अपने समक्ष विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए; और

घ. यदि धारा 8 और 11 के तहत रेफरल अदालत प्रथम दृष्टया कंपनियों के समूह के सिद्धांत के आधार पर मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता के मुद्दे का निर्धारण नहीं कर सकती है, तो वह इस मुद्दे को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए भेज सकती है।

14. 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 8607 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय घोष ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:ए। धारा 2 (1) (एच) उन स्थितियों के लिए "हस्ताक्षरकर्ता" शब्द का उपयोग करता है जहां एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता उत्तराधिकार, कानून के संचालन, असाइनमेंट या मृत्यु द्वारा एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के जूते में प्रवेश करता है; और

बी। कंपनियों के समूह का सिद्धांत एक ऐसी संस्था पर दायित्व निर्धारित करके कॉर्पोरेट कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है जो मध्यस्थता समझौते का पक्ष नहीं है।केवल बातचीत या अनुबंध के प्रदर्शन में भागीदारी व्यक्त सहमति के अभाव में मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य नहीं कर सकती है।

15. 2023 के आई. ए. संख्या 58168 में हस्तक्षेप करने वालों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पल्लव मोंगिया ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) पक्षों की अवज्ञा को "हस्ताक्षरकर्ताओं" तक सीमित नहीं करती है।बल्कि, परिभाषा का अनुमान धारा 7 से लगाया जाना चाहिए।धारा 7 (4) गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए पक्षों की अवज्ञा का विस्तार करती है।

16. 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 8607 में प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने मुख्य मामले से 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 8607 को डी-टैगिंग करने के लिए तर्क दिया, जो कि 2020 की मध्यस्थता याचिका संख्या 38 है, क्योंकि पूर्व तीसरे पक्ष के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्देश जारी करने की अदालतों की शक्ति से संबंधित है।इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अदालतें मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वालों के खिलाफ अंतरिम निर्देश जारी करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत की सहायता ले सकती हैं।

647

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 648

17. गलियारे के दोनों ओर के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों से संकेत मिलता है कि इस संविधान पीठ को मुख्य रूप से भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कंपनियों के समूह के सिद्धांत की वैधता निर्धारित करने के लिए कहा गया है।हालाँकि, अन्य व्यापक सहायक मुद्दे हैं जो विद्वान वकील द्वारा उठाए गए हैं।इनमें शामिल हैं:(i) क्या मध्यस्थता अधिनियम किसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते के पक्षकार के रूप में अनुमति देता है; और, (ii) क्या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 पक्षकारों के आचरण के आधार पर मध्यस्थता करने के इरादे के निर्धारण की अनुमति देती है।यह पीठ नियत समय में संदर्भ आदेश से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के साथ-साथ उपर्युक्त सहायक मुद्दों का समाधान करेगी।

ग. कानूनी पृष्ठभूमि i.भारत

18. मध्यस्थता अधिनियम के अधिनियमन से पहले, मध्यस्थता पर कानून 1940 के मध्यस्थता अधिनियम, 1937 के मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम और 1961 के विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम में काफी हद तक निहित था।1978 में, भारत के विधि आयोग ने 1940 के अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून 10 पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर आदर्श कानून को अपनाया। 11 संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सभी सदस्य देशों को मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कानून को एक समान बनाने की दृष्टि से अपने घरेलू कानून में UNCITRAL मॉडल कानून को अपनाने की सिफारिश की।12 मध्यस्थता अधिनियम को मध्यस्थता से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।इसने UNCITRAL मॉडल लॉ, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित कानून लाया।

19. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) एक "पक्ष" का अर्थ "मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष" बताती है।" एक "मध्यस्थता समझौता" अमान्य है।

9 “1940 ऐक्ट "

10 “अनौपचारिक "

11 “UNCITRAL मॉडल कानून "

12 संयुक्त राष्ट्र महासभा, चालीसवां सत्र, 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर मॉडल कानून' 40/72 (1985)

धारा 2 (1) (बी) के तहत इसका अर्थ "धारा 7 में निर्दिष्ट एक समझौता" है।" धारा 7 एक वैध और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौते के आवश्यक तत्वों को निर्धारित करती है।यह एक मध्यस्थता समझौते को पक्षों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौते के रूप में प्रस्तुत करता है जो सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं।प्रावधान यह भी अनिवार्य करता है कि एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह निम्नलिखित में निहित है:(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार, या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार शामिल है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

धारा 7 (5) में आगे कहा गया है कि मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि दो शर्तों को पूरा किया जाता है।ये शर्तें पहली हैं, कि अनुबंध लिखित में है; और दूसरा, कि संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।

20. एक मध्यस्थता समझौता, अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, 13 एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को अपने विवादों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षों की सहमति पर आधारित है।आम तौर पर, मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष उन व्यक्तियों या संस्थाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ता हैं।हालांकि, पिछले दो दशकों में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के जॉइंडर पर कानून काफी विकसित हुआ है।विकास को मोटे तौर पर दो चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता हैःक्लोरो नियंत्रण से पहले (ऊपर) और क्लोरो के बाद

नियंत्रण (ऊपर)।

21. क्लोरो नियंत्रण (ऊपर) युग से पहले, इस न्यायालय ने इसे केवल मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं तक सीमित करके "पक्षों" का अर्थ लगाया।सुकन्या होल्डिंग्स (उपरोक्त) में आवेदक ने धारा के तहत एक आवेदन का नेतृत्व किया

13 भावेन कंस्ट्रक्शन बनाम कार्यकारी अभियंता, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, (2022) 1 एस. सी. सी. 75 649

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 650

8 उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम और समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों के खिलाफ मध्यस्थता समझौते को लागू करने की मांग की।उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं थे।अपील में, इस न्यायालय ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि क्या किया जाना आवश्यक है जहां मुकदमे के कुछ पक्ष मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं।

सुमितोमो कॉर्पोरेशन बनाम सी. डी. सी. फाइनेंशियल सर्विसेज (मॉरीशस) लिमिटेड, **14**

इस न्यायालय ने एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से निपटने के दौरान यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता समझौते के लिए एक "पक्ष" का अर्थ न्यायिक कार्यवाही के लिए एक पक्ष है। क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) में इसे स्पष्ट रूप से गलत माना गया था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "पक्ष" का अर्थ धारा 2 (1) (एच) को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता समझौते के पक्षकार के रूप में लिया जाना चाहिए।

22. धारा 2 (1) (एच) के तहत अभिव्यक्ति "पक्ष" की व्याख्या इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के विचार के लिए आई।उस मामले में, प्रथम और द्वितीय उत्तरदाताओं द्वारा बिक्री

का समझौता किया गया था।समझौते में दूसरे प्रतिवादी को 'खरीदार' और गैर-हस्ताक्षरकर्ता इंडोविंड के प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया गया था।विवाद उत्पन्न होने के बाद, प्रथम प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी और इंडोविंड के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया।इंडोविंड ने इस आधार पर अभियोग का विरोध किया कि वह अंतर्निहित बिक्री समझौते का एक पक्ष नहीं था और इसलिए, मध्यस्थता खंड द्वारा बाध्य होने के लिए सहमति नहीं दी थी।इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या बिक्री समझौते में निहित मध्यस्थता समझौता इंडोविंड पर बाध्यकारी था।इस न्यायालय ने मध्यस्थता समझौते में इंडोविंड को इस आधार पर शामिल करने से इनकार कर दिया कि (i) इंडोविंड बिक्री समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं था; (ii) इंडोविंड और प्रवर्तक कंपनी एक अलग और विशिष्ट कानूनी अस्तित्व वाली दो स्वतंत्र कंपनियां थीं; और (iii) यह तथ्य कि इंडोविंड ने बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, यह इंगित करता है कि यह सभी पक्षों का आपसी इरादा था कि वे इसे मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष न बनाएं।

23. प्री क्लोरो कंट्रोल्स (सुप्रा) स्थिति की विशेषता तीन अंतर्निहित उपदेशों से थीः(i) मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता के कहने पर मध्यस्थता का आह्वान केवल विवादों के संबंध में किया जा सकता है।

14 (2008) 4 एस. सी. सी 91

एक अन्य हस्ताक्षरकर्ता पक्ष; 15 (ii) न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों की सख्त व्याख्या को अपनाएगा, विशेष रूप से अपरिवर्तित धारा 8 जो केवल मध्यस्थता समझौते के लिए "पक्षों" के संदर्भ की अनुमति देती है; और (iii) पक्षों की औपचारिक सहमति पर जोर दिया गया था, जिससे गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं की निहित सहमति के लिए किसी भी गुंजाइश को एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने की गुंजाइश से बाहर रखा गया था।कानून की इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया जब क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत के आधार पर मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को अनुमति दी।

अ. क्लोरो नियंत्रण

24. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस न्यायालय को बहु-पक्षीय समझौतों के मामले में एक मध्यस्थ संदर्भ निर्धारित करने के लिए कहा गया था, जहां सहायक समझौतों का प्रदर्शन काफी हद तक प्रमुख समझौते के प्रभावी निष्पादन पर निर्भर था।उस मामले में, एक विदेशी इकाई और एक भारतीय इकाई ने क्लोरीनीकरण उपकरण के विपणन और वितरण के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल किया।संयुक्त उद्यम के संबंध में, भारतीय और विदेशी दोनों संस्थाओं की संबंधित कंपनियां भी शामिल थीं।नतीजतन, पक्षों ने कई सहायक समझौते किए जैसे कि शेयरधारकों का समझौता जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल था।सभी संविदाकारी पक्षों ने शेयरधारकों के

समझौते सहित सभी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।जब पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, तो विदेशी संस्थाओं ने संयुक्त उद्यम को समाप्त करने की मांग की।भारतीय इकाई ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन का नेतृत्व किया जिसमें विदेशी संस्थाओं को समझौतों के तहत अपने दायित्वों को अस्वीकार करने से रोकने के लिए एक घोषणा की मांग की गई थी।जवाब में, विदेशी संस्थाओं ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए आवेदन किया कि समझौते लेनदेन की समग्र प्रकृति के कारण गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी थे।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने भारतीय इकाई के आवेदन को मंजूरी दे दी, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया था।इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 के दायरे और दायरे से संबंधित था। इस न्यायालय ने इस मुद्दे को निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया:

" 1.3.क्या ऐसे मामले में जहां विभिन्न पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और जहां कुछ में मध्यस्थता खंड होता है और

15 एस. एन. प्रसाद बनाम मोनेट फाइनेंस लिमिटेड (2011) 1 एस. सी. सी. 320 651

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 652

अन्य पक्ष न्यायालय (एक वाद में) और मध्यस्थता समझौते के समक्ष कार्यवाही में समान रूप से समान नहीं हैं, संपूर्ण या आंशिक रूप से विवादों का संदर्भ मध्यस्थता न्यायाधिकरण को दिया जा सकता है, विशेष रूप से, जहां किसी कार्रवाई के पक्षकार मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष के तहत या उसके माध्यम से दावा कर रहे हैं।

25. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 अपने अपरिवर्तित रूप में इस प्रकार है:

"45. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति।— भाग I या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक न्यायिक प्राधिकरण, जब किसी ऐसे मामले में कार्रवाई करता है जिसके संबंध में पक्षों ने धारा 44 में निर्दिष्ट एक समझौता किया है, तो दोनों में से किसी एक के अनुरोध पर

पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, संदर्भित करता है

मध्यस्थता के पक्षकारों का कहना है कि उक्त समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है।"

(जोर दिया गया) धारा 45 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल करने के लिए मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ता "पक्षों" से परे दायरे को बढ़ाने के विधायी इरादे को दर्शाती है।हालांकि, अदालत ने कहा कि ऐसे गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने

की आवश्यकता होती है।" इस प्रकार, इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले और किसी पक्ष के माध्यम से दावा करने वाले तीसरे पक्ष या गैर-हस्ताक्षर करने वाले के बीच मध्यस्थता संभव है।26. इस न्यायालय के समक्ष अगला मुद्दा यह निर्धारित करना था कि क्या हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता के बीच पूर्व के माध्यम से या उसके तहत दावा करने के लिए कोई कानूनी संबंध था।अदालत ने कहा कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में विकसित किया गया है ताकि हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के रूप में एक ही कॉर्पोरेट समूह के भीतर एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबंध या सहयोगी संस्था को एक मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य किया जा सके, बशर्ते कि सभी पक्षों का आपसी इरादा हो।इस अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि "पक्षों का इरादा" कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए अंतर्निहित सिद्धांत है।यह देखा गयाः

"72. यह इस सिद्धांत को विकसित करता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है बशर्ते ये लेनदेन समूह के साथ हों

कंपनियों और दोनों पक्षों, हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बांधने का एक स्पष्ट इरादा था।दूसरे शब्दों में,

"पक्षकारों का इरादा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे मध्यस्थता के दायरे में हस्ताक्षरकर्ता के साथ**-**साथ गैर**-**हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को शामिल करने से पहले स्थापित किया जाना चाहिए।**"**

(जोर दिया गया) 27।अदालत ने माना कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को चार निर्धारक कारकों के आधार पर "असाधारण मामलों" में "उनकी पूर्व सहमति के बिना" मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता हैः

(i) उस पक्ष के साथ सीधा संबंध जो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है;

((ii) विषय-वस्तु की प्रत्यक्ष समानता और पक्षों के बीच समझौता एक समग्र लेन-देन है।

(iii) लेन-देन एक समग्र प्रकृति का होने के कारण जहां सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरक या सहायक समझौतों की सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना मातृ समझौते का प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है और सामूहिक रूप से विवाद पर असर पड़ता है; और

((iv) ऐसे पक्षों का समग्र संदर्भ न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।28. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि बहु-पक्षीय समझौते से जुड़े समग्र लेनदेन के मामले विचित्र चुनौतियों को जन्म देते हैं जहां गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को उनके कानूनी संबंधों और संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन में भागीदारी के कारण विवाद में फंसाया जा सकता है।ऐसी स्थितियों का

समाधान करने के लिए, यह माना गया कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को तथ्यों और परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करने के लिए लागू किया जा सकता है ताकि मध्यस्थता समझौते के लिए "दोनों, हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बांधने के लिए पक्षों का एक स्पष्ट इरादा" निर्धारित किया जा सके।29. क्लोरो कंट्रोल्स (सुप्रा) एक ऐसी स्थिति से निपट रहा था जहां संयुक्त उद्यम समझौते की सफलता सभी सहायक समझौतों की पूर्ति पर निर्भर थी।इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि सभी सहायक समझौते मूल समझौते से संबंधित थे और सहायक समझौते आंतरिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, इस हद तक कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था।अदालत के विचार में यह 653 के इरादे का संकेत देता है।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 654

पक्षकार मूल समझौते और सहायक समझौतों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजेंगे।

30. इसके अलावा, इस न्यायालय ने "कानूनी संबंध" वाक्यांश को समझाया जिसका अर्थ है हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का उस व्यक्ति के साथ संबंध जो उनके तहत या उनके माध्यम से दावा करता है। इसने देखा कि सभी समझौतों पर "कुछ पक्षों या उनकी होल्डिंग कंपनियों या उन कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें हस्ताक्षरकर्ता कंपनी का विलय हुआ था।" हालाँकि इन कंपनियों ने सभी समझौतों के लिए कागज पर कलम नहीं लगाई, वे हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के हित या सहायकों के वंशज थे और इसलिए समझौते के पक्षों के माध्यम से या उनके तहत "दावा" अभिव्यक्ति के तहत शामिल किए जाएंगे।इस संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि एक ही निगमित समूह का हिस्सा होने के नाते, गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों के हित प्रमुख कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं थे।इसलिए, कंपनियों के समूह के सिद्धांत ने हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से या उसके तहत दावा करने के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के लिए आधार बनाया।क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) ने यह अनुपात निर्धारित किया कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति या संस्था को एक मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष बनाया जा सकता है, एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने के रूप में, यदि परिस्थितियां लेन-देन की समग्र प्रकृति, विषय-वस्तु की प्रत्यक्ष समानता और हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता के प्रत्यक्ष संबंध के आधार पर पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करती हैं।

बी। क्लोरो नियंत्रण के बाद कानून का विकास

31. क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) के बाद, भारत के विधि आयोग ने 2014 में मध्यस्थता अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। आयोग ने पाया कि धारा 45 में प्रयुक्त और समझा गया वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" धारा 8 के संबंधित प्रावधान में अनुपस्थित है।इस विसंगति को दूर करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि धारा 2 (1) (एच) के तहत "पक्ष" की अवज्ञा को "ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला व्यक्ति" अभिव्यक्ति को भी शामिल करने के लिए संशोधित किया जाए।" 16 2016 में, विधायिका ने

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 के अनुरूप लाने के लिए धारा 8 में संशोधन किया। असंशोधित धारा 8 (1) में प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन कर सकता है।संशोधित धारा 8 (1) में प्रावधान किया गया है कि "मध्यस्थता के लिए एक पक्षकार"

16 भारतीय विधि आयोग, 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन', रिपोर्ट संख्या 246 (अगस्त 2014)

समझौता या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ की मांग कर सकता है।हालाँकि, विधायिका ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) या धारा 7 की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया। क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) और धारा 8 में संशोधन के बाद से, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तियों या संस्थाओं को मध्यस्थता समझौतों में शामिल करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत को संदर्भित किया है।

32. चेरन प्रॉपर्टीज (उपरोक्त) में, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मध्यस्थता पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 35 के तहत एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ लागू किया जा सकता है, जो मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक का नामित था और हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच अंतर्निहित अनुबंध का प्रत्यक्ष लाभार्थी था।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 35 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार "उनके अधीन दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों के लिए क्रमशः अनिवार्य और बाध्यकारी होगा।" इस न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" प्रत्येक व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी क्षमता या स्थिति कार्यवाही के एक पक्ष के रूप में प्राप्त होती है और समान है।इसने अभिनिर्धारित किया कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता पक्षों में से एक का नामित होने के नाते, मध्यस्थता पुरस्कार से बाध्य था क्योंकि वह हस्ताक्षरकर्ता के तहत दावा कर रहा था।

33. चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में इस न्यायालय ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका वास्तविक उद्देश्य उन पक्षों के सामान्य इरादे को लागू करना है जहां परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों का इरादा बाध्य होना था।हममें से एक (जे. डी. वाई. चंद्रचूड़) ने भारतीय संदर्भ में कंपनियों के समूह के सिद्धांत के विकास को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः

"23. जैसे-जैसे कानून विकसित हुआ है, यह माना गया है कि आधुनिक व्यावसायिक लेनदेन अक्सर कई परतों और समझौतों के माध्यम से किए जाते हैं।कंपनियों के एक समूह के भीतर लेनदेन हो सकते हैं।जिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रवेश किया है, वे एक ही समूह के भीतर हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों संस्थाओं को बांधने के इरादे को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।एक मध्यस्थता समझौते द्वारा बाध्य एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को धारण करने में, अदालत लेनदेन को उस व्यावसायिक भावना के अनुरूप एक अर्थ प्रदान करके मामले का रुख करती है जिसका

उन्हें श्रेय दिया जाना था।इसलिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता का संबंध, विषय-वस्तु की समानता और 655 जैसे कारक।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 656

लेन-देन की समग्र प्रकृति का संतुलन में वजन होता है।समूह ने

कंपनियों के सिद्धांत का उद्देश्य अनिवार्य रूप से पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से आयोजित इरादे की पूर्ति को सुविधाजनक बनाना है, जहां परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बांधना था।प्रभावी उद्देश्य व्यावसायिक व्यवस्था के वास्तविक सार को स्पष्ट करना और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की एक स्तरित संरचना से बाहर निकालना है, किसी ऐसे व्यक्ति को बांधने का इरादा जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन जिसने हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व ग्रहण किया है।"

(जोर दिया गया) 34।चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में निर्णय में कहा गया है कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को मध्यस्थता समझौते के निर्माण, अनुबंध में प्रवेश करने के समय मौजूद परिस्थितियों और अंतर्निहित अनुबंध के प्रदर्शन पर एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को बांधने के लिए लागू किया जाता है।फिर भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेरन प्रॉपर्टीज (उपरोक्त) ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष बनाने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू नहीं किया।बल्कि, इस न्यायालय ने धारा 35 के तहत एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पर इस आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार को बाध्यकारी बना दिया कि वह एक पक्ष के तहत दावा कर रहा था जो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता था।

35. अमित लालचंद शाह बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज, 17 में दो-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ एक एकल वाणिज्यिक परियोजना के लिए निष्पादित चार परस्पर जुड़े समझौतों से उत्पन्न एक मध्यस्थता विवाद से निपट रही थी।मुद्दा यह था कि क्या चार समझौते सभी पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए आपस में जुड़े हुए थे।उस मामले में, सभी पक्षों ने मध्यस्थता खंड वाले मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।इस न्यायालय ने क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए भरोसा किया कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता, जो एक परस्पर जुड़े समझौते का एक पक्ष है, मुख्य समझौते में मध्यस्थता खंड से बाध्य होगा।इसने पाया कि लेन-देन की समग्र प्रकृति को देखते हुए, विभिन्न समझौतों के पक्षों के बीच विवादों को उन सभी को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करके प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है।

36. समय के साथ, इस न्यायालय ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत के आह्वान के लिए कुछ अतिरिक्त कारकों की पहचान की है।रेकिट बेंकिजर में

17 (2018) 15 एस. सी. सी. 678

(भारत**)** प्राइवेट लिमिटेड बनाम रेयंडर्स लेबल प्रिंटिंग इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड, 18 इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन पर विचार कर रही थी।इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया कहा कि पक्षकार कंपनियों के एक ही समूह से संबंधित थे।इसके बाद, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या पक्षकारों का अंतर्निहित अनुबंध की बातचीत में उनकी भागीदारी के आधार पर हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों को बांधने का स्पष्ट इरादा था।अदालत ने माना कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष, भले ही कॉर्पोरेट समूह का एक घटक हिस्सा हो, का "समझौते से पहले की बातचीत की प्रक्रिया या उसके निष्पादन के साथ कोई कारण संबंध नहीं था, जो भी हो।" इस प्रकार, बातचीत में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष की भागीदारी और अंतर्निहित अनुबंध के प्रदर्शन को एक मध्यस्थता समझौते द्वारा बाध्य होने के लिए पक्षों के इरादे का प्रमुख निर्धारक माना गया था।

37. केनरा बैंक (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को "एकल आर्थिक इकाई" के सिद्धांत के आधार पर लागू किया जा सकता है।उस मामले में तथ्य यह था कि केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 19 ने एम. टी. एन. एल. द्वारा जारी किए गए बांडों की सदस्यता ली थी। बाद में कैनफिना ने बांड को केनरा बैंक को हस्तांतरित कर दिया।आखिरकार, एम. टी. एन. एल. ने बांडों को रद्द कर दिया जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया।केनरा बैंक ने एम. टी. एन. एल. द्वारा बांडों को रद्द करने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका का नेतृत्व किया। उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा, लेकिन केनरा बैंक ने कैनफिना के अभियोग को चुनौती दी। इस न्यायालय ने केनरा बैंक की आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कैनफिना मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक आवश्यक और उचित पक्ष था, जो बांड का मूल खरीदार था।कंपनियों के समूह के सिद्धांत की रूपरेखा पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि इस सिद्धांत को उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है जहां मजबूत संगठनात्मक और वित्तीय संबंधों के साथ एक तंग समूह संरचना है, ताकि एक एकल आर्थिक इकाई या एक एकल आर्थिक वास्तविकता का गठन किया जा सके।"

38. कंपनियों के समूह के सिद्धांत से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में अंतिम निर्णय डिस्कवरी एंटरप्राइजेज में इस न्यायालय का तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है।

18 (2019) 7 एस. सी. सी. 62 19 "कैनफिना"

(ऊपर)।उस मामले में, ओ. एन. जी. सी. ने एक शिपिंग पोत के संचालन के लिए डिस्कवरी एंटरप्राइजेज के साथ एक अनुबंध किया।पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, ओ. एन. जी. सी. ने डिस्कवरी एंटरप्राइजेज और डिस्कवरी एंटरप्राइजेज की सहयोगी कंपनी जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ अनुबंध में मध्यस्थता खंड लागू किया।मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ दावे पर आगे बढ़ने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि उसने मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत ओ. एन. जी. सी. के नेतृत्व में एक अपील में उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा।उच्च न्यायालय के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।इस न्यायालय ने क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) और अनुमोदन के साथ बाद के निर्णयों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को एक समूह के भीतर एक कंपनी को बांधने के लिए लागू किया जा सकता है जो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्लोरो नियंत्रण (उपरोक्त) में निर्धारित संचयी कारकों के अलावा, अनुबंध का प्रदर्शन भी एक आवश्यक कारक था जिस पर न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।अंततः, इस न्यायालय ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह ओ. एन. जी. सी. द्वारा उठाई गई याचिका को संबोधित करने में विफल रहा और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया।

ii.फ्रांस**-**डाउ केमिकल्स मामला

39. मध्यस्थता कानून में कंपनियों के समूह के सिद्धांत का अनुप्रयोग मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न हुआ है।सिद्धांत की रूपरेखा का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी उत्पत्ति और विकास को समझना आवश्यक है।इस तरह का विश्लेषण विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि कंपनियों के समूह के सिद्धांत के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई भी आधिकारिक निर्धारण मध्यस्थता समझौतों में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल होने के परेशान करने वाले मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

40. इस सिद्धांत की उत्पत्ति का श्रेय मुख्य रूप से फ्रांस में दिए गए कई मध्यस्थता पुरस्कारों को दिया जाता है।उनमें से सबसे प्रमुख मामला संख्या 4131 में एक आई. सी. सी. न्यायाधिकरण द्वारा चार दशक से अधिक समय पहले दिया गया एक अंतरिम पुरस्कार है, जिसे डॉव केमिकल्स मामले के रूप में जाना जाता है।उस मामले में, डाउ केमिकल (वेनेजुएला) ने प्रवेश किया।

20 डाउ केमिकल बनाम इसोवर सेंट गोबेन, अंतरिम पुरस्कार, आईसीसी मामला संख्या 4131,23 सितंबर 1982

एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक अनुबंध में, जिसने बाद में फ्रांस में थर्मल अलगाव उत्पादों के वितरण के लिए इसोवर सेंट गोबेन को अधिकार सौंपे।डाउ केमिकल (वेनेजुएला) ने बाद में डाउ केमिकल एजी को अनुबंध सौंपा, जो डाउ केमिकल कंपनी-होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी थी। इसके बाद, डाउ केमिकल एजी की सहायक कंपनी डाउ केमिकल यूरोप ने तीन कंपनियों के साथ इसी तरह का अनुबंध किया, जिसने बाद में इसोवर सेंट गोबेन को अनुबंध सौंपा।दोनों अनुबंधों में यह प्रावधान था कि वितरकों को उत्पादों की डिलीवरी डॉव केमिकल फ्रांस या डॉव केमिकल कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी द्वारा की जाएगी।फ्रांसीसी अदालतों के समक्ष डाउ केमिकल समूह की कंपनियों के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए थे।जवाब में, डाउ केमिकल समूह की चार कंपनियों (अनुबंध के दो औपचारिक पक्ष-डाउ केमिकल एजी और डाउ केमिकल यूरोप, और दो गैर-हस्ताक्षरकर्ता-डाउ केमिकल कंपनी और डाउ केमिकल फ्रांस) ने आईसीसी न्यायाधिकरण के समक्ष इसोवर सेंट गोबेन के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की।

41. आई. सी. सी. न्यायाधिकरण के समक्ष प्राथमिक मुद्दा गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों पर अपना अधिकार क्षेत्र निर्धारित करना था।न्यायाधिकरण ने यह निर्धारित करने की मांग की कि क्या मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए पक्षों का एक सामान्य इरादा मौजूद है।न्यायाधिकरण ने बातचीत, प्रदर्शन और अनुबंधों की समाप्ति को रेखांकित करने वाली तथ्यात्मक परिस्थितियों का विश्लेषण करके पक्षों के सामान्य इरादे को स्थापित किया।न्यायाधिकरण ने माना कि डाउ केमिकल फ्रांस दो अनुबंधों का "एक पक्ष" था, और इसके परिणामस्वरूप उनमें निहित मध्यस्थता समझौतों के लिए, क्योंकि इसने बातचीत, प्रदर्शन और अनुबंध की समाप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाई।डॉव केमिकल कंपनी के लिए, न्यायाधिकरण ने माना कि होल्डिंग कंपनी के पास ट्रेडमार्क का स्वामित्व था जिसके तहत उत्पादों का विपणन फ्रांस में किया गया था और इसकी सहायक कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण था जो बातचीत, प्रदर्शन और दो अनुबंधों की समाप्ति में शामिल थे।न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर भी भरोसा किया कि इसोवर सेंट गोबेन ने पेरिस के अपील न्यायालय के समक्ष फ्रांस में अदालती कार्यवाही में होल्डिंग कंपनी के जॉइंडर के लिए आवेदन किया था।

659

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 660

42. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता भी मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष थे, न्यायाधिकरण ने कंपनियों के एक ही समूह से संबंधित हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता की तथ्यात्मक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा।शुरुआत में, न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनियों का एक समूह एक ही आर्थिक वास्तविकता का गठन करता है।हालाँकि, न्यायाधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता उसी समूह की किसी अन्य इकाई द्वारा किए गए मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है यदि गैर-हस्ताक्षरकर्ता बातचीत, प्रदर्शन और अनुबंधों की समाप्ति में उनकी भागीदारी के आधार पर अनुबंधों का एक वास्तविक पक्ष प्रतीत होता है। प्रासंगिक अवलोकन नीचे निकाला गया है:

"विशेष रूप से, इस बात पर विचार करते हुए कि समूह की कुछ कंपनियों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किए गए मध्यस्थता खंड को अन्य कंपनियों को बाध्य करना चाहिए, जो अपने निष्कर्ष, प्रदर्शन या उक्त खंड वाले अनुबंधों की समाप्ति में अपनी भूमिका के आधार पर और कार्यवाही में सभी पक्षों के आपसी इरादे के अनुसार, इन अनुबंधों के लिए वास्तविक पक्षकार प्रतीत होते हैं या मुख्य रूप से उनके द्वारा संबंधित थे और वे विवाद जिनसे वे उत्पन्न हो सकते हैं।"43. डाउ केमिकल (उपरोक्त) में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए मध्यस्थता समझौते का विस्तार करने के अपने निर्णय को केवल इस तथ्य पर आधारित नहीं किया कि हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्ष एक ही समूह के सदस्य थे।न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता समझौते के सच्चे पक्षों को बातचीत, प्रदर्शन और समझौते की समाप्ति में उनकी भागीदारी के आधार पर निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया।डाउ केमिकल मामले को मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए निहित सहमति के लिए आवश्यक प्रासंगिकता को जोड़ने वाले अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने वाली सहमति की प्रतिबंधात्मक व्याख्या से संक्रमण में सहायक माना गया है।21

44. बाद के फैसलों की एक श्रृंखला में, पेरिस की अपील अदालत ने गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए एक मध्यस्थता समझौते के विस्तार को स्वीकार किया, बशर्ते कि सभी पक्षों का सामान्य इरादा हो। अपील न्यायालय के अनुसार, आम इरादे का पता अनुबंध के प्रदर्शन में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका से लगाया जा सकता है।

21 बर्नार्ड हनोटियाउ और लियोनार्डो ओहलरॉग, 'डाउ केमिकल अवार्ड की 40 वीं वर्षगांठ' 40 (2) एएसए बुलेटिन 300-308।

मध्यस्थता समझौता, जो इस धारणा को जन्म देता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते का ज्ञान था।22

45. फ्रांसीसी कानून को 2001 के मामले संख्या 11405 में एक अप्रकाशित आई. सी. सी. पुरस्कार में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

"[टी] यहाँ फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कानून में कोई सामान्य नियम नहीं है, जो यह प्रदान करेगा कि कंपनियों के एक ही समूह के गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष सदस्य एक मध्यस्थता खंड से बाध्य होंगे, चाहे वह हमेशा या निर्धारित परिस्थितियों में हो।प्रासंगिक बात यह है कि क्या सभी पक्षों का इरादा गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता खंड से बाध्य होना था।न केवल हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को, बल्कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता दलों को भी मध्यस्थता खंड द्वारा बाध्य होने का इरादा (या अन्य पक्षों को यथोचित रूप से विश्वास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था कि वे चाहते थे)।" 23

इसलिए फ्रांसीसी कानून में स्थिति के बारे में हमारी समझ यह है कि एक मध्यस्थता समझौते को गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों तक बढ़ाया जा सकता है यदि मध्यस्थता समझौते के सभी पक्षों का समझौते से बाध्य होने का एक सामान्य इरादा था।पक्षकारों के व्यक्तिपरक इरादे का अनुमान

मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन और समाप्ति के दौरान उनके उद्देश्यपूर्ण आचरण के आधार पर लगाया जाना है।

iii.स्विट्जरलैंड

46. स्विस निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिनियम 1987 की धारा 178 (1) में कहा गया है कि एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में या संचार के किसी अन्य माध्यम से किया जाना चाहिए जिससे इसे पाठ द्वारा प्रमाणित किया जा सके।" 2003 में, स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार स्विस अधिनियम की धारा 178 (1) के अनुसार एक वैध मध्यस्थता खंड होने के बाद, यह मुद्दा कि क्या यह गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं तक भी फैला हुआ है, अदालतों या मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा तय किया जा सकता है।सामान्य नियम के रूप में, स्विस अदालतों ने आमतौर पर दावे के समनुदेशन, ऋण की धारणा या अनुबंध के प्रत्यायोजन के मामलों में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए एक मध्यस्थता समझौते का विस्तार किया है।24

22 पेरिस अपील न्यायालय, 7 दिसंबर 1994, वी. 2000 (पूर्व में जगुआर फ्रांस) बनाम परियोजना एक्स. एस., रेव. अरब। (1996) 67.

23 यवेस डेरेंस, 'क्या कंपनी सिद्धांत का कोई समूह है?' आई. सी. सी. इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड बिजनेस लॉ के दस्तावेज़ में बर्नार्ड हनोटियाउ और एरिक श्वाट्र्ज (संस्करण), खंड 7,131-145।

24 ए, बी, सी बनाम डी और लीबिया राज्य, 4 ए 636/2018 661

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 662

47. 1996 में दिए गए एक निर्णय में, स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह तथ्य कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के रूप में कंपनियों के एक ही समूह से संबंधित था, मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए एक पर्याप्त वैज्ञानिक औचित्य नहीं था।25 हालाँकि, स्विस अदालतें गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता समझौते का विस्तार करने के खिलाफ नहीं हैं यदि मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष की सहमति की एक स्वतंत्र और औपचारिक रूप से वैध अभिव्यक्ति है।

48. स्विस कानून में, मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए पक्षों की सहमति आचरण द्वारा व्यक्त या निहित हो सकती है।2008 के एक निर्णय में, स्विस संघीय न्यायालय ने माना कि कुछ व्यवहार या आचरण एक मध्यस्थता समझौते की औपचारिक आवश्यकता के साथ अनुपालन का स्थान ले सकते हैं।26 निहित सहमति निर्धारित करने के लिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अदालतें या न्यायाधिकरण इस तथ्य को ध्यान में रख सकते हैं कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष अनुबंध की बातचीत और प्रदर्शन में शामिल था, और इस तरह मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने की अपनी इच्छा व्यक्त की।27 इस प्रकार, मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने की इच्छा के व्यक्तिपरक तत्व को बातचीत या अनुबंध के प्रदर्शन के रूप में एक वस्तुनिष्ठ तत्व के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए।

iv.इंग्लैंड

49. अंग्रेजी अदालतों ने आम तौर पर मध्यस्थता समझौतों के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बाध्य करने के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है।इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 की धारा 82 (2) "मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष" को "समझौते के लिए एक पक्ष के तहत या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति" को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है।" अंग्रेजी कानून में परिकल्पना की गई है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष भी एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे समझौते के लिए मूल पक्ष के तहत या उसके माध्यम से दावा कर रहे हों।अंग्रेजी अदालतों ने एक दृष्टिकोण अपनाया है जो गोपनीयता के सिद्धांत के सख्त पालन का समर्थन करता है।अंग्रेजी कानून के तहत, एक मध्यस्थता समझौते को पारंपरिक संविदात्मक सिद्धांतों और सिद्धांतों जैसे एजेंसी, नोवेशन, आदि के आधार पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों तक बढ़ाया जाता है।

25 सऊदी ब्यूटेक लिमिटेड एट अल फौज ट्रेडिंग बनाम सऊदी अरब साइपेम लिमिटेड, 25 अक्टूबर 1994 का अप्रकाशित आईसीसी अंतरिम पुरस्कार, 29 जनवरी 1996 को डीएफटी द्वारा प्रदान किया गया, एएसए बुलेटिन (1996) खंड 3 पी 496।

26 5 दिसंबर 2008 का निर्णय 4 ए 376/2008।

27 एक्स बनाम वाई इंजीनियरिंग एस. पी.ए. और वाई. एसपी.ए., 4 ए. 450/2013, एएसए बुल।, 160 (2015).

समनुदेशन, कानून का संचालन, और विलय और उत्तराधिकार।28 हालाँकि, अंग्रेजी कानून ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता समझौते का विस्तार करने के आधार के रूप में कॉर्पोरेट घूंघट, न्यायसंगत अवरोध और कंपनियों के समूह को भेदने जैसे अन्य सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

50. पीटरसन फ़ार्म्स आई. एन. सी. बनाम सी. एंड एम. फ़ार्मिंग लिमिटेड में, 29 एक दावा

पीटरसन फ़ार्म्स के खिलाफ प्रतिवादी सी एंड एम फ़ार्मिंग द्वारा कई सी एंड एम समूह संस्थाओं द्वारा किए गए नुकसान के लिए नुकसान के लिए लाया गया था, जिनमें से कुछ मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता थे।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को यह मानने के लिए लागू किया कि सी एंड एम फार्मिंग ने पूरे सी एंड एम समूह की संस्थाओं की ओर से अनुबंध किया था, और इसलिए पीटरसन के साथ संविदात्मक संबंध से उत्पन्न सी एंड एम समूह की संस्थाओं द्वारा किए गए सभी नुकसान का दावा करने का हकदार था।अपील में, वाणिज्यिक न्यायालय ने माना कि समझौते का चुना गया उचित कानून-अर्कांसस कानून-अंग्रेजी कानून के समान है जो कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग को बाहर करता है।इस प्रकार, अंग्रेजी कानून गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता समझौते का विस्तार करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के पक्ष में नहीं है।

51. अंग्रेजी उदाहरणों में "माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश के अर्थ पर भी चर्चा की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था।

क्लोरो नियंत्रण (ऊपर)।रूसेल-उक्काफ बनाम जी. डी. सियरले एंड कंपनी लिमिटेड 30 में,

चांसरी डिवीजन के न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मूल कंपनी और किसी तीसरे पक्ष के बीच मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष होने का दावा कर सकती है।न्यायालय को 1975 के मध्यस्थता अधिनियम की धारा 1 की व्याख्या करने के लिए कहा गया था, जो मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष को या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थता समझौता मौजूद होने पर कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अदालत में आवेदन करने की अनुमति देता है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सहायक कंपनी मध्यस्थता समझौते के लाभ का दावा कर सकती है क्योंकि मूल कंपनी और सहायक कंपनी "इतने निकट से संबंधित" थे कि यह कहा जा सकता है कि सहायक कंपनी "या के माध्यम से दावा कर रही थी"।

28 ऑडली विलियम शेपर्ड, 'अंग्रेजी मध्यस्थता कानून में तीसरे पक्ष के गैर-हस्ताक्षरकर्ता' स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, जूलियन ल्यू, और अन्य (संस्करण) द इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 2016) 183-198।

29 [2004] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 121 (कॉम)

30 [1978] 1 लॉयड के प्रतिनिधि 663

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 664

मूल कंपनी के तहत।सिटी ऑफ लंदन बनाम संचेती, 31 में अपील न्यायालय ने रूसेल-उक्काफ (उपरोक्त) को इस आधार पर खारिज कर दिया कि किसी संस्था को केवल इसलिए या उसके तहत दावा करने वाला नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनके बीच "कानूनी या वाणिज्यिक संबंध" है।

52. अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 5 में मध्यस्थता समझौते को लिखित रूप में होने की आवश्यकता है।इसके अलावा, धारा 5 (2) (ए) में प्रावधान है कि पक्षों के लिए मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है।ऐसी स्थितियों में, अंग्रेजी अदालतों के समक्ष जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वह यह है कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष मध्यस्थता समझौते से बाध्य है।अंग्रेजी कानून की स्थिति यह है कि "अनुबंधों को हल्के में निहित नहीं किया जाना चाहिए" और अदालत को "दोनों पक्षों को संविदात्मक संबंध बनाने का इरादा रखने के साथ निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए और यह कि समझौता उस प्रभाव के लिए था जिसके लिए तर्क दिया गया था।" 32 हालांकि, सीमित स्थितियों में, एक अनुबंध निहित है यदि पक्ष इस तरह से खुद को संचालित करते हैं जैसे कि उन्होंने औपचारिक रूप से एक अनुबंध में प्रवेश किया है।33

53. दल्ला रियल एस्टेट एंड टूरिज्म होल्डिंग कंपनी बनाम धार्मिक मामलों के मंत्रालय में, पाकिस्तान सरकार 34, सरकार

पाकिस्तान सरकार ने मक्का, सऊदी अरब में आवास सुविधाओं के निर्माण के लिए डल्ला रियल एस्टेट और टूरिज्म होल्डिंग कंपनी 35 के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।इसके बाद, डल्ला और अवामी हज ट्रस्ट के बीच एक समझौता किया गया, जिसे सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था।हालाँकि, ट्रस्ट का एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि अध्यादेश को संसद के समक्ष नहीं रखा गया था और आगे कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया था।डल्ला ने सरकार के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की।ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या सरकार और दल्ला की ओर से पूर्व को समझौते में एक पक्ष बनाने का एक सामान्य इरादा था।अदालत ने कहा कि "पक्षों के सामान्य इरादे का मतलब है कि उनका व्यक्तिपरक इरादा प्राप्त हुआ है

31 द मेयरलिटी एंड कॉमनलिटी एंड सिटिजन्स ऑफ द सिटी ऑफ लंदन बनाम अशोक संचेती, [2008] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1283

32 ब्लैकपूल और फिल्डे एयरो क्लब लिमिटेड बनामब्लैकपूल बरो काउंसिल, [1990] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1195

33 चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ह्यूग बील (संस्करण), (32 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, 2015) पैरा 2-169।

34 [2010] यूकेएससी 46

35 “डल्लाह "

वस्तुनिष्ठ साक्ष्य से।” यह माना गया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सरकार के व्यवहार से पता चलता है कि वह हमेशा खुद को समझौते का एक सच्चा पक्ष मानता है।

v. सिंगापुर

54. मनुचर स्टील हांगकांग लिमिटेड बनाम स्टार पैसिफी सी लाइन पीटीई

लिमिटेड, 36 सिंगापुर उच्च न्यायालय ने गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत थाःपहला, मध्यस्थता के लिए एक समझौते के सहमति के आधार के तर्क के लिए अभिशाप; और दूसरा, एक व्यापक समूह के भीतर कंपनियों के आदेश का मतलब यह नहीं था कि कोई अलग कानूनी इकाई के साथ वितरित कर सकता है।सिंगापुर उच्च न्यायालय ने पीटरसन फ़ार्म्स आई. एन. सी. (ऊपर) में ली गई कानून की स्थिति पर भरोसा करते हुए कहा कि मध्यस्थता समझौते के लिए "अजनबियों" पर लागू करने योग्य दायित्व नहीं लगाए जा सकते हैं।

vi.संयुक्त राज्य अमेरिका

55. संघीय मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के सहयोगी के पहलू पर चुप है।फिर भी, अमेरिकी अदालतों ने अक्सर अनुबंध कानून के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग किया है जैसे कि संदर्भ द्वारा निगमन, धारणा, एजेंसी, घूंघट भेदन या अहंकार को बदलना, और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौतों के लिए बाध्य करने के लिए रोक लगाना।37 यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यस्थता समर्थक नीति का पालन करता है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो अक्सर विचार-विमर्श के लिए आता है वह यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मामलों में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करने के लिए घरेलू सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है।

56. जी. ई. ऊर्जा शक्ति रूपांतरण में फ्रांस एस. ए. एस. बनाम आउटकुम्पू

38 संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या न्यूयॉर्क कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता को न्यायसंगत बहिष्कार जैसे घरेलू सिद्धांतों को लागू करके बाध्यकारी मध्यस्थता से रोकता है।उस मामले में, ग्यारहवें सर्किट कोर्ट ने न्यायसंगत बहिष्कार के घरेलू सिद्धांत को इस आधार पर लागू करने से इनकार कर दिया कि यह न्यूयॉर्क के तहत हस्ताक्षर आवश्यकताओं के साथ आई. सी. टी. एस. को जोड़ता है।

36 [2014] एसजीएचसी 181

37 एंड्रिजाना मिसोविक, 'मध्यस्थता के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करनाःसंयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण '(2021) 37 (3) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 749-768।

38 140 एस. सीटी. 1637 (2020)

सम्मेलन।सर्किट कोर्ट ने कहा कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II में एक सख्त आवश्यकता है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए मजबूर करने के लिए मध्यस्थता समझौते पर "वास्तव में हस्ताक्षर" करें।अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन का अनुच्छेद II अनुबंध करने वाले राज्यों को मध्यस्थता समझौतों के लिए पक्षों को संदर्भित करने के लिए घरेलू कानून लागू करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।इसके अलावा, यह देखा गया कि "अनुच्छेद II के प्रावधान कन्वेंशन में सभी खामियों को दूर करने के लिए घरेलू सिद्धांतों के उपयोग पर विचार करते हैं।" इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन मध्यस्थता समझौतों को लागू करने के लिए घरेलू कानून के उपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक व्यवस्था निर्धारित नहीं करता है।

57. अंग्रेजी अदालतों के विपरीत, अमेरिकी अदालतों ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता समझौतों का विस्तार करने के लिए गैर-सहमति वाले सिद्धांतों का उपयोग किया है।उदाहरण के लिए, अमेरिकी अदालतों ने कॉर्पोरेट पर्दा को छेद दिया है और असाधारण परिस्थितियों में अहंकार को उत्तरदायी ठहराया है जहां मूल कंपनी ने मुद्दे पर लेनदेन के संबंध में सहायक कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग किया है।39 इसी तरह, गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए अमेरिकी न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता निरोध का सिद्धांत विकसित किया गया

है।मध्यस्थता निरोध के सिद्धांत से पता चलता है कि एक पक्ष को मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध से 'प्रत्यक्ष लाभ' प्राप्त करने पर मध्यस्थता करने के अपने दायित्व से इनकार करने से रोक दिया जाता है।40 अमेरिकी अदालतों द्वारा विकसित दूसरे प्रकार का मध्यस्थता बहिष्कार हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के बीच पर्याप्त परस्पर निर्भर संबंधों पर जोर देता है।41 ऐसी स्थिति में जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले और हस्ताक्षर न करने वाले दोनों के खिलाफ ठोस कदाचार के दावे किए गए थे, अदालतों ने मध्यस्थता समर्थक नीति को आगे बढ़ाने के लिए न्यायसंगत बहिष्कार के सिद्धांत का सहारा लिया है।42 58.उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, किसी न किसी रूप में, मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए सहमति की औपचारिक आवश्यकता से आगे बढ़ गए हैं।प्राथमिक निष्कर्ष यह है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता के लिए बाध्य करने का मुद्दा

39 अमेरिकी ईंधन निगम बनाम यूटा ऊर्जा विकास कंपनी, इंक, 122 एफ. 3 डी 130,134 (2 डी सिर 1997)

40 अमेरिकन ब्यूरो, शिपिंग बनाम टेनकारा शिपयार्ड, 170 एफ. 3 डी 349,353 (2 डी सिर 1999) 41 सनकिस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स, इंक. बनाम सनकिस्ट ग्रोवर्स, इंक., 10 एफ. 3 डी 753,757 (11 वीं सिर 1993) 42 ग्रिगसन बनाम क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी, एल. एल. सी., 210 एफ. 3 डी 524 (2000)

समझौता एक तथ्य-विशिष्ट सी पहलू है।43 फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे क्षेत्राधिकारों में, एक व्यापक सहमति है कि मध्यस्थता के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की सहमति या व्यक्तिपरक इरादे को आचरण द्वारा साबित किया जा सकता है।इस तरह का व्यक्तिपरक इरादा मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन या समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी के रूप में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य से प्राप्त किया जा सकता है।हालाँकि, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को सभी क्षेत्राधिकारों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

फ्रांस जैसे क्षेत्राधिकारों में जहां इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली है, कंपनियों का समूह उन कई कारकों में से एक है जिन पर एक अदालत या न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता में शामिल होने के लिए सभी पक्षों के आपसी इरादे को निर्धारित करने पर विचार करता है।उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अब हम भारतीय संदर्भ में कंपनियों के समूह के सिद्धांत की प्रयोज्यता का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

मध्यस्थता समझौता

आई. मध्यस्थता के आधार के रूप में सहमति

59. मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जहां पक्षकार घरेलू न्यायालयों के बहिष्कार के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने बीच विवाद प्रस्तुत करने का सहमति से निर्णय लेते हैं।44 मध्यस्थता एकल मंच पर विवाद समाधान के लिए एक तटस्थ, प्रभावी और विशेषज्ञ प्रक्रिया

प्रदान करता है जिसका निर्णय अनिवार्य और पक्षों पर बाध्यकारी होता है।पक्ष की स्वायत्तता का सिद्धांत मध्यस्थता प्रक्रिया को रेखांकित करता है क्योंकि यह पक्षों को तकनीकी औपचारिकताओं को समाप्त करने और विवाद के गुण-दोष पर लागू ठोस और प्रक्रियात्मक कानूनों और नियमों पर सहमत होने की अनुमति देता है।45 पार्टी की स्वायत्तता पक्षों को मध्यस्थता का स्थान, मध्यस्थों की संख्या, मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया, मध्यस्थता प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियम और मध्यस्थता का प्रशासन करने वाली संस्था का चयन करने की अनुमति देती है।मध्यस्थता कार्यवाही को मोटे तौर पर दो चरणों में विभाजित किया गया हैःसबसे पहले

43 बर्नार्ड हनोटियाउ, 'एक मध्यस्थता खंड गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए विस्तारित किया जा सकता हैःव्यक्ति, राज्य या समूह की अन्य कंपनियाँ?' जटिल मध्यस्थताओं मेंःबहु-पक्षीय, बहु-अनुबंध, बहु-मुद्दा-एक तुलनात्मक अध्ययन 'बर्नार्ड हनोटियाउ (संस्करण) (दूसरा संस्करण, 2020) 95,194.

44 गैरी बोर्न, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉ एंड प्रैक्टिस (तीसरा संस्करण, 2021) 2.

45 भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा, (2016) 4 एस. सी. सी. 126 667

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 668

चरण एक मध्यस्थता समझौते के साथ शुरू होता है और एक मध्यस्थता पुरस्कार बनाने के साथ समाप्त होता है।दूसरा चरण मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित है।46

60. सहमति मध्यस्थता की आधारशिला है।एक मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता के लिए अपने विवादों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षों की सहमति को दर्ज करता है।बिहार राज्य खनिज में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ

विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड। 47 निर्धारित किया गया

मध्यस्थता समझौते के चार आवश्यक तत्वःi) कुछ चिंतनशील संबंध के संबंध में वर्तमान या भविष्य का अंतर होना चाहिए।

((ii) पक्षकारों को एक निजी न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के मतभेद का निपटारा करने का इरादा रखना चाहिए।

((ग) पक्षकारों को ऐसे न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए लिखित रूप में सहमत होना चाहिए।

((iv) पक्षकारों को विज्ञापन पहचान वाला होना चाहिए।

61. एक मध्यस्थता समझौता दो या दो से अधिक पक्षों द्वारा मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा अपने विवादों को हल करने के लिए एक संविदात्मक उपक्रम है, भले ही विवाद स्वयं संविदात्मक दायित्वों पर आधारित न हों।एक मध्यस्थता समझौता एक निर्णायक प्रमाण है कि पक्षों ने घरेलू अदालतों के बहिष्कार के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में अपने विवाद को प्रस्तुत करने के लिए सहमति दी

है।एक मध्यस्थता समझौते का आधार आम तौर पर पार्टियों की संविदात्मक स्वतंत्रता से पता चलता है कि वे अपने विवादों को एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के लिए सहमति से प्रस्तुत करने के अपने इरादे को संहिताबद्ध कर सकते हैं।

62. 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अनुसार, अदालतों को उन मुकदमों को छोड़कर सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जिनका संज्ञान स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।उक्त प्रावधान किसी भी व्यक्ति को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है।इसके अलावा, 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28-48 में यह प्रावधान है कि कोई भी समझौता जो किसी पक्ष को अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को लागू करने से रोकता है।

46 सतीश कुमार बनाम सुरिंदर कुमार, (1969) 2 एससीआर 244 47 (2003) 7 एससीसी 418

48 “अनुबंध अधिनियम "

अदालतों या न्यायाधिकरणों के समक्ष इस हद तक अमान्य है।हालांकि, प्रावधान विशेष रूप से एक अनुबंध को बचाता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत होते हैं कि किसी भी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।इस प्रकार, मध्यस्थता समझौतों को अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के तहत एक वैधानिक अपवाद दिया जाता है। में।

धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

अभिनिर्धारित किया कि दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता को कानून के एक स्पष्ट प्रावधान या ऐसी कानून से उत्पन्न होने वाले स्पष्ट इरादे से बाहर रखा जा सकता है।49 क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 एक वैध मध्यस्थता समझौते के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों पर प्रबल होगी।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक मध्यस्थता समझौते में दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र शामिल नहीं है, ऐसा समझौता वैध और लागू करने योग्य होना चाहिए।

63. एक मध्यस्थता समझौते को एक वैध समझौते के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अनुबंध अधिनियम के तहत निर्धारित अनुबंध कानून के सिद्धांतों को पूरा करना चाहिए।50 अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (ई) एक समझौते को प्रत्येक वादे और एक दूसरे के लिए विचार करने वाले वादों के प्रत्येक समूह के रूप में परिभाषित करती है।कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है।एक समझौते को अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अधिदेश को पूरा करना चाहिए जिसे कानून द्वारा लागू किया जा सके।धारा 10 में प्रावधान है कि सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध

करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं।धारा 13 के अनुसार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सहमति देने के लिए कहा जाता है जब वे एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत होते हैं।इस प्रकार, पक्षों के बीच सहमति एक वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए आवश्यक आधार बनाती है।

64. एक अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, एक मध्यस्थता समझौता अनुबंध कानून के सामान्य सिद्धांतों से भी बंधा होता है, जिसमें गोपनीयता का सिद्धांत भी शामिल है।निजता के सिद्धांत का अर्थ है कि एक अनुबंध अनुबंध के पक्षों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है या देनदारियां नहीं लगा सकता है।इस सिद्धांत के दो पहलू हैं:यदि सबसे पहले, केवल अनुबंध के पक्ष इसके तहत हकदार हैं या इसके द्वारा बाध्य हैं; और दूसरा, अनुबंध के पक्ष एक लागू नहीं कर सकते हैं

49 (1968) 3 एससीआर 662

50 विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1 669

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 670

किसी तीसरे पक्ष पर दायित्व।परिणामस्वरूप, कोई तीसरा पक्ष अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है और

एक अनुबंध के तहत अधिकार।एम. सी. चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में,

इस न्यायालय ने इसे कानून के एक तय किए गए सिद्धांत के रूप में माना कि एक व्यक्ति जो किसी अनुबंध का पक्ष नहीं है, वह अनुबंध की शर्तों को लागू नहीं कर सकता है, जो कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों जैसे ट्रस्ट, पारिवारिक व्यवस्था और असाइनमेंट के अधीन है।51 यह सिद्धांत कि केवल मध्यस्थता समझौते के पक्ष या तो बाध्य हैं या इस तरह के समझौते से लाभान्वित होते हैं, मध्यस्थता के लिए मौलिक है।52 यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलनों के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम में समान रूप से प्रतिबिंबित होता है। उदाहरण के लिए, UNCITRAL मॉडल लॉ की धारा 7 एक मध्यस्थता समझौते को "पक्षों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौते के रूप में बताती है जो सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक हो या नहीं।" (जोर दिया गया)

65. यह एक आम तौर पर स्वीकृत कानूनी प्रस्ताव है कि मध्यस्थता अनुबंध का मामला है और एक पक्ष को किसी भी विवाद को मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है जिसे प्रस्तुत करने के लिए वे सहमत नहीं हुए हैं।53 चूंकि सहमति मध्यस्थता की आधारशिला है, इसलिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को जबरन मध्यस्थता समझौते का "पक्ष" नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से अनुबंध की गोपनीयता और पक्ष की स्वायत्तता के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन

होगा।हालांकि, बहु-पक्षीय अनुबंधों के मामले में, अदालतों और न्यायाधिकरणों को अक्सर मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है।

ii.मध्यस्थता समझौते के पक्षकार

66. मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों को बाहर निकालने का सामान्य तरीका उन संस्थाओं की तलाश करना है जिनका नाम पाठ में लिया गया है और जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर एक पक्ष के हस्ताक्षर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए एक व्यक्ति या संस्था की सहमति की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है।हालाँकि, यह परिणाम कि जिन व्यक्तियों या संस्थाओं ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे इससे बाध्य नहीं हैं, हमेशा सही नहीं हो सकता है।एक लिखित अनुबंध के लिए आवश्यक नहीं है कि पार्टियां दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर करें जिसमें दस्तावेज़ की शर्तों को शामिल किया गया हो।

51 (1969) 2 एससीसी 343

52 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1518।

53 यूनाइटेड स्टीलवर्कर्स ऑफ अमेरिका बनाम वॉरियर एंड गल्फ नेविगेशन, (1960) 363 यूएस 574,582

समझौता।54 इसलिए, पारंपरिक "तीसरे पक्ष" के बजाय "गैर-हस्ताक्षरकर्ता" शब्द, उन स्थितियों का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त लगता है जहां मध्यस्थता के लिए सहमति हस्ताक्षर के अलावा अन्य साधनों के माध्यम से व्यक्त की जाती है।एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक व्यक्ति या संस्था है जो एक विवाद में फंसा हुआ है जो एक मध्यस्थता का विषय है, हालांकि इसने औपचारिक रूप से एक मध्यस्थता समझौते में प्रवेश नहीं किया है।55 महत्वपूर्ण निर्धारण यह है कि क्या इस तरह के गैर-हस्ताक्षरकर्ता का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ कानूनी संबंध स्थापित करना और मध्यस्थता समझौते से बाध्य होना है।ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जिन्होंने औपचारिक रूप से मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे समझौते की शर्तों से बाध्य होने का इरादा रख सकते हैं।दूसरे शब्दों में, यह मुद्दा कि मध्यस्थता समझौते का "पक्ष" कौन है, मुख्य रूप से सहमति का मुद्दा है।67. अनुबंध अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी करने या करने से दूर रहने की अपनी इच्छा को दर्शाता है, तो इस तरह के कार्य या संयम के लिए उस दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से, एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है।कहा जाता है कि प्रस्ताव को तब स्वीकार किया जाता है जब जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है वह उनकी सहमति देता है। स्वीकृति मिलने पर प्रस्ताव वादा बन जाता है।प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक सेट, एक दूसरे के लिए विचार करना, एक समझौता है।महत्वपूर्ण रूप से, धारा 9 में प्रावधान है कि एक वादे को व्यक्त कहा जाता है यदि किसी वादे का प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में की जाती है, जबकि एक वादे को

निहित कहा जाता है यदि ऐसा प्रस्ताव या स्वीकृति "शब्दों के अलावा अन्यथा की जाती है।" इस प्रकार, एक अनुबंध या तो व्यक्त या निहित हो सकता है।

68. चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स स्पष्ट और निहित अनुबंधों के बीच के अंतर को इस प्रकार बताती हैः

"अनुबंध या तो व्यक्त या निहित हो सकते हैं।भिन्नता नहीं है

कानूनी प्रभावों में से एक लेकिन केवल उस तरीके से जिसमें पक्षों की सहमति प्रकट होती है। अनुबंधों को तब व्यक्त किया जाता है जब उनकी शर्तें पार्टियों द्वारा शब्दों में बताई जाती हैं। उन्हें अक्सर तब निहित कहा जाता है जब उनकी शर्तों को इस तरह से नहीं कहा जाता है, उदाहरण के लिए, जब कोई यात्री

54 पोलक एंड मुल्ला, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफी सी रिलीफ्स एक्ट (14 वां संस्करण, 2016) 235. 55 स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में सहमति पर पुनर्विचारःगैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए एक सामान्य सिद्धांत (2017) 8 जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट 610।

671

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 672

बस में चढ़ने की अनुमति हैःपक्षकारों के आचरण से कानून का तात्पर्य यात्री द्वारा किराया देने का वादा और बस के संचालक द्वारा उसे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक ले जाने का वादा है।[...] एक्सप्रेस

और निहित अनुबंध दोनों शब्द के सही अर्थों में अनुबंध हैं, क्योंकि वे दोनों पक्षों के समझौते से उत्पन्न होते हैं, हालांकि एक मामले में समझौता शब्दों में और दूसरे में प्रकट होता है।

व्यवहार द्वारा मामला।चूंकि, जैसा कि हमने देखा है, समझौता एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक कार्य है, आचरण से एक अनुमान है, और चूंकि एक स्पष्ट अनुबंध की कई शर्तें अक्सर निहित होती हैं, इसलिए यह इस प्रकार है कि व्यक्त और निहित अनुबंधों के बीच अंतर का बहुत कम महत्व है।" 56 69.उपरोक्त व्याख्या इस निष्कर्ष को जन्म देती है कि एक निहित अनुबंध के मामले में, प्रश्न अनुबंध की शर्तों से बाध्य होने के लिए पक्षों की सहमति के निर्धारण के इर्द-गिर्द घूमता है।इस तरह का दृढ़ संकल्प कृत्यों या आचरण के माध्यम से प्रकट होता है।आचरण द्वारा निहित अनुबंध के सिद्धांत को भी इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।हाजी में

मोहम्मद इशाक बनाम मोहम्मद इकबाल, 57 वादी ने तंबाकू की आपूर्ति की

अभियुक्त के लिए।हालाँकि पक्षों के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं था, प्रतिवादी ने सामान स्वीकार कर लिया, लेकिन कथित तौर पर वादी द्वारा बार-बार की गई मांगों के बावजूद बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा।इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि माल को स्वीकार करने और वादी द्वारा उठाए गए किसी भी मांग पत्र को अस्वीकार नहीं करने में प्रतिवादियों का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक प्रत्यक्ष अनुबंध जिसे कानून में आचरण द्वारा एक निहित

अनुबंध कहा जाता है, उनके बीच था।" भारतीय अनुबंध कानून के तहत, यह माना जाता है कि कार्य या आचरण एक अनुबंध द्वारा बाध्य होने के लिए एक पक्ष की सहमति का एक संकेतक हो सकता है।यह इस तथ्य पर विचार करते हुए एक मध्यस्थता समझौते पर भी लागू होता है कि यह अनुबंध का एक प्राणी है।हालांकि, एक मध्यस्थता समझौते को वैध और लागू करने योग्य होने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ता है।

70. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (एच) एक "पक्ष" को मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के रूप में परिभाषित करती है।धारा 7 एक मध्यस्थता समझौते की अवहेलना करती है जिसका अर्थ पक्षकारों द्वारा सभी या कुछ निश्चित रूप से मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है।

56 चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ह्यूग बील (संस्करण) (32 वां संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, 2015) पैरा 1-104।

57 (1978) 2 एससीसी 493

विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।" धारा 7 में यह अपेक्षा की गई है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए।धारा 7 उन परिस्थितियों को इंगित करती है जिनमें इसे लिखित रूप में एक समझौता माना जाता है।इस तरह के समझौते को किसी दस्तावेज़ में, संचार के आदान-प्रदान में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या दावे के बयान में सन्निहित किया जा सकता है, जो बचाव में निहित नहीं है।में।

विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा व्यापार निगम, 58 इस न्यायालय ने कहा कि

कानूनी संबंध का अर्थ है एक ऐसा संबंध जो कानूनी दायित्वों और कर्तव्यों को जन्म देता है, और एक अधिकार प्रदान करता है।ऐसा अधिकार संविदात्मक या गैर-संविदात्मक हो सकता है।गैर-संविदात्मक कानूनी संबंध के मामले में, कार्रवाई का कारण यातना, पुनर्स्थापन, वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन, या कार्रवाई के किसी अन्य गैर-संविदात्मक कारण में उत्पन्न होता है।इस प्रकार, धारा 7 में अंतर्निहित विधायी आशय से पता चलता है कि कोई भी कानूनी संबंध, जिसमें ऐसे संबंध शामिल हैं जहां व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच कोई अनुबंध नहीं है, लेकिन जिनके कार्यों या आचरण ने संबंध को जन्म दिया है, धारा 7 के तहत मध्यस्थता समझौते का विषय बन सकता है। यह दृष्टिकोण टिप्पणियों के अनुरूप है

फियोना ट्रस्ट एंड होल्डिंग कंपनी बनाम प्रीवालोव में लॉर्ड हॉफ मैन जहाँ

यह देखा गया कि "मध्यस्थता खंड का निर्माण इस धारणा से शुरू होना चाहिए कि तर्कसंगत व्यवसायियों के रूप में पक्षों ने उस संबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का इरादा किया होगा जिसमें उन्होंने प्रवेश किया है या उसी न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने के लिए प्रवेश करने का इरादा है।" 59 (जोर दिया गया)

71. धारा 7 (3) एक मध्यस्थता समझौते को लिखित रूप में होने की अपेक्षा करती है।धारा 7 (4) तीन परिस्थितियों को विस्तार से बताती है जब मध्यस्थता समझौते को लिखित में कहा जा सकता है।धारा 7 (4) (ए) के तहत निर्धारित पहली परिस्थिति के अनुसार, एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि उस पर पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।यह परिस्थिति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां पक्षों ने औपचारिक रूप से निष्पादित किया है और मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध में अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करके पक्षों की स्थिति को स्पष्ट रूप से ग्रहण किया है।ऐसी स्थितियों में, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को मध्यस्थता समझौते के पक्षों को सूचित करने के लिए केवल हस्ताक्षर पृष्ठ या पाठ का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है।

58 (2021) 2 एससीसी 59 [2007] यूकेएचएल 40 673

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 674

72. धारा 7 (4) (बी) दूसरी परिस्थिति प्रदान करती है, जिसके अनुसार एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों के आदान-प्रदान में निहित है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार शामिल है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।इस प्रावधान के अनुसार, पक्षों द्वारा विधिवत अनुमोदित विभिन्न दस्तावेजों से मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।60 धारा 7 (4) (बी) हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ एक दस्तावेज के रूप में एक समझौते की पारंपरिक भावना को समाप्त करती है।बल्कि, यह दस्तावेजों के आदान-प्रदान के कार्यों के माध्यम से व्यक्तियों या संस्थाओं की सहमति की अभिव्यक्ति पर जोर देता है।हालाँकि, उक्त प्रावधान का महत्वपूर्ण पहलू इस तथ्य में निहित है कि पक्षों को साक्ष्य के दस्तावेजी रिकॉर्ड के माध्यम से अपने समझौते को दर्ज करने में सक्षम होना चाहिए।इन ग्रेट ऑफ शोर लिमिटेड बनाम

ईरानी अपतटीय इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी, यह न्यायालय

यह पाया गया कि धारा 7 (4) (बी) अदालत से यह पूछने की अपेक्षा करती है कि क्या समझौते का रिकॉर्ड पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों के आदान-प्रदान में पाया जाता है।61 इस प्रकार, व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा सहमत होने के कार्य का अनुमान अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा संबंधित दस्तावेजों और संचार से लगाया या निकाला जाना चाहिए, जिनमें से किसी को भी पारंपरिक अनुबंध के बराबर नहीं माना जा सकता है।

73. तीसरी परिस्थिति धारा 7 (4) (सी) के तहत प्रदान की गई है, जिसके अनुसार एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में है यदि यह दावे और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान में निहित है जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।एक दो-न्यायाधीश

एस. एन. प्रसाद बनाम मोनेट फाइनेंस लिमिटेड 62 में इस न्यायालय की पीठ ने स्पष्टीकरण दिया

कि धारा 7 (4) (ग) के प्रयोजनों के लिए "दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान" होगा यदि किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी मुकदमे, याचिका या आवेदन में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का दावा किया जाता है, और यदि बचाव, प्रतिवाद या लिखित बयान में इसका कोई खंडन नहीं है।इस प्रकार, तीसरी परिस्थिति में न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से इनकार नहीं करने में व्यक्ति या संस्था का आचरण इसके निर्णायक प्रमाण की ओर ले जाता है।

60 शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड बनाम कोला शिपिंग लिमिटेड, (2009) 2 एससीसी 134; ट्राइमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई लिमिटेड बनाम वेदांता एल्यूमीनियम लिमिटेड, (2010) 3 एससीसी 1

61 (2008) 14 एससीसी 240 62 (2011) 1 एससीसी 320

अस्तित्व।धारा 7 (4) में निहित तीनों परिस्थितियाँ मध्यस्थता समझौते से बंधे पक्षों के आपसी इरादे को निर्धारित करने की दिशा में तैयार हैं।

74. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में दो पहलू हैं:एक मूल पहलू और एक औपचारिक पहलू।मूल पहलू धारा 7 (1) है जो पक्षों को मध्यस्थता के लिए कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।पक्षों के बीच और उनके बीच कानूनी संबंध या तो संविदात्मक या गैर-संविदात्मक हो सकते हैं।कानूनी संबंध संविदात्मक प्रकृति के होने के लिए, उन्हें अनुबंध अधिनियम में निहित भारतीय अनुबंध कानून की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में यह दिखाया गया है कि एक अनुबंध या तो व्यक्त या निहित हो सकता है, जिसका अनुमान पक्षों की कार्रवाई या आचरण के आधार पर लगाया जाता है।इस प्रकार, किसी कानूनी संबंध में प्रवेश करने के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है-यह निर्धारित करने के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या वे अपनी कार्रवाई या आचरण के कारण कानूनी संबंध में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं या सहमति देते हैं।

75. दूसरा पहलू धारा 7 (3) में निहित है जो एक लिखित मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता को निर्धारित करता है।यदि समझौते का रिकॉर्ड है तो पक्षों द्वारा लिखित मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।63 एक लिखित मध्यस्थता समझौते की अनिवार्य आवश्यकता केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि घरेलू न्यायालयों के बहिष्कार के लिए मध्यस्थता के लिए अपने विवादों को संदर्भित करने के लिए पक्षों की सहमति का एक स्पष्ट रूप से स्थापित रिकॉर्ड है।76. धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (एच) में स्पष्ट रूप से "पक्ष" को मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध के लिए हस्ताक्षरकर्ता होने की

आवश्यकता नहीं है।यह व्याख्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधानों में सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप है कि मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।2006 में संशोधित UNCITRAL मॉडल कानून अनुच्छेद 7 के तहत मध्यस्थता समझौते के लिए लिखित आवश्यकता को निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित करता हैः

“(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि इसकी सामग्री दर्ज की जाती है।

किसी भी रूप में, चाहे मध्यस्थता समझौता या अनुबंध मौखिक रूप से, आचरण द्वारा या अन्य माध्यमों से किया गया हो या नहीं।”

63 गोविंद रबर लिमिटेड बनाम मेसर्स लुई ड्रेफस कमोडिटीज, (2015) 13 एस. सी. सी. 477 675

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 676

उपरोक्त प्रावधान में कहा गया है कि एक मध्यस्थता समझौता किसी भी रूप में किया जा सकता है, उदाहरण के लिए मौखिक या मौन रूप से, जब तक कि समझौते की सामग्री दर्ज की जाती है।यह पार्टियों के हस्ताक्षर या पार्टियों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान की आवश्यकता को समाप्त करता है।77. न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 2 में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित या पत्रों या तारों के आदान-प्रदान में निहित एक अनुबंध या मध्यस्थता समझौते में एक मध्यस्थ खंड को शामिल करने के लिए "लिखित समझौते" की अवहेलना की गई है।UNCITRAL मॉडल कानून का अनुच्छेद 7 एक लिखित मध्यस्थता समझौते के लिए अधिक अनुकूल आवश्यकता स्थापित करता है।2006 में, UNCITRAL ने सिफारिश की कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II पैराग्राफ 2 में वर्णित परिस्थितियों को यह मानते हुए लागू किया जाए कि उसमें वर्णित परिस्थितियां संपूर्ण नहीं हैं।” 64 इसके अतिरिक्त, इसने यह भी सिफारिश की कि यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून के अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 1 को लागू किया जाना चाहिए "किसी भी इच्छुक पक्ष को उस देश के कानून या संधियों के तहत अपने अधिकारों का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए, जहां एक मध्यस्थता समझौते पर भरोसा करने की मांग की जाती है, इस तरह के मध्यस्थता समझौते की वैधता की मान्यता प्राप्त करने के लिए।” मध्यस्थता अधिनियम काफी हद तक UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित है। इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय UNCITRAL मॉडल कानून का उल्लेख किया जा सकता है। 65 यद्यपि UNCITRAL मॉडल कानून की संशोधित धारा 7 को भारतीय कानून में नहीं अपनाया गया है, लेकिन यह आधुनिक वाणिज्यिक वास्तविकता को दर्शाता है जहां तकनीकी कानूनी औपचारिकताओं पर सार को प्राथमिकता दी जाती है।66

78. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 को पढ़ने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:पहला, मध्यस्थता समझौते व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच या उनके बीच एक कानूनी संबंध से उत्पन्न होते हैं जो संविदात्मक या अन्यथा हो सकते हैं; दूसरा, ऐसी स्थितियों में जहां कानूनी संबंध प्रकृति में संविदात्मक है, संबंध की प्रकृति हो सकती है

64 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून, 10 जून 1958 को न्यूयॉर्क में किए गए विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन के अनुच्छेद II, पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद VII, पैराग्राफ 1 की व्याख्या के संबंध में सिफारिश (7 जुलाई 2006 को UNCITRAL द्वारा अपनाया गया)।

65 सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम एन**.** ई**.** पी**.** सी**.** इंडिया लिमिटेड**, (1999) 2** एस**.** सी**.** सी**. 479,** पैरा **9;** पी**.** मनोहर रेड्डी और ब्रदर्स बनाम महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम**, (2009) 2** एस**.** सी**.** सी**. 494,** पैरा **27**।

66 रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (7 वां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2023) पैरा 2.23।

सामान्य अनुबंध कानून के सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए; तीसरा, व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता होना आवश्यक नहीं है कि वे इसके द्वारा बाध्य हों; चौथा, गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के मामले में, अदालतों के लिए महत्वपूर्ण निर्धारण यह है कि क्या व्यक्ति या संस्थाएं मध्यस्थता समझौते या अपने कार्यों या आचरण के माध्यम से मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध से बाध्य होने का इरादा रखती हैं या सहमति देती हैं; पांचवां, लिखित मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन जिस रूप में ऐसा समझौता दर्ज किया जाता है वह अप्रासंगिक है; छठा, लिखित मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बाध्य करने की संभावना को बाहर नहीं करती है यदि उनके बीच एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध है।

79. यह माना जाता है कि मध्यस्थता समझौते के औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता ऐसे पक्ष हैं जो इसके लिए बाध्य होंगे।हालांकि, असाधारण मामलों में जिन व्यक्तियों या संस्थाओं ने लिखित मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं या औपचारिक रूप से सहमति नहीं दी है, उन्हें इस तरह के समझौते से बाध्य माना जा सकता है।जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, गोपनीयता का सिद्धांत किसी अनुबंध के लिए तीसरे पक्ष पर अधिकारों और देनदारियों के अधिरोपण को सीमित करता है।आम तौर पर, केवल मध्यस्थता समझौते के पक्ष राहत और उपचार के संदर्भ में समझौते के पूर्ण प्रभाव के अधीन हो सकते हैं क्योंकि वे मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए सहमत थे।इसलिए, अदालतों या न्यायाधिकरणों के समक्ष निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या कोई गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए सहमत है।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य है, अदालतें और न्यायाधिकरण अनुबंध कानून और कॉर्पोरेट कानून के विशिष्ट सिद्धांतों को लागू करते हैं।कानूनी सिद्धांत मध्यस्थता समझौते से बंधे पक्षों के इरादों को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट संविदात्मक भाषा और तथ्यात्मक सेटिंग्स का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।67

80. गैरी बॉर्न सुझाव देते हैं कि कानूनी सिद्धांत और सिद्धांत एक मध्यस्थता समझौते से बंधे पक्षों के वास्तविक इरादे को निर्धारित करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।इसलिए, गैर-

हस्ताक्षरकर्ताओं या 'तीसरे पक्षों' के लिए मध्यस्थता समझौते के 'विस्तार' जैसी शब्दावली का उपयोग करना गलत हैः

67 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1531।

677

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 678

“न्यायिक मामला कानून और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर टिप्पणी कभी-कभी गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं, या एक या अधिक पूर्वगामी सिद्धांतों के आधार पर "तीसरे पक्ष" के लिए एक मध्यस्थता समझौते के "विस्तार" का संदर्भ देती है।ये अभिव्यक्तियाँ गलत हैं, क्योंकि उनका अर्थ है कि एक इकाई जो मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष नहीं है, फिर भी पार्टियों की सहमति के अलावा कुछ और के आधार पर उस समझौते के प्रभाव के अधीन है।"विस्तार" या "तीसरे पक्ष" के संदर्भों के विपरीत, अधिकांश सिद्धांत [.] यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं कि एक इकाई वास्तव में मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है-जिसे इसलिए "तीसरे पक्ष" के लिए "विस्तारित" करने की आवश्यकता नहीं है-क्योंकि उस पक्ष के कार्यों से समझौते के लिए सहमति बनती है, या अन्यथा समझौते के औपचारिक निष्पादन की कमी के बावजूद इसे समझौते से बांध दिया जाता है। इसलिए मध्यस्थता समझौते को आम तौर पर "विस्तारित" नहीं किया जाता है, बल्कि उन सच्चे पक्षों की पहचान की जाती है जिन्होंने मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति दी है।”

81. दुनिया भर के न्यायालय और न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों की सहमति निर्धारित करने के लिए पारंपरिक संविदात्मक और वाणिज्यिक सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं।आम तौर पर, सहमति आधारित सिद्धांत जैसे एजेंसी, नवीनता, असाइनमेंट, कानून का संचालन, विलय और उत्तराधिकार, और तीसरे पक्ष के लाभकारी निकायों को अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में लागू किया गया है।असाधारण परिस्थितियों में, गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए गैर-सहमति वाले सिद्धांतों जैसे कि कॉर्पोरेट घूंघट को भेदना या अहंकार और अवरोध को बदलना भी लागू किया गया है।कंपनियों के समूह का सिद्धांत एक ऐसा सहमति-आधारित सिद्धांत है जिसे एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए पक्षों के वास्तविक इरादे की पहचान करने के लिए, हालांकि विवादास्पद रूप से, लागू किया गया है।

कंपनी समूह सिद्धांत **I.**अलग कानूनी व्यक्तित्व

82. समूह कंपनियों की घटना आर्थिक जीवन और व्यावसायिक संगठन की आधुनिक वास्तविकता है।समूह कंपनियाँ मूल कंपनी के नियंत्रण में औपचारिक या अनौपचारिक संरचनाओं में एक साथ जुड़े अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं का एक समूह है।समूह की कंपनियों को भारतीय संदर्भ में "निजी रूप से आयोजित और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में काम करती हैं, जिनमें से

प्रत्येक को एक अलग कानूनी इकाई के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन जो सामूहिक रूप से उद्यमशीलता के तहत हैं।

एक आम प्राधिकरण, आमतौर पर एक परिवार का वित्तीय और रणनीतिक नियंत्रण, और एक समान व्यक्तित्व, जातीयता या समुदाय के आसपास बनाए गए विश्वास-आधारित संबंधों से जुड़े होते हैं।" 68 मूल निगम के दायित्व को सीमित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, निवेशकों के साथ व्यावसायिक उद्यमों में प्रवेश करने, घरेलू कॉर्पोरेट निवास की स्थापना करने और कर दायित्व से बचने जैसे असंख्य उद्देश्यों के लिए मूल और सहायक कंपनियों को शामिल करते हुए एक समूह कंपनी बनाई जाती है।

83. अलग कानूनी व्यक्तित्व का सिद्धांत कॉर्पोरेट कानून की आधारशिला रहा है।सालोमोन बनाम सालोमोन, 69 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि एक कंपनी कानूनी रूप से प्रवर्तकों, निदेशकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों से पूरी तरह से अलग व्यक्ति है।अलग कानूनी व्यक्तित्व का सिद्धांत कॉर्पोरेट समूहों पर समान रूप से लागू होता है।एक मूल कंपनी को आम तौर पर सहायक कंपनी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारक है।कंपनी अधिनियम, 2013 70 ने एक सहायक कंपनी को एक अलग कानूनी इकाई के रूप में वैधानिक रूप से मान्यता दी है।71 2013 के अधिनियम की धारा 2 (46) एक होल्डिंग कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित करती है जिसमें एक या अधिक अन्य कंपनियां सहायक कंपनियां हैं।धारा 2 (87) का अर्थ "सहायक कंपनी" से है एक ऐसी कंपनी जिसमें धारक कंपनी निदेशक मंडल की संरचना पर नियंत्रण रखती है और मतदान अधिकारों पर कम से कम 50 प्रतिशत का नियंत्रण हित रखती है।यद्यपि एक होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी में एक नियंत्रक हित का मालिक है, उन्हें अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में माना जाता है।समूह कंपनियों की संरचनाएँ बहुराष्ट्रीय निगमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने व्यवसायों की संरचना करने की अनुमति देती हैं ताकि निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न का लाभ उठाया जा सके और निगम का व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

84. वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी बनाम भारत संघ 72 मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में निगमित अलगाव के सिद्धांतों पर जोर दिया:

68 जयती सरकार, 'बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया' इन अस्ली कोपलान, ताकाशी हिकिनो, और जेम्स लिंकन (संस्करण) द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ बिजनेस ग्रुप्स (2010) 299

69 [1897] एसी 22

70 "2013 ऐक्ट "

71 बलवंत राय सलूजा बनाम एयर इंडिया, (2014) 9 एस. सी. सी. 407

72 (2012) 6 एससीसी 613 679

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 680

101. एक कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्ति है और यह तथ्य कि इसके सभी शेयरों का स्वामित्व एक व्यक्ति या माता-पिता के पास है, इसका इसके अलग कानूनी अस्तित्व से कोई लेना-देना नहीं है। यदि स्वामित्व वाली कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, तो परिसमापक और उसकी मूल कंपनी को सहायक कंपनी की संपत्ति मिल जाएगी।किसी भी प्राधिकरण में सहायक की संपत्ति को माता-पिता की संपत्ति नहीं माना गया है जब तक कि वह एक एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।इस प्रकार, भले ही एक सहायक कंपनी आम तौर पर एक मूल कंपनी के अनुरोध का पालन कर सकती है, यह केवल मूल कंपनी की कठपुतली नहीं है।अंतर शक्ति रखने या प्रेरक स्थिति रखने के बीच है। हालांकि मूल और सहायक कंपनियों के लिए एक समूह के रूप में काम करना फायदेमंद हो सकता है, प्रत्येक सहायक यह देखने के लिए देखेगी कि क्या अलग-अलग वाणिज्यिक हित हैं जिन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए।"

85. कॉर्पोरेट व्यक्तित्व की अलगाव को अदालतों द्वारा असाधारण स्थितियों में नजरअंदाज कर दिया जाएगा जहां एक कंपनी का उपयोग सदस्यों और शेयरधारकों द्वारा धोखाधड़ी करने या कर देनदारियों से बचने के लिए किया जाता है।यदि न्यायालय, तथ्यात्मक साक्ष्य के आधार पर, यह निर्धारित करता है कि कंपनी सदस्यों या शेयरधारकों के एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही थी, तो यह व्यक्तियों को दायित्व देने के लिए कंपनी के अलग व्यक्तित्व की अनदेखी करेगा।टाटा इंजीनियरिंग में

और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 73, संविधान के समक्ष मुद्दा

इस न्यायालय की पीठ यह थी कि क्या किसी कंपनी को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए एक नागरिक के रूप में माना जा सकता है।कंपनी ने आग्रह किया कि कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाना चाहिए ताकि याचिका को शेयरधारकों के नेतृत्व में एक एफ. आई. के रूप में माना जा सके।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निगम का पर्दा हटाया जा सकता है जहां धोखाधड़ी को रोकने का इरादा है या दुश्मन के साथ व्यापार को हराने की कोशिश की जाती है।

86. समूह कंपनियों के मामले में, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां एक होल्डिंग कंपनी अपने नियंत्रण का दुरुपयोग करने की सीमा तक, देयता से बचने या छिपाने के लिए सहायक कंपनी के कामकाज पर पूरी तरह से हावी हो जाती है।ऐसी स्थितियों में, अदालतें दोनों कंपनियों के बीच कॉर्पोरेट अलगाव की अवहेलना करने और उन्हें एक इकाई के रूप में मानने के लिए "अहंकार को बदलने" या कॉर्पोरेट पर्दे को भेदने के सिद्धांत को लागू करती हैं।74 एल. आई. सी. बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, 75 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

73 (1964) 6 एससीआर 885

74 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1545। 75 (1986) 1 एससीसी 264

यह ध्यान दिया गया कि विशिष्ट कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा सकता है जहां सहयोगी कंपनियां अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं, वास्तव में, एक चिंता का हिस्सा हैं।पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी ने कहाः“90. […] आम तौर पर और व्यापक रूप से, हम कह सकते हैं कि निगमित पर्दा उठाया जा सकता है जहां एक क़ानून स्वयं पर्दा उठाने पर विचार करता है, या धोखाधड़ी, या अनुचित आचरण को रोकने का इरादा है, या एक कर कानून या एक लाभकारी प्रतिशत क़ानून से बचने की कोशिश की जाती है या जहां संबद्ध कंपनियाँ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई हैं, वास्तव में, एक चिंता का हिस्सा हैं।उन मामलों के वर्गों की गणना करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है जहां पर्दा उठाने की अनुमति है, क्योंकि यह आवश्यक रूप से प्रासंगिक वैधानिक या अन्य प्रावधानों, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विवादित आचरण, सार्वजनिक हित के तत्व की भागीदारी, उन पक्षों पर प्रभाव, जिन्हें आरोपित किया जा सकता है, आदि पर निर्भर होना चाहिए।”

87. निगमित पर्दा उठाने के सिद्धांत का अनुप्रयोग न्याय और समानता के प्रमुख विचारों पर निर्भर करता है।76 अक्सर, अदालतें कॉर्पोरेट पर्दा को छेद देती हैं जब कॉर्पोरेट व्यक्तित्व की अलगाव को बनाए रखते हुए न्याय, सुविधा और सार्वजनिक हितों के खिलाफ पाया जाता है।77 बलवंत राय सलूजा बनाम एयर इंडिया, 78 में इस न्यायालय ने आगाह किया कि निगमित आवरण को छेदने का सिद्धांत प्रतिबंधात्मक तरीके से लागू किया जाना चाहिए और केवल उन परिदृश्यों में लागू किया जाना चाहिए जहां यह स्पष्ट हो कि सहायक कंपनी केवल दायित्व से बचने के उद्देश्य से होल्डिंग कंपनी द्वारा जानबूझकर बनाई गई छल।यह आगे देखा गया कि कॉर्पोरेट घूंघट को छेदने का इरादा ऐसा होना चाहिए जो होल्डिंग कंपनी द्वारा की गई गलती को सुधारने का प्रयास करे।मध्यस्थता के संदर्भ में, निगमित पर्दा को छेदने के सिद्धांत का बहुत कम उपयोग किया गया है क्योंकि यह गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौते से बांधने के लिए सद्भावना और समानता के प्रमुख विचारों पर जोर देकर पक्षों के इरादे की अवहेलना करता है।

88. इसके अलावा, चूंकि एक समूह में कंपनियों का अलग कानूनी व्यक्तित्व होता है, इसलिए सामान्य शेयरधारकों या निदेशकों की उपस्थिति से

76 दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड, (1996) 4 एससीसी 662

77 कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य, (2003) 6 एससीसी 1

78 (2014) 9 एससीसी 407 681

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 682

यह निष्कर्ष कि सहायक कंपनी धारक कंपनी के कार्यों से बाध्य होगी।प्रवर्तकों या निदेशकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दिए गए बयान या अभ्यावेदन किसी कंपनी को बाध्य नहीं करेंगे।इसी तरह, केवल यह तथ्य कि दोनों कंपनियों के साझा शेयरधारक या एक साझा निदेशक मंडल है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा कि वे एक एकल आर्थिक इकाई हैं।एकल आर्थिक इकाई या एकल आर्थिक इकाई सिद्धांत निगम पर सामान्य उद्यम दायित्व लगाता है।

समूह।डी एच एन फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड बनाम टावर हैमलेट्स लंदन

बरो काउंसिल 79, लॉर्ड डेनिंग ने माना कि तीन कंपनियों के एक समूह को दो कारकों के आधार पर एक एकल आर्थिक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए:सबसे पहले, मूल कंपनी के पास सहायक कंपनियों के सभी शेयरों का स्वामित्व इस हद तक था कि वह दी गई सहायक कंपनियों की हर आवाजाही को नियंत्रित करती थी; और दूसरा, समूह की सभी तीन कंपनियों ने वस्तुतः भागीदार के रूप में काम किया और उन्हें अलग से नहीं माना जा सकता था।इस प्रकार, दो या दो से अधिक कंपनियाँ एक ही आर्थिक इकाई का गठन करती हैं या नहीं, इसका निर्धारण एक सामान्य प्रयास या उद्यम के अनुसरण में कार्य करने के लिए कंपनियों के समेकित प्रभावों पर निर्भर करता है।

89. उपरोक्त चर्चा से, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट समूह के भीतर संस्थाओं का अलग कानूनी व्यक्तित्व होता है, जिसे धोखाधड़ी जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के बीच का अंतर मौलिक है, और आर्थिक सुविधा का सहारा लेकर इसे आसानी से कम नहीं किया जा सकता है।80 कानूनी रूप से, मूल कंपनी के अधिकारों और देनदारियों को सहायक कंपनी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, और इसके विपरीत, जब तक कि ऐसा करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार न हो।

ii.सहमति के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना

90. मध्यस्थता कानून के संदर्भ में, पक्षों का इरादा मध्यस्थता समझौते में उपयोग किए गए शब्दों से लिया जाना चाहिए।मध्यस्थता समझौते का अर्थ लगाते समय, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मानव मस्तिष्क की पेचीदगियों में गहराई से न जाए, बल्कि केवल पक्षों के व्यक्त किए गए इरादों पर विचार करे।81 अनुबंध में उपयोग किए गए शब्द वाणिज्यिक को प्रतिबिंबित करते हैं।

79 [1976] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 852 (2)

80 बैंक ऑफ टोक्यो बनाम करूण, (1986) 3 सभी ई. आर. 468

81 कमला देवी बनाम तख्तमल लैंड, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 859; बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम ई. एस. सोलर पावर (पी) लिमिटेड, (2021) 6 एस. सी. सी. 718

पक्षों के बीच समझ।पक्षों के इरादे का पता अनुबंध में उपयोग किए गए शब्दों से लगाया जाना चाहिए, जो आसपास की परिस्थितियों और इस तरह के अनुबंध के उद्देश्य के आलोक में माना जाता है।82

91. एक मध्यस्थता समझौता अपने कानूनी संबंधों के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के तरीके और तरीके के संबंध में व्यावसायिक संस्थाओं की वाणिज्यिक समझ को समाहित करता है।अधिकांश स्थितियों में, अनुबंध की भाषा केवल ऐसे अनुबंध के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के इरादे का संकेत देती है, न कि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं का।हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ कोई व्यक्ति या संस्था मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, फिर भी हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ उनके कानूनी संबंधों और अंतर्निहित अनुबंध के प्रदर्शन में भागीदारी के कारण इस तरह के मध्यस्थता समझौते के लिए एक वास्तविक पक्ष होने का आभास देती है।विशेष रूप से कई पक्षों और अनुबंधों से जुड़े जटिल लेनदेन वाले मामलों में, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता सहित आगामी बोझों से बाध्य होने के लिए औपचारिक रूप से सहमति दिए बिना संविदात्मक दायित्वों की बातचीत या प्रदर्शन में काफी हद तक शामिल हो सकता है।

92. आधुनिक वाणिज्यिक वास्तविकता से पता चलता है कि अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ एक कंपनी जिसने मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, वह हमेशा बातचीत करने या अंतर्निहित संविदात्मक दायित्वों का पालन करने वाली नहीं होती है।ऐसी स्थितियों में, औपचारिक सहमति पर जोर देने से ऐसे गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे कार्यवाहियों की बहुलता और मध्यस्थता समझौते का विभाजन होगा।

विवाद।ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम, 83 में इस न्यायालय ने कहा कि

न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे उस वाणिज्यिक समझ को व्यावसायिक प्रभाव की भावना प्रदान करें।" अदालतों को अनुबंधों की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जिससे उन्हें पक्षों के वाणिज्यिक हितों को अमान्य करने के बजाय प्रभावशीलता की भावना मिले।अनुबंध का अर्थ एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण को अपनाकर एकत्र किया जाना चाहिए, जिसे संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण और कानूनी व्याख्या द्वारा विफल नहीं होने दिया जाना चाहिए।" 84 इसलिए, सहमति के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो

82 बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास, (2009) 5 एससीसी 313; एम. दयानंद रेड्डी बनाम एपी औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड, (1993) 3 एससीसी 137

83 (2016) 10 एस. सी. सी. 386

84 भारत संघ बनाम डी. एन. रेवरी, (1976) 4 एस. सी. सी. 147 683

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 684

व्यावसायिक लेन-देन की परिस्थितियों, प्रत्यक्ष आचरण और वाणिज्यिक पहलुओं पर विचार करें।

93. जैसा कि प्रोफेसर हनोटियाउ सुझाव देते हैं, सहमति के लिए एक आधुनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हैः

"मेरा सुझाव है कि सहमति के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण का उल्लेख करना अधिक सटीक है; एक ऐसा दृष्टिकोण जो अधिक व्यावहारिक है, तथ्यों के विश्लेषण पर अधिक केंद्रित है, जो वाणिज्यिक अभ्यास, आर्थिक वास्तविकता, व्यापार उपयोग और कंपनियों के समूह और बहु-पक्षीय बहु-अनुबंध परिदृश्यों में जुड़े समझौतों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के जटिल और बहुआयामी आयामों पर जोर देता है; एक ऐसा दृष्टिकोण जो अब सहमति व्यक्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी सभी विभिन्न अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखता है और संबंधित व्यक्तियों या कंपनियों के आचरण को पहले की तुलना में बहुत अधिक महत्व देता है।" 85

94. हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि जहां एक लिखित मध्यस्थता समझौता स्पष्ट रूप से पक्षकारों को निर्धारित करता है, अदालतें या न्यायाधिकरण समझौते में हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के अलावा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को बांधने के इरादे को नहीं पढ़ सकते हैं।रूप कुमार बनाम मोहन थेदानी, 86 पर भरोसा रखा गया था, जहाँ इस न्यायालय ने कहा था कि "जहाँ भी लिखित लिखतों को या तो कानून की आवश्यकता से, या पक्षों के अनुबंध से, सत्य के भंडार और स्मारक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहाँ किसी भी अन्य साक्ष्य का उपयोग या तो ऐसे लिखतों के विकल्प के रूप में, या उनका खंडन करने या उन्हें बदलने के लिए नहीं किया जाता है।" नतीजतन, यह आग्रह किया गया कि अदालतें या न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते की व्याख्या इस तरह से नहीं कर सकते हैं ताकि समझौते में नामित नहीं किए गए पक्षों तक इसकी पहुंच का विस्तार किया जा सके।

95. मध्यस्थता कानून एक स्वायत्त कानूनी कानून है।जबकि निगमित कानून और अनुबंध कानून का मुख्य उद्देश्य मूल कानूनी दायित्व का आरोप लगाना है, मध्यस्थता कानून के पीछे मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद पर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है या नहीं।एक ओर, अदालतें और न्यायाधिकरण पक्षकारों के किसी को व्यक्ति या न्यायाधीश नहीं बनाने के निर्णय को हल्के में नहीं ले सकते हैं।

85 बर्नार्ड हनोटियाउ, 'मध्यस्थता के लिए सहमतिः क्या हम एक समान दृष्टि साझा करते हैं?' (2011) 27(4) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 539,554

86 (2003) 6 एस. सी. सी. 595

मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष।यह तथ्य कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने कागज पर कलम नहीं लगाई, मध्यस्थता समझौते के तहत किसी भी अधिकार या जिम्मेदारियों को ग्रहण नहीं करने के अपने इरादे का एक संकेतक हो सकता है।दूसरी ओर, अदालतें और न्यायाधिकरण उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को बाहर करने के लिए एक कठोर दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं, जो हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ अपने आचरण और संबंधों के माध्यम से, मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध से बाध्य होने का इरादा रखते हैं।मध्यस्थता कानून का क्षेत्र न केवल घरेलू कानून से संबंधित है, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून भी शामिल है, विशेष रूप से जब यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है।इसलिए, इस न्यायालय को मध्यस्थता कानून, अनुबंध कानून और कंपनी कानून के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल किए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणामी कानूनी ढांचा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रथाओं और सिद्धांतों के अनुरूप है।

96. मध्यस्थता समझौते के एक औपचारिक निर्माण से पता चलता है कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के किसी पक्ष के निर्णय का अर्थ यह होना चाहिए कि पक्षों का आपसी इरादा उस पक्ष को मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर करना था।वास्तव में, निगमित संस्थाओं को अपने दायित्व को सीमित करने के लिए अपने व्यवसायों की संरचना करने की वाणिज्यिक और संविदात्मक स्वतंत्रता है।हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ एक निगमित संस्था ने जानबूझकर मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध से बाध्य नहीं होने के लिए एक प्रभाव बनाया है, लेकिन अनुबंध की बातचीत और प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल थी।गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष की भागीदारी का स्तर इस हद तक था कि दूसरे पक्ष को यह विश्वास हो कि वह अनुबंध और उसके तहत निहित मध्यस्थता समझौते के लिए एक वास्तविक पक्ष था।इसलिए, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को संविदात्मक व्यवस्थाओं के आसपास की तथ्यात्मक परिस्थितियों का विश्लेषण करके पक्षों के इरादों का पता लगाने के लिए लागू किया जाता है।87

97. तेजी से, बहुराष्ट्रीय समूह अक्सर निर्माण अनुबंध, रियायत अनुबंध, लाइसेंस समझौते, दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन और समुद्री अनुबंध जैसे जटिल वाणिज्यिक लेनदेन के निष्पादन और वितरण के लिए नई और परिष्कृत कॉर्पोरेट संरचनाओं को अपनाते हैं।इस तरह के अनुबंधों के निष्पादन के लिए, कॉर्पोरेट संरचनाएं इक्विटी, संयुक्त उद्यमों पर आधारित समूहों का रूप ले सकती हैं, और

87 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1568।

अनौपचारिक गठबंधन।88 एक बहु-निगमित संरचना एक समूह को संचालन के व्यावसायिक रूप से प्रभावी मॉडल को अपनाने में मदद करती है क्योंकि अलग-अलग कंपनियां एकल लेनदेन के अलग-अलग चरणों में शामिल हो सकती हैं।अक्सर, ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं, जो मध्यस्थता समझौते वाले

अंतर्निहित अनुबंध के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं, अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन या समाप्ति में शामिल होते हैं।मध्यस्थता कानून के संदर्भ में, चुनौती तब उत्पन्न होती है जब समूह का केवल एक सदस्य अन्य सदस्यों के बहिष्कार के लिए मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करता है।क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता कार्यवाही से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही उन्हें उस विवाद में फंसाया गया हो जो मध्यस्थता का विषय है?इस चुनौती की प्रतिक्रिया के रूप में, मध्यस्थता कानून ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को विकसित और अपनाया है, ताकि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने की अनुमति या मजबूर किया जा सके।

iii.कंपनियों के समूह का सिद्धांत**-**एक तथ्य आधारित सिद्धांत

98. कंपनियों के समूह के सिद्धांत का उपयोग उन कंपनियों के संदर्भ में किया जाता है जो एक ही कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा होने के कारण एक दूसरे से संबंधित हैं।चूँकि समूह की प्रत्येक कंपनी का एक अलग कानूनी व्यक्तित्व होता है, इसलिए समूह के एक सदस्य द्वारा औपचारिक रूप से किया गया अनुबंध सीमित देयता सिद्धांत के आधार पर अन्य सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। कंपनियों के समूह के सिद्धांत का उपयोग एक समूह के भीतर एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी को एक मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए किया जाता है जिस पर समूह के अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।89 कंपनियों के समूह के सिद्धांत का अंतर्निहित आधार मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को बांधने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे को निर्धारित करते हुए समूह की कंपनियों की कॉर्पोरेट अलगाव को बनाए रखने पर आधारित है।दूसरे शब्दों में, कंपनियों के समूह का सिद्धांत अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के कॉर्पोरेट संबंध पर जोर देकर और उनका विश्लेषण करके मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बांधने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे की पहचान करने का एक साधन है।90

88 स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, 'अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पार्टियाँः'द इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन' (2016) 119 में स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, जूलियन डी. एम. ल्यू और अन्य (संस्करण) में सहमति बनाम वाणिज्यिक वास्तविकता,120.

89 UNCITRAL, 'वाणिज्यिक विवादों का समाधानःवाणिज्यिक विवादों के निपटारे से संबंधित कुछ मुद्दों पर संभावित समान नियमःसुलह, संरक्षण के अंतरिम उपाय, मध्यस्थता समझौते का लिखित रूपःमहासचिव की रिपोर्ट 'ए/सी. एन. 9/डब्ल्यू. जी. II/डब्ल्यू. पी. 108/ऐड 1 (26 जनवरी 2000)

90 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1563।

99. कंपनियों के समूह का सिद्धांत मध्यस्थता कानून के व्यवसायियों और क्षेत्र विशेषज्ञता वाले शिक्षाविदों के बीच कठोर शैक्षणिक बहस का विषय रहा है।प्रथम दृष्टिकोण यह सुझाव देकर सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता पर सवाल उठाता है कि जटिल बहु-पक्षीय मध्यस्थता में सहमति का निर्धारण पारंपरिक संविदात्मक और वाणिज्यिक कानून सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है।

प्रोफेसर बर्नार्ड हनोटियाउ सुझाव देते हैं कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग "कानूनी तर्क से बचने के लिए शॉर्टकट" के रूप में किया गया है जिससे अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा विकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।91 हालांकि, प्रोफेसर हनोटियाउ यह स्वीकार करते हैं कि कंपनियों के एक समूह का अस्तित्व यह निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक तथ्यात्मक तत्व हो सकता है कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का आचरण सहमति के बराबर है।100. इसके विपरीत, दूसरा दृष्टिकोण बताता है कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत मध्यस्थता कानून का एक अभिन्न पहलू है।इस दृष्टिकोण के अनुसार, गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष बनाने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे को निर्धारित करने के लिए कॉर्पोरेट संरचना के विशिष्ट सी पैटर्न का अस्तित्व एक उपयोगी तथ्यात्मक संकेतक हो सकता है।92 उदाहरण के लिए, समूह की अन्य हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों द्वारा संचालित एक वाणिज्यिक परियोजना की सुविधा और प्रदर्शन में एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता समूह कंपनी की सक्रिय भागीदारी को एक संकेत के रूप में माना जा सकता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष भी मध्यस्थता के लिए सहमत था।इसके अलावा, गैरी बॉर्न यह भी सुझाव देते हैं कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत सहायक है क्योंकि यह अदालतों को अनुबंध के निष्पादन से पहले, उसके दौरान और बाद में अपने गतिशील व्यक्तिपरक इरादों को निर्धारित करने के लिए पक्षों के वस्तुनिष्ठ इरादों से परे जाने की अनुमति देता है।93 बोर्न के अनुसार, यह सिद्धांत एक समूह के भीतर गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों द्वारा उपग्रह मुकदमेबाजी के माध्यम से मध्यस्थता के उल्लंघन को प्रतिबंधित करके मध्यस्थता समझौतों के प्रभाव को भी बढ़ावा देता है।हम अनुसरण किए जाने वाले कारणों के लिए इस दृष्टिकोण से व्यापक रूप से सहमत हैं।

101. कंपनियों के समूह का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा विशेष रूप से मध्यस्थता के संदर्भ में विकसित किया गया था, और आम तौर पर नहीं है

91 हनोटियाउ (एन 85) 546।

92 स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, 'अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पार्टियाँः'द इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन' (2016) 119 में स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, जूलियन डी. एम. ल्यू और अन्य (संस्करण) में सहमति बनाम वाणिज्यिक वास्तविकता137.

93 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1568।

कानून के अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।94 हालाँकि कंपनियों के समूह का अस्तित्व एक आवश्यक शर्त है, लेकिन पक्षों के इरादे को निर्धारित करने के लिए यह पर्याप्त शर्त नहीं है।लगभग सभी सूत्रीकरणों में, अदालतों और न्यायाधिकरणों ने आगाह किया है कि कंपनियों के एक समूह में एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की मात्र सदस्यता इसे मध्यस्थता समझौते से बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। बल्कि, अदालतों को यह निर्धारित करने की आवश्यकता हैःपहला, कंपनियों के एक समूह का अस्तित्व; और दूसरा, हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का आचरण जो गैर-हस्ताक्षरकर्ता

को मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष बनाने के उनके सामान्य इरादे का संकेत देता है।95 इस प्रकार, कंपनियों के समूह का सिद्धांत अन्य सहमति आधारित सिद्धांतों जैसे एजेंसी, असाइनमेंट, धारणा और गारंटी के समान है, इस हद तक कि इसे आम तौर पर मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बांधने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे की पहचान करने के साधन के रूप में लागू किया जाता है।

102. उपरोक्त स्थिति को डाउ केमिकल्स (उपरोक्त) में आई. सी. सी. ट्रिब्यूनल द्वारा स्पष्ट रूप से अपनाया गया था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक कॉर्पोरेट समूह की कुछ कंपनियों द्वारा हस्ताक्षरित एक मध्यस्थता समझौता अन्य गैर-हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों को केवल वहीं बाध्य करेगा जहां सभी पक्ष गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को "अनुबंधों के निष्कर्ष, प्रदर्शन या समाप्ति" में उनकी भागीदारी के आधार पर मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध के "वास्तविक पक्ष" होने का इरादा रखते हैं और समझते हैं।इस प्रकार, कंपनियों के एक समूह का अस्तित्व एक तथ्यात्मक तत्व है जिस पर अदालत या न्यायाधिकरण को पक्षों की सहमति का विश्लेषण करते समय विचार करना पड़ता है।यह अनिवार्य रूप से एक अभ्यास में मानदंडों की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है जो इसके मूल में कई पक्षों और समझौतों से जुड़े जटिल लेनदेन के मामले में पक्षों की सहमति निर्धारित करने में प्रमुख है।

103. क्लोरो कंट्रोल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने ठीक ही कहा कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है बशर्ते कि अंतर्निहित लेनदेन कंपनियों के एक समूह के साथ हों और पक्षकारों का स्पष्ट इरादा हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने का हो।केनरा बैंक (ऊपर) और डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (ऊपर) सहित इस न्यायालय के बाद के निर्णयों की एक श्रृंखला में इस कानूनी प्रस्ताव को दोहराया गया है।इसके अलावा, चेरन संपत्तियों में यह न्यायालय

94 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1559। 95 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1562।

(उपर्युक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की स्तरित संरचना को समझने में मदद करता है ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को बांधने के लिए पक्षों के सच्चे इरादे को उजागर किया जा सके जो औपचारिक रूप से अनुबंध के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन एक हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व "ग्रहण" किया है।इस अदालत ने हित में "सच्चे" पक्ष को समझने के लिए सिद्धांत के उद्देश्य को समझाया:

“25. […] कंपनियों के समूह के सिद्धांत को ब्याज में "सच्चे" पक्ष का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने के लिए लागू किया गया है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, कंपनियों के समूह के क्रेडिट योग्य सदस्य को लक्षित करने के लिए।इस सिद्धांत के विस्तार के माध्यम से कॉर्पोरेट व्यक्तित्व के कानूनी आरोप के आधार पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, सिद्धांत का

अनुप्रयोग मध्यस्थता समझौते के निर्माण और अंतर्निहित अनुबंध में प्रवेश और प्रदर्शन से संबंधित परिस्थितियों को बदल देता है।"

104. कॉक्स एंड किंग्स (ऊपर) में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या अहंकार को बदलने या कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने के सिद्धांत ही निहित सहमति के अभाव में भी कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग को उचित ठहरा सकते हैं।चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत और घूंघट छेदने या अहंकार को बदलने के सिद्धांत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।अहं परिवर्तन का सिद्धांत समता और सद्भावना के प्रमुख विचारों को ध्यान में रखते हुए निगमित अलगाव और पक्षों के इरादों की अवहेलना करता है।इसके विपरीत, कंपनियों के समूह का सिद्धांत विचाराधीन इकाई के कानूनी व्यक्तित्व को परेशान किए बिना मध्यस्थता समझौते के सच्चे पक्षों को निर्धारित करने के लिए पक्षों के इरादे की पहचान की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए, अहंकार को बदलने या कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने का सिद्धांत कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग का आधार नहीं हो सकता है।

iv.आपसी इरादे का निर्धारण

105. बहु-पक्षीय समझौतों में, अदालतों या न्यायाधिकरणों को यह निर्धारित करने के लिए कॉर्पोरेट संरचना की जांच करनी होगी कि क्या हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्ष एक ही समूह से संबंधित हैं।यह मूल्यांकन तथ्य विशिष्ट ग है और इसे कंपनी कानून के उपयुक्त सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए।एक बार निगमित समूह का अस्तित्व स्थापित हो जाने के बाद, अगला कदम यह निर्धारित करना है कि क्या सभी पक्षों का मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले को बांधने का आपसी इरादा था।

689

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 690

106. कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुसार अदालतों और न्यायाधिकरणों को मध्यस्थता करने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे को प्रदर्शित करने के लिए वाणिज्यिक परिस्थितियों और पक्षों के आचरण पर विचार करने की आवश्यकता होती है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत केवल मध्यस्थता समझौते के पक्षों से संबंधित है न कि अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से।96 नतीजतन, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को अंतर्निहित अनुबंध का औपचारिक पक्ष बने बिना मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष माना जा सकता है।समूह कंपनियों का अस्तित्व यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारकों में से एक है कि क्या आचरण सहमति के बराबर है, लेकिन किसी समूह की सदस्यता अपने आप में पर्याप्त नहीं है।डाउ केमिकल्स (उपरोक्त) पुरस्कार से शुरू होकर यह कानून की सुसंगत स्थिति रही है, जहां यह देखा गया था कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता के लिए बाध्य करने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे का अनुमान उन परिस्थितियों से लगाया जा सकता है जो निष्कर्ष को घेरती हैं और प्रदर्शन और बाद में अनुबंधों की समाप्ति को दर्शाती हैं।" दूसरे शब्दों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता

पक्ष को मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध के निष्कर्ष, प्रदर्शन या समाप्ति में उनकी भूमिका के आधार पर मध्यस्थता समझौते के लिए एक "सच्चे पक्ष" के रूप में माना जा सकता है।

107. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस न्यायालय ने चार तथ्यात्मक सूचकांक निर्धारित किए कि अदालतों या न्यायाधिकरणों को एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने पर विचार करना चाहिए।प्रासंगिक अनुच्छेदों को पूरी तरह से निकालना महत्वपूर्ण है:

"72. यह इस सिद्धांत को विकसित करता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है बशर्ते कि ये लेनदेन कंपनियों के समूह के साथ हों और दोनों पक्षों, हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बाध्य करने का एक स्पष्ट इरादा हो।दूसरे शब्दों में, "का इरादा

पक्षकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे मध्यस्थता के दायरे में हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को शामिल करने से पहले स्थापित किया जाना चाहिए।"

73. एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता या तीसरे पक्ष को उनकी पूर्व सहमति के बिना मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है, लेकिन यह केवल असाधारण मामलों में ही होगा।न्यायालय मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ प्रत्यक्ष संबंध की कसौटी से इन अपवादों की जांच करेगा।

विषय-वस्तु की प्रत्यक्ष समानता और पक्षों के बीच समझौता एक समग्र लेनदेन है।लेन-देन एक मिश्रित प्रकृति का होना चाहिए जहां सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने और सामूहिक रूप से विवाद पर असर डालने के लिए पूरक या सहायक समझौतों की सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना मातृ समझौते का प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है।इन सबके अलावा, अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ऐसे पक्षों का समग्र संदर्भ न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।एक बार जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है और अदालत उसी का जवाब प्रत्यावेदन में देती है, तो गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का संदर्भ भी पूर्व-चर्चा किए गए अपवाद के भीतर आएगा।" (जोर दिया गया) 108।कॉक्स एंड किंग्स (ऊपर) में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) के उपरोक्त निकाले गए पैराग्राफ 72 और 73 के संदर्भ में एक विरोधाभास का अवलोकन किया।न्यायमूर्ति सूर्यकांत के अनुसार, एक ओर, क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) "पक्षों के इरादे" पर जोर देता है, जबकि दूसरी ओर यह गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को "उनकी पूर्व सहमति के बिना" मध्यस्थता कार्यवाही की अनुमति देता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उपरोक्त दो अनुच्छेदों में टिप्पणियों में इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए वास्तव में सही कहा है।पैरा 72 आपसी इरादे को रेखांकित करता है जबकि पैरा 73 पूर्व सहमति के अभाव का सुझाव देकर इससे दूर जाता प्रतीत होता है।हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि "उनकी पूर्व

सहमति के बिना" वाक्यांश का अर्थ "मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध के लिए पूर्व औपचारिक सहमति के बिना" के रूप में लगाया जाना चाहिए।" उपरोक्त दो पैराग्राफ को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पैराग्राफ 72 एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए "पक्षों के इरादे" को निर्धारित करने पर जोर देता है।पैराग्राफ 73 में, न्यायालय एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष में शामिल होने के लिए परीक्षणों से संबंधित है जिसने औपचारिक रूप से मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति नहीं दी है।इसके अलावा, उक्त अनुच्छेद मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों में शामिल होने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को समझने के लिए संचयी कारकों को सूचीबद्ध करता है।उपरोक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि इस तरह से क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) के पैराग्राफ 72 और 73 के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।109. हमारे सामने उठाए गए तर्कों में से एक क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) के पैराग्राफ 73 में टिप्पणियों से संबंधित है कि सभी पक्षों के समग्र संदर्भ को "न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति" करनी चाहिए।

691

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 692

यह तर्क दिया गया था कि इक्विटी क्षेत्राधिकार आम तौर पर मध्यस्थता समझौतों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे निजी कानून के दायरे में होते हैं।चूंकि मध्यस्थता सहमति का मामला है, इसलिए न्याय और समानता के हित मध्यस्थता समझौते को लागू करने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं।कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए प्राथमिक परीक्षण अंतर्निहित तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर पक्षों के इरादे का निर्धारण करना है।कंपनियों के समूह के सिद्धांत का अनुप्रयोग कॉर्पोरेट समूह के गैर-हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों द्वारा उपग्रह मुकदमेबाजी को रोकने का काम करेगा, जिससे पक्षों के बीच समझौते की प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।कार्यवाही की बहुलता और विवादों के विखंडन से बचना निश्चित रूप से न्याय के हित में है।हालाँकि, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करना कभी भी एकमात्र विचार नहीं हो सकता है।

110. डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उन संचयी कारकों को संशोधित और स्पष्ट किया जिन पर अदालतों और न्यायाधिकरणों को यह तय करने में विचार करना चाहिए कि क्या कंपनियों के समूह के भीतर एक कंपनी मध्यस्थता समझौते से बाध्य है:

"40. यह तय करने में कि क्या कंपनियों के समूह के भीतर एक कंपनी जो मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी इसके द्वारा बाध्य होगी, कानून निम्नलिखित कारकों पर विचार करता है:

((i) पक्षकारों का आपसी इरादा;

((ii) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध;

((ग) विषय-वस्तु की समानता;

((iv) लेन-देन की समग्र प्रकृति और (v) अनुबंध का निष्पादन।"

111. चूँकि कंपनियों के समूह का सिद्धांत एक सहमति आधारित सिद्धांत है, इसका अनुप्रयोग इसमें शामिल सभी पक्षों के आपसी इरादे को स्थापित करने के लिए विभिन्न तथ्यात्मक तत्वों के विचार पर निर्भर करता है।दूसरे शब्दों में, कंपनियों के समूह का सिद्धांत मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों के आपसी इरादों का अनुमान लगाने का एक साधन है।निगमित समूह संरचना के भीतर कानूनी संस्थाओं के बीच और उनके बीच संबंध और अंतर्निहित संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन में पक्षों की भागीदारी इसके लिए संकेतक हैं -

पक्षों के आपसी इरादों को निर्धारित करें।अन्य कारक जैसे विषय वस्तु की समानता, लेन-देन की समग्र प्रकृति और अनुबंध के प्रदर्शन पर अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा संचयी रूप से विचार और विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को बांधने के लिए पक्षों के इरादे की पहचान की जा सके।गैर-हस्ताक्षरकर्ता के सहयोगी की मांग करने वाले पक्ष को उपरोक्त कारकों को अदालत या न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए संतुष्ट करने के प्रमाण का भार वहन करना पड़ता है, जैसा भी मामला हो।112. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 मोटे तौर पर कानूनी संबंधों के संबंध में पक्षों द्वारा एक समझौते के बारे में बात करती है, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं।इस तरह के कानूनी संबंधों को कानूनी दायित्वों और कर्तव्यों को जन्म देना चाहिए।एक निगमित समूह में, एक कंपनी में विभिन्न संबंधित कंपनियां हो सकती हैं।कानूनी संबंधों का विश्लेषण मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध के संदर्भ में किया जाना चाहिए।संविदात्मक संबंध की प्रकृति को या तो औपचारिक रूप से अंतर्निहित अनुबंध में निहित किया जा सकता है, या इस तरह के अनुबंध के संबंध में हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के आचरण से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है।हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच केवल एक वाणिज्यिक संबंध की उपस्थिति पक्षों के बीच और उनके बीच "कानूनी संबंध" का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।यदि यह कारक पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो किसी भी संबंधित इकाई या कंपनी को तब भी शामिल किया जा सकता है जब उसके पास अंतर्निहित अनुबंध के तहत कोई अधिकार या दायित्व नहीं हैं और उसने अनुबंध के प्रदर्शन में भाग नहीं लिया है।कंपनी समूह के सिद्धांत को पार्टी की सहमति और स्वायत्तता को निरस्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।उचित रूप से परिकल्पित और लागू किया गया सिद्धांत आपसी इरादे और स्वायत्तता को प्रभावी बनाता है।

113. केनरा बैंक (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है जहां "मजबूत संगठनात्मक और वित्तीय संबंधों के साथ एक तंग समूह संरचना, ताकि एक एकल आर्थिक इकाई, या एक एकल आर्थिक वास्तविकता का गठन किया जा सके।" कॉक्स एंड किंग्स (उपरोक्त) मामले में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि इस दृष्टिकोण को लागू करने में निगमित अलगाव के सिद्धांत की अनदेखी करने और पक्षों की सहमति से

इसे समाप्त करने की प्रवृत्ति है।न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा व्यक्त की गई सावधानी में महत्व है।एक पक्ष और एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के बीच वाणिज्यिक संबंधों की उपस्थिति मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बांधने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने से सभी गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक कॉर्पोरेट समूह के भीतर बाध्य होंगे, भले ही वे 693 नहीं हैं।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 694

विचाराधीन संविदात्मक दायित्वों से संबंधित, मध्यस्थता समझौते से संबंधित।नतीजतन, इस तरह के दृष्टिकोण से मध्यस्थता के मूल कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन होगा-एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए सहमति की आवश्यकता, या तो व्यक्त या निहित,।इसके अलावा, समूह के अन्य सदस्यों के कृत्यों के लिए समूह के भीतर एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी पर केवल इस तथ्य के आधार पर दायित्व अधिरोपित करना कि वे एक "एकल आर्थिक इकाई" से संबंधित हैं, विशिष्ट निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत पर भारी पड़ेगा।कंपनियों के समूह के सिद्धांत का उद्देश्य संस्थाओं के कानूनी व्यक्तित्व की अवहेलना किए बिना पक्षों के आपसी इरादों की पहचान करना है।

114. डाउ केमिकल्स (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कंपनियों का एक समूह एक ही आर्थिक वास्तविकता का गठन करता है, जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए।न्यायाधिकरण के अनुसार, कंपनियों के समूह की उपस्थिति केवल एक अतिरिक्त कारक है जिस पर न्यायाधिकरण पक्षों के आपसी इरादे को निर्धारित करने के लिए विचार कर सकता है।केनरा बैंक (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को केवल इस आधार पर लागू नहीं किया कि कंपनियां एक ही आर्थिक इकाई से संबंधित थीं।बल्कि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल किए जाने के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष (सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए.) द्वारा एक निहित या मौन सहमति थी। हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच मजबूत संगठनात्मक संबंधों और वित्तीय संबंधों की उपस्थिति केवल उन तथ्यात्मक तत्वों में से एक है जिन पर अदालत या न्यायाधिकरण हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच कानूनी संबंध निर्धारित करने के लिए विचार कर सकता है।हम तदनुसार स्पष्ट करते हैं कि "एकल आर्थिक इकाई" के सिद्धांत का उपयोग कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए एकमात्र आधार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

115. कई पक्षों के मामले में, एक सामान्य विषय-वस्तु और समग्र लेन-देन की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक संकेतक है।एक मध्यस्थता समझौता किसी विशेष विषय के संबंध में पक्षों के बीच एक अवज्ञापूर्ण कानूनी संबंध से उत्पन्न होता है।विषय वस्तु की समानता इंगित करती है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का आचरण मध्यस्थता समझौते के विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मध्यस्थता समझौते में अंतर्निहित अनुबंध की विषय वस्तु स्वास्थ्य देखभाल वस्तुओं के वितरण से संबंधित है, तो गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का आचरण भी संबंधित होना चाहिए या इसके अनुसरण में होना चाहिए

संविदात्मक कर्तव्य और दायित्व, जो स्वास्थ्य देखभाल वस्तुओं के वितरण से संबंधित हैं।इस कारक का निर्धारण यह प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष विशेष विषय वस्तु के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए सहमत था।

116. कई समझौतों से जुड़े समग्र लेन-देन के मामले में, अदालतों और न्यायाधिकरणों के लिए यह आकलन करना अनिवार्य होगा कि क्या समझौते परिणामी हैं या मुख्य समझौते के अनुवर्ती प्रकृति के हैं।केनरा बैंक (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा कि एक समग्र लेनदेन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां लेनदेन प्रकृति में परस्पर जुड़ा हुआ है या जहां पूरक या सहायक समझौतों की सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना प्रमुख समझौते का प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है।

117. कानून की सामान्य स्थिति यह है कि पक्षों को मुख्य समझौते के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा यदि ऐसी स्थिति है जहां मुख्य समझौते के संबंध में विवाद और मतभेद हैं और मुख्य समझौते के विषय-वस्तु से जुड़े विवाद भी हैं।97 क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "समग्र प्रदर्शन" के सिद्धांत को एक ओर प्रमुख और पूरक समझौतों के संयुक्त पठन से और दूसरी ओर पक्षों और परिचर परिस्थितियों के स्पष्ट इरादे से एकत्र करना होगा।एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों द्वारा वाणिज्यिक परियोजना में आम भागीदारी इस तथ्य का एक संकेतक हो सकता है कि सभी पक्षों का इरादा गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता समझौते से बाध्य होना था।इस प्रकार, समग्र लेन-देन के मामले में कंपनियों के समूह के सिद्धांत का अनुप्रयोग उन सभी पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है जिन्होंने बातचीत और लेन-देन के प्रदर्शन में भौतिक रूप से भाग लिया है और ऐसा करने से मध्यस्थता के समझौते से बाध्य होने का आपसी इरादा सामने आया है।

118. अंतर्निहित अनुबंध के निष्पादन में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा विचार किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है।गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का आचरण गैर-हस्ताक्षरकर्ता के मध्यस्थता समझौते से बंधे होने के इरादे का एक संकेतक है।पक्षकारों का एक मध्यस्थता समझौते से बंधे होने का इरादा हो सकता है

97 ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम मीना विजय खेतान, (1999) 5 एससीसी 651 695

उन परिस्थितियों से मापा जाए जो इस तरह के समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन और समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष की भागीदारी को घेरती हैं।अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंध का यू. एन. आई. डी. आर. ओ. आई. टी. सिद्धांत, 2016-98 प्रदान करता है कि

निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षों के व्यक्तिपरक इरादे का पता लगाया जा सकता हैः

(क) पक्षकारों के बीच प्रारंभिक वार्ता;

(बी) प्रथाएं जो पार्टियों ने अपने बीच स्थापित की हैं; (सी) अनुबंध के समापन के बाद पार्टियों का आचरण;

((घ) अनुबंध की प्रकृति और उद्देश्य;

(ई) संबंधित व्यापार में शब्दों और अभिव्यक्तियों को आम तौर पर दिया गया अर्थ; और

(च) उपयोग।

119. डाउ केमिकल्स (उपरोक्त) में, मध्यस्थता के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों की सहमति मुख्य रूप से अनुबंधों के निष्कर्ष, प्रदर्शन और समाप्ति में उनकी प्रमुख भागीदारी को देखते हुए निहित थी।इसी तरह, केनरा बैंक (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कहा कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकती है जहां कंपनियों के समूह का एक अभिभावक या सदस्य मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है और समूह की गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई वाणिज्यिक अनुबंध की बातचीत या प्रदर्शन में लगी हुई है।

120. रेकिट बेंकिजर (ऊपर) में, इस न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई के एक कथित प्रवर्तक का प्रतिनिधित्व इसे उक्त प्रतिनिधित्व से बाध्य करेगा।उस मामले में, आवेदक ने पैकिंग सामग्री की आपूर्ति के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ एक समझौता किया।बातचीत के चरण के दौरान, आवेदक ने भारतीय कंपनी के साथ ईमेल द्वारा समझौते का एक मसौदा वितरित किया।इस ईमेल को श्री फ्रेडरिक रेंडर्स द्वारा वापस किया गया था, जिसके बारे में आवेदक ने दावा किया था कि वह भारतीय कंपनी की बेल्जियम की एक सहयोगी कंपनी का प्रवर्तक था।बेल्जियन

98 UNIDROIT अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों के सिद्धांत, 2016, अनुच्छेद 4.3

कंपनी समझौते की गैर-हस्ताक्षरकर्ता थी।फिर भी, आवेदक ने बेल्जियम की कंपनी को इस आधार पर शामिल करने की मांग की कि उसने समझौते के निष्पादन से पहले बातचीत के दौरान भाग लिया था।इस न्यायालय ने बेल्जियम कंपनी के जॉइंडर को इस आधार पर मध्यस्थता समझौते की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि श्री रेयंडर्स बेल्जियम कंपनी के प्रवर्तक नहीं थे, और इसलिए कंपनी की ओर से या उसकी ओर से उस क्षमता में कार्य नहीं कर रहे थे और आवेदक यह साबित करने के लिए अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा कि बेल्जियम कंपनी ने मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति दी थी।

121. किसी अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन या समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष की भागीदारी का मूल्यांकन करना कई कारणों से एक महत्वपूर्ण कारक है।पहला, किसी अनुबंध के निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल होने से, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता यह आभास कर सकता है कि वह मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध का एक वास्तविक पक्ष है; दूसरा, गैर-हस्ताक्षरकर्ता का आचरण समूह के अन्य सदस्यों के आचरण के अनुरूप हो सकता है, जिससे दूसरे पक्ष को वैध रूप से विश्वास हो सकता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता अनुबंध का एक वास्तविक पक्ष था; और तीसरा, दूसरे पक्ष के पास गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष द्वारा बनाई गई उपस्थिति पर भरोसा करने के वैध कारण हैं ताकि उसे मध्यस्थता समझौते से जोड़ा जा सके।

v. सीमा मानक

122. कॉक्स एंड किंग्स (ऊपर) मामले में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि रेकिट बेंकिजर (ऊपर) ने इस न्यायालय के पहले के फैसलों की तुलना में कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए साक्ष्य की उच्च सीमा निर्धारित की है।इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि रेकिट बेंकिजर (ऊपर दिया गया) इस तथ्य का संकेत है कि कंपनियों के एक समूह की मात्र उपस्थिति एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए एकमात्र या निर्धारक कारक नहीं है। बल्कि, अदालतों या न्यायाधिकरणों को अनुबंध के प्रदर्शन में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के समग्र आचरण और भागीदारी का बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिए।अनुबंध के निष्पादन में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी की प्रकृति या मानक ऐसा होना चाहिए कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने अनुबंध के तहत सक्रिय रूप से दायित्वों या प्रदर्शन को ग्रहण कर लिया हो।दूसरे शब्दों में, परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता की बातचीत, प्रदर्शन या अनुबंध की समाप्ति में सकारात्मक, प्रत्यक्ष और पर्याप्त भागीदारी है।अनुबंध की बातचीत या प्रदर्शन में केवल आकस्मिक भागीदारी अंतर्निहित अनुबंध या इसके मध्यस्थता द्वारा बाध्य होने के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता की सहमति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

समझौता।उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी के एक सचेत और जानबूझकर आचरण को साबित करने के लिए मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता के सहयोगी की मांग करने वाले पक्ष पर बोझ है।

123. एक मध्यस्थता समझौता मूल वाणिज्यिक अनुबंध से एक अलग और अलग समझौता है जिसमें मध्यस्थता समझौता शामिल है।एक मध्यस्थता समझौता अनुबंध की अन्य शर्तों से इस हद तक स्वतंत्र है कि अनुबंध के रद्द होने से मध्यस्थता समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकेगा।99 मध्यस्थता समझौते को अंतर्निहित अनुबंध से अलग करने की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने का पक्षों का इरादा केवल अंतर्निहित अनुबंध की कानूनी वैधता को चुनौती देने के कारण गायब नहीं होता है।100 मध्यस्थता के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता में शामिल होने के लिए, निर्णायक प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि

क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति दी है, जो मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध से अलग है।101

124. स्टावरोस ब्रेकोलाकिस का तर्क है कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत जैसे कानूनी सिद्धांतों का अनुप्रयोग इस धारणा पर आधारित है कि एक मध्यस्थता समझौते के लिए मध्यस्थता समझौते वाले अंतर्निहित अनुबंध की तुलना में "कम सहमति" या "सहमति के कम सबूत" की आवश्यकता होती है।102 ब्रेकोलाकिस ने आगे कहा कि यह धारणा कि अंतर्निहित अनुबंध के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की सहमति निहित है, इस तरह के अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति का गठन करने के लिए पर्याप्त है, अनुबंधों को अलग करने के सिद्धांत के खिलाफ है।103

125. बातचीत, प्रदर्शन या अनुबंध की समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी अनुबंध द्वारा बाध्य होने की निहित सहमति को जन्म दे सकती है।ब्रेकोलाकिस ठीक ही एक विसंगत स्थिति की ओर इशारा करते हैं जहाँ कंपनियों के समूह जैसे कानूनी सिद्धांत सहमति को मुख्य प्रश्न का निर्धारण किए बिना एक कार्यात्मक कानूनी निर्माण के रूप में मानते हैं -

99 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2014) 7 एससीसी 603 100 एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1

101 गैरी का जन्म (संख्या 44) 1545।

102 स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में सहमति पर पुनर्विचार:गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए एक सामान्य सिद्धांत (2017) 8 जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट 610,621.

103 स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, 'अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पार्टियाँ:'द इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन' (2016) 119 में स्टावरोस ब्रेकोलाकिस, जूलियन डी. एम. ल्यू और अन्य (संस्करण) में सहमति बनाम वाणिज्यिक वास्तविकता148.

क्या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास विवादों को हल करने के लिए पक्षों (और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों) पर अधिकार क्षेत्र है?104

126. अंतर्निहित अनुबंध की बातचीत, प्रदर्शन या समाप्ति में एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है कि इस तरह के गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने अनुबंध द्वारा बाध्य होने को स्वीकार किया है।हालांकि, इस तरह की सहमति का मध्यस्थता समझौते में स्थानांतरण वाणिज्यिक वास्तविकता को समायोजित करने के लिए एक कानूनी निर्णय है। समकालीन वाणिज्यिक वास्तविकता से पता चलता है कि एक समूह के भीतर अलग-अलग कंपनियां अक्सर संविदात्मक लेनदेन के निष्पादन और प्रदर्शन के अलग-अलग चरणों में शामिल हो जाती हैं।उदाहरण के लिए, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता केवल एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने या मूल कंपनी की सहायता करने के लिए एक अनुबंध के प्रदर्शन में भाग ले सकता है।संविदात्मक निष्पादन में इस तरह की आकस्मिक भागीदारी अंतर्निहित अनुबंध के लिए सहमति का गठन करने के लिए

अनुचित है, मध्यस्थता समझौते की तो बात ही छोड़िए।बल्कि, यह सुझाव दिया गया है कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या वाणिज्यिक विवाद पर्याप्त रूप से गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए निहित करता है।105 हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच विवाद के विषय वस्तु के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के दायरे पर जोर देने से प्रभावी मध्यस्थता सुनिश्चित होगी और विवादों के अनावश्यक विखंडन को रोका जा सकेगा।यह तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके मध्यस्थता समझौते (और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन जैसे आगामी प्रक्रियात्मक पहलुओं) के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता की ओर से औपचारिक सहमति की कमी के लिए भी पर्याप्त रूप से जिम्मेदार है, जैसे कि घनिष्ठ संबंध और समग्र लेनदेन, जो इंगित करता है कि मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों के रूप में गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मानने के लिए सभी पक्षों के बीच आपसी समझ या अभिसरण था।106

127.हमारी राय है कि मध्यस्थता की सहमति की प्रकृति और आधुनिक वाणिज्यिक वास्तविकता के बीच एक संतुलन की तलाश करने की आवश्यकता है, जहां एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कई अलग-अलग तरीकों से वाणिज्यिक लेनदेन में फंस जाता है।यदि डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) के तहत निर्धारित कारकों को लागू किया जाए तो इस तरह का संतुलन पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

104 इबिद, 121 पर।

105 ब्रेकोलाकिस (एन 102) 629।

106 करीम यूसुफ, 'सहमति की सीमाएँःबहुपक्षीय मध्यस्थता में कंपनियों के समूह में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के मध्यस्थता का अधिकार या दायित्वःआई. सी. सी. विश्व व्यापार कानून संस्थान के दस्तावेज़, खंड 7 (2010) 71,79.

समग्र रूप से।उदाहरण के लिए, अंतर्निहित अनुबंध के प्रदर्शन में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी इस तरह से है जो बताती है कि यह मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध से बाध्य होने का इरादा रखता है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।लेन-देन की समग्र प्रकृति और विषय वस्तु की समानता जैसे अन्य कारकों से पता चलता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ दावे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के विषय वस्तु के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए थे।कारकों को समग्र रूप से देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ अपने संबंधों और वाणिज्यिक दायित्वों के प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी के आधार पर, जो विषय वस्तु से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं, वास्तव में हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच विवाद के लिए अजनबी नहीं हैं।

128. हमारा मानना है कि कंपनी सिद्धांत के समूह की प्रयोज्यता का निर्धारण करते समय डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में निर्धारित सभी संचयी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, उपरोक्त कारकों का अनुप्रयोग तथ्य-विनिर्दिष्ट होना चाहिए और यह न्यायालय उपरोक्त कारकों को कितना महत्व देना चाहिए, यह निर्धारित करके अदालतों या न्यायाधिकरणों के हाथों को बांध नहीं सकता है।यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सहमति के लिए एक आधुनिक

दृष्टिकोण के पक्ष में व्यक्त सहमति पर एक हठधर्मी जोर दिया जाए जो तथ्यात्मक विश्लेषण, वाणिज्यिक परियोजनाओं की जटिलता पर केंद्रित है और इस तरह बहु-पक्षीय विवादों में मध्यस्थता की प्रासंगिकता को बढ़ाता है।इसके अलावा, यह मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप भी है जिसका उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता कानून को समकालीन आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना है।

एफ. कंपनियों के समूह के सिद्धांत का स्वतंत्र अस्तित्व है

129. कॉक्स एंड किंग्स (ऊपर) में, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर), और बाद के निर्णयों की श्रृंखला ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 45 के तहत आने वाले वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा" के दायरे और दायरे को उचित रूप से नहीं देखा है। संबंधित रूप से, इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों में से एक यह है कि क्या "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने" वाक्यांश की व्याख्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को शामिल करने के लिए की जा सकती है।

130. मध्यस्थता अधिनियम किसी पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति वाक्यांश की अवहेलना नहीं करता है।एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत "दावा करने वाला" व्यक्ति अनुबंध या समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत अधिकार का दावा कर सकता है।मध्यस्थता पर रसेल का कहना है कि एक असाइनी कर सकता है

मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति के रूप में मध्यस्थता समझौते का आह्वान करें।107 एक समनुदेशिती मध्यस्थता खंड के लाभ और बोझ दोनों के साथ एक अनुबंध के तहत सौंपा गया अधिकार लेता है।108 इसी तरह, अंग्रेजी अदालतों ने माना है कि एक अंतरिती या अधीनस्थ मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा कर सकता है।109 अंग्रेजी कानून के तहत, विशिष्ट परिदृश्य जहां कोई व्यक्ति या संस्था किसी पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा कर सकती है, वे हैं असाइनमेंट, सब्रोगेशन और नोवेशन।इन स्थितियों में, समनुदेशक या प्रतिनिधि मध्यस्थता समझौते के तहत हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के हितों के उत्तराधिकारी बन जाते हैं।वे हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के स्थान पर कदम रखते हैं, जिनसे वे मध्यस्थता समझौते के तहत एक स्वतंत्र अधिकार का दावा करने के बजाय मध्यस्थता करने का अधिकार प्राप्त करते हैं।131. अंग्रेजी कानून के तहत एक मध्यस्थता समझौते का दायरा उन पक्षों तक सीमित है जो इसमें प्रवेश करते हैं और जो उनके माध्यम से या उनके तहत दावा करते हैं।110 रूसेल-उक्क्राफ (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सहायक कंपनी इस आधार पर मध्यस्थता समझौते को लागू कर सकती है कि वह दोनों कंपनियों के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण मूल कंपनी के माध्यम से या उसके तहत "दावा" कर रही है।हालांकि, रूसेल-उक्क्राफ (ऊपर) को

संचेती (ऊपर) में अपील न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था कि किसी व्यक्ति के लिए मध्यस्थता समझौते के माध्यम से या उसके तहत दावा करने के लिए केवल कानूनी या वाणिज्यिक संबंध पर्याप्त नहीं है।

132. "के माध्यम से या उसके तहत दावा" वाक्यांश के दायरे का मूल्यांकन अन्य सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों द्वारा किया गया है।टैनिंग रिसर्च लैबोरेटरीज इंक बनाम ओ 'ब्रायन, 111 में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या परिसमापक को मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है।उच्च न्यायालय ने "के माध्यम से" या "के तहत" शब्दों का अर्थ यह ठहराने के लिए लगाया कि परिसमापक का कंपनी के माध्यम से व्युत्पन्न हित था।प्रासंगिक अवलोकन नीचे निकाला गया है:

107 मध्यस्थता पर रसेल (23 वां संस्करण, 2007) 99 पैरा 3-018।

108 शिफ अहट्र्स-गेसेलशाफ्ट डेटलेव वॉन एप्पेन बनाम वोएस्ट अल्पाइन इंटरट्रेडिंग, [1997] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1420।

109 ट्रांसपोर्ट म्यूचुअल इंश्योरेंस एसोसिएशन **(**यूरेशिया**)** लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड**, [2005]** ई**.** डब्ल्यू**.** एच**.** सी**. 455 (**कॉम**);** वेस्ट टैंकर इंक**.** बनाम।एलियांज स्पा**, [2012]** ई**.** डब्ल्यू**.** सी**.** ए**.** सिविल **27**।

110 अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 82 (2) 111 [1990] एच. सी. ए. 8 701

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 702

“[टी] वह पूर्वसर्ग "के माध्यम से" या "के तहत" कार्रवाई के व्युत्पन्न कारण या रक्षा के आधार की धारणा को व्यक्त करते हैं, अर्थात, कार्रवाई का कारण या पक्ष से प्राप्त रक्षा का आधार।दूसरे शब्दों में, कार्रवाई या बचाव के कारण का एक आवश्यक तत्व पक्ष द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य होना चाहिए, इससे पहले कि पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला व्यक्ति कार्रवाई के कारण या बचाव के आधार पर भरोसा कर सके।परिसमापक एक व्यक्ति हो सकता है जो किसी कंपनी के माध्यम से या उसके तहत दावा करता है क्योंकि कार्रवाई के कारण या बचाव के आधार जिन पर वह निर्भर है, वे कंपनी में निहित हैं या कंपनी द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं; दिवालियापन में एक न्यासी ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्योंकि कार्रवाई के कारण या बचाव के आधार जिन पर वह निर्भर है, दिवालिया द्वारा निहित या प्रयोग किए जा सकते थे।”

व्युत्पन्न कार्रवाई का परीक्षण बताता है कि तीसरे पक्ष की कार्रवाई का कारण मध्यस्थता समझौते के मूल पक्ष से प्राप्त होता है।तीसरे पक्ष को नए कर्तव्यों और देनदारियों के साथ भारित नहीं किया जा सकता है जिनके लिए उसने सहमति नहीं दी है।उन्हें केवल उस हद तक उत्तरदायी या हकदार ठहराया जा सकता है जब तक वे समझौते के मूल पक्ष से अपने अधिकार या हक प्राप्त करते हैं।

133. उपरोक्त सूत्रीकरण को ऑस्ट्रेलियाई द्वारा और स्पष्ट किया गया था।

राइनहार्ट बनाम हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग पीटीवाई लिमिटेड 112 में उच्च न्यायालय, जहाँ यह

यह देखा गया कि टैनिंग रिसर्च (ऊपर) में अंतिम परीक्षण यह था कि क्या बचाव का एक आवश्यक तत्व मध्यस्थता समझौते में पक्ष द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य था या नहीं।राइनहार्ट (ऊपर) में, न्यायालय एक ऐसी स्थिति से निपट रहा था जहां एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष ने विश्वासघात में खनन आवास सौंपे थे।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समनुदेशित व्यक्ति समनुदेशक के रूप में दावेदार के समान स्थिति में खड़ा होता है क्योंकि समनुदेशित व्यक्ति ने अपना रुख एक ऐसे आधार पर रखा जो समनुदेशक के लिए उपलब्ध था।" न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि समनुदेशित व्यक्ति हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के माध्यम से या उनके तहत इस आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति थे कि मध्यस्थता समझौते के पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि खनन घरों के लाभकारी स्वामित्व के बारे में कोई भी विवाद मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जाएगा।चूंकि तीसरे पक्षों ने समझौते के लाभों को स्वीकार कर लिया था, इसलिए यह माना गया कि उन्हें मध्यस्थता सहित इसकी निर्धारित शर्तों के बोझ को भी स्वीकार करना चाहिए।

112 [2019] एचसीए 13

134.राइनहार्ट (ऊपर) में, ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अमेरिकी न्यायालयों द्वारा विकसित न्यायसंगत बहिष्कार के सिद्धांत के समान है, इस आशय के लिए कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष जो अनुबंध के कुछ पहलुओं का लाभ उठाने का चुनाव करता है, उसे भी इसका बोझ स्वीकार करना चाहिए।113 हालाँकि, हम "माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश के संदर्भ में राइनहार्ट (उपरोक्त) स्थिति को नहीं अपना सकते हैं क्योंकि ऐसा करना सामान्य कानून की स्थिति और मध्यस्थता अधिनियम को रेखांकित करने वाले विधायी इरादे के विपरीत होगा, जैसा कि नीचे चर्चा की जाएगी।

135. ऊपर उद्धृत मामलों का विश्लेषण कानून के निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित करता है:सबसे पहले, विशिष्ट परिदृश्य जहां कोई व्यक्ति या संस्था किसी पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा कर सकती है, वे हैं समनुदेशन, अभियोग, और नवीनता; दूसरा, एक व्यक्ति "जिसके माध्यम से या उसके तहत दावा करता है" वह व्युत्पन्न क्षमता में अधिकार का दावा कर सकता है, जो कि मध्यस्थता समझौते के पक्ष के माध्यम से है, समझौते में भाग लेने के लिए; तीसरा, जिसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों के रूप में खड़े होने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है, लेकिन हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के हित के उत्तराधिकारी के रूप में; और चौथा, केवल कानूनी या वाणिज्यिक संबंध एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के लिए हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

आई. पार्टी और व्यक्ति "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले" अलग-अलग हैं

136. 246 वें विधि आयोग ने सुझाव दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) के तहत "पक्ष" की अवज्ञा में "या ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति" शब्दों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाए।आयोग ने तर्क दिया कि उचित संदर्भों में, एक पक्ष में ऐसे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करते हैं जैसे कि हित में उत्तराधिकारी।हालाँकि, सुझाए गए संशोधन को संसद द्वारा लागू नहीं किया गया था।

137. "दावा" शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है जो कानूनी मांग की हर प्रजाति को शामिल करता है। सामान्य अर्थों में, इसका अर्थ है अपने या अपने अधिकार के रूप में मांग करना।114 "दावा" का अर्थ कार्रवाई के कारण का दावा करना भी है।115 अभिव्यक्ति "के माध्यम से" का अर्थ है, परिणामस्वरूप

113 विक्की प्रिस्किच, मध्यस्थता समझौतों के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करना-एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति कौन हैं?' (2019) 35(3) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 375-386। 114 ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण, 1979) 224

115 पी. रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन (1997) 330 703

के कारण से।" 116 "नीचे" शब्द का उपयोग एक निम्न या अधीनस्थ स्थिति के संदर्भ में किया जाता है।पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन में व्युत्पन्न अधिकारों के तहत दावा करने वाले व्यक्ति को इंगित करने के लिए "उसके तहत दावा करना" या "उसके तहत दावा करना" कहा गया है।117 जब उपरोक्त परिभाषाओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, तो यह एक निष्कर्ष को जन्म देता है कि एक व्यक्ति "माध्यम से या उसके तहत दावा कर रहा है" एक मध्यवर्ती या व्युत्पन्न क्षमता में अपनी कानूनी मांग या कार्रवाई के कारण का दावा कर रहा है।हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस पक्ष से वह अपना दावा या अधिकार प्राप्त कर रहा है, उसकी तुलना में "उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले" व्यक्ति के पास कम या अधीनस्थ अधिकार हैं।इसलिए, एक व्यक्ति जो "माध्यम से या उसके तहत दावा करता है" अपनी शर्तों पर मध्यस्थता समझौते का "पक्ष" नहीं हो सकता है क्योंकि यह केवल मूल हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के स्थान पर है।

138. एक मध्यस्थता पक्षकारों की सहमति पर स्थापित की जाती है ताकि वे अपने विवादों को एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में भेज सकें।नतीजतन, आम तौर पर तीसरे पक्ष को उस समझौते के आधार पर मध्यस्थता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने सहमति नहीं दी है।"माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश का उपयोग मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) या धारा 7 में नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्रावधान पार्टी की स्वायत्तता और पार्टी की स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित हैं, जिसके लिए पार्टी को अपने विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए सहमति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने

वाला व्यक्ति केवल मूल पक्ष के स्थान पर इस हद तक खड़ा है कि यह केवल मध्यस्थता समझौते के लिए मूल पक्ष के अधिकार को उत्तेजित कर रहा है।

139. "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश का उपयोग धारा 8,35 और 45 में उनके विशिष्ट संदर्भों में किया गया है।धारा 8 में एक आदेश है कि जब किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, तो विवाद को किसी पक्ष या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 45 के अनुरूप लाने के लिए धारा 8 में "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश जोड़ा गया था।धारा 8 और 45 आकस्मिक प्रकृति की हैं जो न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अनिवार्य करती हैं यदि कोई वैध मध्यस्थता समझौता है।118 ए अय्यासामी (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया था

116 ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वीं संस्करण, 1979) 1328

117 पी. रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन (1997) 331

118 एग्री गोल्ड एक्जिम्स लिमिटेड बनाम श्री लक्ष्मी निट्स एंड वोवेन्स, (2007) 3 एस. सी. सी. 686

कि धारा 8 प्रत्येक न्यायिक प्राधिकारी पर "विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए उनके बीच किए गए समझौते की शर्तों के लिए पक्षों को रोकने" के लिए एक बाध्यकारी दायित्व लगाती है।" 119 इस प्रकार, धारा 8 और 45 के पीछे विधायी इरादा यह सुनिश्चित करना है कि पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से उनके बीच या उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने के अपने आपसी इरादे को पूरा करें।140. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 35 में प्रावधान है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार क्रमशः पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी होगा।चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने ठीक ही कहा कि अभिव्यक्ति "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" "इस सिद्धांत की एक विधायी मान्यता है कि पक्षों के अलावा, एक मध्यस्थ पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य करता है जिसकी क्षमता या स्थिति कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में प्राप्त होती है।" यह आगे देखा गया कि "[एच] एविंग ने एक पक्ष से अपनी क्षमता प्राप्त की और कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में एक ही स्थिति में होना उस व्यक्ति को बाध्य करता है जो इसके तहत दावा करता है।" इसी तरह, धारा 73 में यह भी प्रावधान है कि पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता समझौता उनके तहत दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों के लिए क्रमशः अनिवार्य और बाध्यकारी होगा।"

141. धारा 8,35 और 45 में "पक्ष या कोई भी व्यक्ति जो इसके माध्यम से या उसके तहत दावा करता है" वाक्यांश का उपयोग किया गया है।"या" शब्द का उपयोग धारा 8 और 45 में एक विकल्प को व्यक्त करने या "पक्षों" या "किसी भी व्यक्ति के माध्यम से या उसके तहत दावा करने" के बीच

एक विकल्प देने के लिए एक विभेदक कण के रूप में किया जाता है।नतीजतन, या तो मध्यस्थता समझौते का पक्षकार या पक्षकार के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।यह पक्षों के इरादे का सम्मान करने और वाणिज्यिक प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के हित में है कि उपरोक्त प्रावधान या तो पक्ष या किसी भी व्यक्ति को "उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने" को मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने की अनुमति देते हैं।

142. दूसरी ओर, धारा 35 और 73 में "पक्षकार और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति" वाक्यांश का उपयोग किया गया है।धारा 35 और 73 में "और" शब्द का उपयोग इस विचार को व्यक्त करता है कि "पक्षों" को बाद के वाक्यांश "किसी भी व्यक्ति के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले" के साथ जोड़ा या लिया जाना है।" उपरोक्त प्रावधानों में यह प्रावधान है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार न केवल पक्षों को बल्कि ऐसे सभी व्यक्तियों को भी बाध्य करता है जो मध्यस्थता समझौते के लिए पक्ष से अपनी क्षमता प्राप्त करते हैं।पुनः, इस प्रावधान का मूलभूत आधार है -

119 (2016) 10 एससीसी 386 705

वाणिज्यिक प्रभावकारिता क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार वास्तविकता की ओर ले जाता है, जैसे कि दोनों पक्ष और उनके माध्यम से या उनके तहत दावा करने वाले सभी व्यक्ति दावों को फिर से सक्रिय नहीं करते हैं।इसके अलावा, धारा 35 और 73 में "और" शब्द का उपयोग एक स्पष्ट निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत, एक "पक्ष" की अवधारणा मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों की अवधारणा से अलग और अलग है।

ii.क्लोरो नियंत्रण में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण गलत है।

143. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहाःपहला, कि "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति का उपयोग मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ता "पक्षों" से परे शब्दों के दायरे को बढ़ाने के विधायी इरादे को दर्शाता है; दूसरा, मध्यस्थता समझौते के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का कंपनी समूह के सिद्धांत के आधार पर पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले पक्ष के साथ कानूनी संबंध हो सकता है; और तीसरा, एक बहु-पक्षीय अनुबंध के मामले में, एक सहायक कंपनी जो मूल अनुबंध से अपने मूल हित को "प्राप्त" करती है, "हालांकि या उसके तहत दावा" अभिव्यक्ति के तहत शामिल होगी।"

144. कानून का पहला प्रस्ताव "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति के निर्माण पर निर्भर करता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि धारा 45 की भाषा का व्यापक महत्व है।हालाँकि, "किसी भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति को इसके संदर्भ के बिना अलग नहीं किया जा सकता है और इसका अर्थ नहीं

लगाया जा सकता है।संदर्भ, धारा 8 और 45 के संदर्भ में, बाद के वाक्यांश द्वारा प्रदान किया गया है-"माध्यम से या उसके तहत दावा करना"।इसलिए, ऐसे "कोई भी व्यक्ति" केवल व्युत्पन्न क्षमता में कार्य कर रहे हैं।चूँकि एक मध्यस्थता समझौते में राष्ट्रीय न्यायालयों की अधिकारिता शामिल नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि पक्षकार, या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपने विवाद प्रस्तुत करने के लिए सहमति दें।

145. कानून के दूसरे और तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत बाद वाले के साथ अपने कानूनी या वाणिज्यिक संबंधों के आधार पर दावा कर सकता है।हालाँकि, यह प्रस्ताव सामान्य कानून की स्थिति के विपरीत है जैसा कि संचेती (ऊपर) और टैनिंग रिसर्च लैबोरेटरीज़ (ऊपर) में प्रमाणित किया गया है, जिसके अनुसार केवल कानूनी या वाणिज्यिक संबंध एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते के माध्यम से या उसके तहत दावा करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं है।ए. अय्यासामी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की व्याख्या की जानी चाहिए "ताकि इसकी व्याख्या में अंतर्निहित सिद्धांतों को इस तरह से लाया जा सके कि

सामान्य कानून की दुनिया में प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुरूप।" इसलिए, भले ही एक सहायक कंपनी एक समूह के भीतर कंपनी द्वारा किए गए अनुबंध से ब्याज या लाभ प्राप्त करती है, लेकिन वे केवल इस आधार पर "दावे के माध्यम से या उसके तहत" अभिव्यक्ति के तहत शामिल नहीं होंगे कि वह पक्षों के साथ कानूनी या वाणिज्यिक संबंध साझा करती है।

146. हमारे सामने जिन प्रश्नों का उल्लेख किया गया है, उनमें से एक यह है कि क्या धारा 8 में "दावे के माध्यम से या उसके तहत" वाक्यांश की व्याख्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को शामिल करने के लिए की जा सकती है।कंपनियों के समूह का सिद्धांत यह निर्धारित करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे पर आधारित है कि क्या किसी समूह के भीतर गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई को अपने अधिकार में मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष बनाया जा सकता है।ऐसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता संस्था किसी हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा नहीं कर रही है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" का उपयोग ब्याज में उत्तराधिकारियों के संदर्भ में किया जाता है जो एक व्युत्पन्न क्षमता में कार्य करते हैं और मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को प्रतिस्थापित करते हैं।इसके विपरीत, कंपनियों के समूह के सिद्धांत का उपयोग मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बांधने के लिए किया जाता है ताकि यह लाभों को उत्तेजित कर सके और अनुबंध के प्रदर्शन के दौरान प्राप्त या प्रदान किए गए बोझ के अधीन हो सके।इस सिद्धांत का उपयोग मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 45 में दिखाई देने वाले वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने" की परवाह किए बिना मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को बांधने के लिए किया जा सकता है।

147. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में, यह न्यायालय गैर-हस्ताक्षरकर्ता संस्थाओं को उनके अपने अधिकारों में मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों के रूप में इस आधार पर शामिल करता है कि वे सहायक समझौतों के हस्ताक्षरकर्ता थे जो मध्यस्थता समझौते वाले प्रमुख समझौते के प्रदर्शन के साथ निकटता से जुड़े थे।क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस अदालत ने तर्क दिया कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता संस्थाएं, हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के रूप में एक ही कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा होने के नाते, हित या सहायक कंपनियों में सहायक थीं, और इसलिए हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के माध्यम से या उनके तहत "दावा" कर रही थीं।जैसा कि ऊपर कहा गया है, वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" केवल एक व्युत्पन्न क्षमता में कार्य करने वाली संस्थाओं पर लागू होता है न कि अपने स्वयं के अधिकार में पक्षों के सहयोगी के संबंध में।इसलिए, हम मानते हैं कि क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस न्यायालय का दृष्टिकोण इस हद तक है कि उसने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को "माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश से जोड़ा है जो गलत है और अनुबंध और वाणिज्यिक कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, 707

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 708

कंपनियों के समूह के सिद्धांत का अस्तित्व आंतरिक रूप से एक वाणिज्यिक सौदे के लिए पक्षों के आपसी इरादे के सिद्धांत पर पाया जाता है।148. मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना ने इस सवाल पर भी विचार करने का अनुरोध किया कि क्या क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) और उसके बाद के निर्णयों द्वारा व्याख्या की गई "कंपनियों के समूह का सिद्धांत" कानून में मान्य है।कंपनियों के समूह के सिद्धांत की कई पक्षों और कई समझौतों से जुड़े जटिल लेनदेन के संदर्भ में पक्षों के आपसी इरादे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण उपयोगिता है।इसके अलावा, यह सिद्धांत भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून सहित कुछ अन्य क्षेत्राधिकारों में समर्थन नहीं मिला है।हालाँकि, हम उस सिद्धांत को बनाए रखना उचित समझते हैं जो भारतीय न्यायशास्त्र में निहित है, हालांकि इसे आपसी सहमति या वाणिज्यिक सौदे के लिए पक्षों के आपसी इरादे के दायरे में स्थापित करके।यह एक ओर यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय मध्यस्थता कानून में गतिशीलता की भावना बनी रहे ताकि समकालीन चुनौतियों का जवाब दिया जा सके।साथ ही, सिद्धांत को सुझाए गए तरीके से संरचित करना आवश्यक है ताकि इसे पारस्परिक इरादे की व्याख्या को नियंत्रित करने वाले स्थिर सिद्धांतों में आधारित किया जा सके।यह सुनिश्चित करेगा कि इस सिद्धांत का पक्ष की स्वायत्तता और मध्यस्थता के लिए सहमति में एक न्यायशास्त्रीय आधार है।

149. यद्यपि हमारे समक्ष मुद्दा काफी हद तक भारतीय संदर्भ में कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित है, यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में बदलती धाराओं से अनजान नहीं हो सकता है।कंपनियों के समूह के सिद्धांत की रूपरेखा तय करने में, हमने सामान्य कानूनी प्रस्ताव को दोहराया है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति या संस्थाएं भी एक मध्यस्थता समझौते से बंधी हो सकती हैं।इस तरह के जुड़ाव का आधार मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के साथ

धारा 2 (1) (एच) के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से उत्पन्न होता है। चूँकि इस निर्णय का दायरा कंपनियों के समूह के सिद्धांत तक सीमित था, इसलिए इस निर्णय के दौरान इस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक निर्धारण की व्याख्या मध्यस्थता समझौतों के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करने के लिए अन्य सिद्धांतों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बाहर करने के लिए नहीं की जानी चाहिए।हालाँकि, हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारतीय न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों तक बढ़ाने के लिए केवल इस आधार पर अति उत्साही दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कि वे एक कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा हैं।

150. चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला पाया, न कि मध्यस्थता समझौते के लिए एक "पक्ष" के रूप में।उस मामले में, यह न्यायालय एक मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित मुद्दे पर विचार कर रहा था।उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध के तहत हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का एक नामित व्यक्ति था, और इसलिए एक व्युत्पन्न क्षमता में कार्य कर रहा था।केनरा बैंक (ऊपर) में इस न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से हस्ताक्षर न करने वाले को इस आधार पर बाध्य करने के लिए रोक लगाने के सिद्धांत को अपनाया कि उसने पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में भाग लिया था, और बाद में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष होने से इनकार नहीं कर सकता है।डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करके खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया।इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत से संबंधित अवलोकन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रस्तुत किए गए थे।हमने पिछले पैराग्राफ में इन निर्णयों से उत्पन्न कानून के अलग-अलग हिस्सों को सुसंगत बनाया है।

151. लॉज एम्पायर में, रोनाल्ड ड्वोर्किन ने एक काल्पनिक प्रस्ताव रखा जिसमें उपन्यासकारों का एक समूह एक उपन्यास धारावाहिक लिखते हैं, प्रत्येक उपन्यासकार उन्हें दिए गए अध्यायों की व्याख्या करते हुए एक नया अध्याय लिखते हैं।120 उपन्यासकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे "निरंतरता की अपनी जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता से लें" ताकि "एक एकल एकीकृत उपन्यास बनाया जा सके जो सबसे अच्छा हो सकता है।" 121 क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कंपनियों के समूह के सिद्धांत का पहला अध्याय था।चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) से शुरू होने वाले और कॉक्स और किंग्स (ऊपर) के साथ समाप्त होने वाले बाद के निर्णयों की श्रृंखला वृद्धिशील अध्याय थे-प्रत्येक पिछले अध्यायों में पहले से ही प्रतिपादित सिद्धांत में और आयाम जोड़ते हैं।इस मामले में, हमने कंपनियों के समूह के सिद्धांत में एक और अध्याय जोड़ा है।हमारा

उद्देश्य मध्यस्थता कानून के विकास के क्रम में और प्रगति करना था।इस प्रक्रिया में, हमने पिछले अध्यायों को फिर से लिखने या त्यागने के बजाय उपन्यास को अधिक सुसंगत पढ़ने के लिए कथानक में बदलाव किया है।

120 रोनाल्ड ड्वोर्किन, लॉज़ एम्पायर (बेल्कनैप प्रेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1986) 229। 121 आई. बी. आई. डी.

709

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 710

iii.धारा 9 के तहत निर्देश जारी करने की न्यायालयों की शक्ति

152. कॉक्स एंड किंग्स (उपरोक्त) मामले में, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने" वाक्यांश में कंपनियों के समूह के सिद्धांत को स्थापित करने से एक विसंगत स्थिति पैदा होती है जहां एक पक्ष "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने" को मध्यस्थता समझौते के लिए संदर्भित किया जा सकता है, लेकिन उसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत राहत लेने का अधिकार नहीं होगा। धारा 9 एक "पक्ष" को किसी नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति, किसी भी सामान की अभिरक्षा या बिक्री जो मध्यस्थता समझौते का विषय है, और प्राप्तकर्ता की नियुक्ति जैसे अंतरिम उपायों की मांग करने के लिए अदालत से संपर्क करने की अनुमति देती है।

153. कंपनियों के समूह का सिद्धांत मध्यस्थता समझौते के लिए एक "वास्तविक" पक्ष के रूप में गैर-हस्ताक्षरकर्ता में शामिल होने के आपसी इरादे को निर्धारित करने पर आधारित है।एक बार जब कोई न्यायाधिकरण इस निर्धारण पर पहुंच जाता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है, तो ऐसा गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों के लिए आवेदन कर सकता है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (1) (एच) के तहत "पक्ष" की अवज्ञा में कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए कानूनी आधार स्थापित करना मुख्य न्यायाधीश रमन्ना द्वारा बताई गई विसंगति को हल करता है।

G. निर्देश स्तर पर निर्धारण का मानक-धारा 8 और 11

154. अंतिम लेकिन कम से कम मुद्दा जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह मध्यस्थता अधिनियम के तहत कंपनियों के समूह के सिद्धांत की प्रयोज्यता के चरण से संबंधित है। कॉक्स एंड किंग्स (उपरोक्त) मामले में, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि अपरिवर्तित धारा 2 (1) (एच) के दायरे पर विचार करते हुए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के चरण में न्यायिक संदर्भ के दायरे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि "कोई भी न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया है।" "इस प्रकार प्रदान किए गए" का संदर्भ धारा 8 और 11 में निहित है जो अदालतों को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का आदेश देता है।धारा 8 के तहत, अदालत को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का

"प्रथम दृष्टया" पता लगाना होता है।धारा 11 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सहमत मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करने में पक्षों की विफलता पर मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है।धारा 11 को ऐसी स्थिति में लागू किया जा सकता है जब कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो और किसी एक पक्ष को

मध्यस्थता समझौते ने दूसरे पक्ष के असहयोग के कारण मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत प्रक्रिया को असफल रूप से लागू किया।

155. एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 122 में सात न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश या उनकी नामित शक्तियों का दायरा निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश के पास अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र, एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, एक जीवित दावे का अस्तित्व, अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए शर्त का अस्तित्व और मध्यस्थों की योग्यता निर्धारित करने की शक्तियां होंगी।इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम के तहत परिभाषित कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या अनुरोध करने वाला व्यक्ति इस तरह के समझौते का पक्षकार है।

156. 2015 में मध्यस्थता अधिनियम में धारा 11 (6-ए) को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था।उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

“(6 क) उच्चतम न्यायालय, या यथास्थिति, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या (उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद,

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच।”

गैर-अस्थाई खंड के आधार पर, धारा 11 (6 ए) ने एक नई स्थिति निर्धारित की है, जो पटेल इंजीनियरिंग (उपरोक्त) में निर्धारित स्थिति के आधार को छीन लेती है।2019 में, संसद ने धारा 11 (6-ए) को हटाते हुए मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया।हालांकि, धारा 11 (6-ए) में संशोधन को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।उस समय तक, 2015 में संशोधित धारा 11 लागू रहेगी।

157. रेफरल मुद्दे का निर्णय करते समय, धारा 8 और 11 दोनों के तहत संदर्भ का दायरा सीमित है। जहां धारा 8 रेफरल अदालत से एक वैध मध्यस्थता समझौते के प्रथम दृष्टया अस्तित्व को देखने

की अपेक्षा करती है, धारा 11 अदालत के अधिकार क्षेत्र को एक मध्यस्थता समझौते की परीक्षा के अस्तित्व तक सीमित करती है।

122 (2005) 8 एससीसी 618 711

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 712

158. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 भारतीय मध्यस्थता कानून में योग्यता-क्षमता के सिद्धांत को स्थापित करती है।यह प्रावधान मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर कोई भी निर्णय शामिल है।धारा 16 एक समावेशी प्रावधान है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता से जुड़े सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझता है।123 योग्यता-क्षमता के सिद्धांत का उद्देश्य सीमा स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है।मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों को निर्धारित करने का मुद्दा मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अधिकारिता क्षमता की जड़ तक जाता है।

159. विद्या द्रोलिया (ऊपर) में, न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 8 में संशोधन ने घरेलू मध्यस्थता के संबंध में क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में बताई गई कमियों को दूर किया।उन्होंने आगे कहा कि मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों के निर्धारण का मुद्दा एक जटिल अभ्यास है, और इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरणों पर छोड़ दिया जाना चाहिएः

“239. […] एक बहु-पक्षीय मध्यस्थता में समूह-कंपनी सिद्धांत या सद्भावना आदि के तहत कुछ पक्ष किसी विशेष मध्यस्थता से बंधे हैं या नहीं, इस संबंध में न्यायिक मुद्दे जटिल तथ्यात्मक प्रश्न उठाते हैं, जिन्हें संभालने के लिए न्यायाधिकरण पर सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है।इस मोर्चे पर धारा 8 में संशोधन संदर्भ के स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को और कम करने के विधायी इरादे को भी इंगित करता है।”

160. प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इन्फ्रा और

इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, 124 इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर याचिका से उत्पन्न अपील पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था।न्यायालय के समक्ष मुद्दा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का निर्धारण था।इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया राय दी कि एक वैध मध्यस्थता के अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था

123 उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम.उत्तरी कोयला क्षेत्र, (2020) 2 एससीसी 455

124 (2021) 5 एस. सी. सी. 671

पक्षों के बीच समझौता।इसलिए, एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के मुद्दे को दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत जांच और गवाहों से जिरह करने के बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया गया था।

161. कानून की उपरोक्त स्थिति हमें इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर ले जाती है कि रेफरल चरण में, अदालत को केवल एक मध्यस्थता समझौते के प्रथम दृष्टया अस्तित्व का निर्धारण करना होता है। यदि रेफरल अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर सकती है, तो उसे इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए।रेफरल अदालत को मध्यस्थता की कार्यवाही में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिए।शिन-एटसु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड, 125 में इस न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता समझौते की वैधता से संबंधित मामलों पर अंतिम निर्धारण न्यायाधिकरण पर छोड़ने के अलग-अलग फायदे हैं:

74. […] भले ही न्यायालय का यह विचार हो कि मध्यस्थता समझौता दूषित नहीं है या यह विशुद्ध रूप से प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के आधार पर वैध, निष्क्रिय या अप्रवर्तनीय नहीं है, मध्यस्थ को इस मुद्दे पर पूरी तरह से अंतिम निर्णय देने से कुछ भी नहीं रोकता है।यदि मध्यस्थ समझौते को वैध पाता है, तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि मध्यस्थता आगे बढ़ेगी और निर्णय लिया जाएगा।हालाँकि, यदि मध्यस्थ को समझौता अमान्य, निष्क्रिय या अमान्य लगता है, तो इसका मतलब है कि जो पक्ष मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ना चाहता था, उसे मध्यस्थता की कार्यवाही का अवसर दिया गया था, और मध्यस्थ ने मुद्दे को पूरी तरह से देखने के बाद पाया है कि मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।"

162. क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 का विधायी आशय यह निष्कर्ष निकालना है कि क्या मध्यस्थता समझौता पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले "अमान्य, निष्क्रिय और निष्पादित करने में असमर्थ" है। 2019 में, धारा 45 में "जब तक कि यह प्रथम दृष्टया न मिले" अभिव्यक्ति को जोड़ा गया था।विधायी संशोधन को देखते हुए, आधार

125 (2005) 7 एस. सी. सी. 234 713

क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) की उपरोक्त होल्डिंग को स्पष्ट रूप से हटा लिया गया है।कानून की वर्तमान स्थिति यह है कि रेफरल अदालत को केवल मध्यस्थता समझौते की वैधता या अस्तित्व पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष देने की आवश्यकता है।

163. डॉयचे पोस्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड बनाम तादुरी

श्रीधर, 126, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत किसी तीसरे पक्ष को याचिका में शामिल किया जाता है, तो रेफरल अदालत को मामले को न्यायाधिकरण को भेजने से पहले ऐसे तीसरे पक्ष को पक्षकारों की श्रेणी से हटा देना चाहिए या बाहर कर देना चाहिए।यह अवलोकन क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय से पहले किया गया था और अब कानून की वर्तमान स्थिति के आलोक में प्रासंगिक नहीं है।इस प्रकार, जब एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति या संस्था को धारा 8 या धारा 11 के चरण में एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो रेफरल अदालत को प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते की वैधता या अस्तित्व का निर्धारण करना चाहिए, जैसा भी मामला हो, और यह निर्णय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते से बाध्य है।

164. मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के शामिल होने के मामले में, निम्नलिखित दो परिदृश्य प्रमुख रूप से सामने आएंगे:पहला, जहां एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का सहयोगी चाहता है; और दूसरा, जहां एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष स्वयं एक मध्यस्थता समझौते का आह्वान चाहता है। दोनों परिदृश्यों में, रेफरल अदालत को प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी और क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते का एक वास्तविक पक्ष है। इस तरह के निर्धारण की जटिलता को देखते हुए, रेफरल अदालत को यह तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष वास्तव में तथ्यात्मक साक्ष्य और कानूनी सिद्धांत के अनुप्रयोग के आधार पर मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है या नहीं। न्यायाधिकरण यह तय करने के लिए मामले के तथ्यात्मक, परिस्थितिजन्य और कानूनी पहलुओं पर विचार कर सकता है कि क्या इसका अधिकार क्षेत्र गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष तक फैला हुआ है। प्रक्रिया में, न्यायाधिकरण को आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए

126 (2011) 11 एससीसी 375

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जैसे कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता के संबंध में आपत्तियां उठाने का अवसर देना।यह व्याख्या धारा 16 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले मध्यस्थता समझौते के लिए सच्चे पक्षों के निर्धारण के मुद्दे को छोड़कर क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को भी सही प्रभाव देती है।

एच. निष्कर्ष

165. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं:

ए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (1) (एच) के तहत "पक्षों" की परिभाषा में हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष दोनों शामिल हैं;

बी। गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का आचरण मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए उनकी सहमति का एक संकेतक हो सकता है;ग. धारा 7 के तहत एक लिखित मध्यस्थता समझौते की आवश्यकता गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को बाध्य करने की संभावना को बाहर नहीं करती है;

घ. मध्यस्थता अधिनियम के तहत, एक "पक्ष" की अवधारणा मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों की अवधारणा से अलग और अलग है।

ङ. गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे का निर्धारण करते हुए कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने का अंतर्निहित आधार समूह की कंपनियों की कॉर्पोरेट अलगाव को बनाए रखने पर आधारित है।

च. अहंकार को बदलने या निगमित आवरण को भेदने का सिद्धांत कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है।

छ. कंपनियों के समूह के सिद्धांत का कानून के एक सिद्धांत के रूप में एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के साथ धारा 2 (1) (एच) के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से उत्पन्न होता है।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 716

ज. कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए, अदालतों या न्यायाधिकरणों को, जैसा भी मामला हो, डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में निर्धारित सभी संचयी कारकों पर विचार करना होगा।नतीजतन, एकल आर्थिक इकाई का सिद्धांत कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

आई. "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले" व्यक्ति केवल व्युत्पन्न क्षमता में अधिकार का दावा कर सकते हैं;

जे. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में इस न्यायालय का दृष्टिकोण इस हद तक कि उसने कंपनियों के समूह के सिद्धांत का पता "माध्यम से या उसके तहत दावा करना" वाक्यांश से लगाया है, गलत है और अनुबंध कानून और कॉर्पोरेट कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।

के. कंपनियों के समूह के सिद्धांत को भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कई पक्षों और कई समझौतों से जुड़े जटिल लेनदेन के संदर्भ में पक्षों के इरादे को निर्धारित करने में इसकी उपयोगिता पर विचार करते हुए बनाए रखा जाना चाहिए;

एल. रेफरल स्तर पर, रेफरल अदालत को यह तय करने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते से बाध्य है; और

एम. गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए अन्य सिद्धांतों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बाहर करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत से संबंधित इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्धारण की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।

166. हम उपरोक्त शब्दों में इस संविधान पीठ को निर्दिष्ट कानून के प्रश्नों का उत्तर देते हैं।रजिस्ट्री प्रशासनिक पक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश प्राप्त करने के बाद मामलों को निपटान के लिए नियमित पीठ के समक्ष रखेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

न्याय

सूचकांक *

ए. परिचय. 1 बी. सिविल उपचार और मध्यस्थता।मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध है।धारा 7 (4) (बी). 9 सी. कंपनियों का समूह सिद्धांत. 17 i.अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य. 17 ii.कंपनी समूह पर भारतीय पूर्वाभास सिद्धांत. 27 डी. धारा 7.39 ई के संदर्भ में कंपनी समूह सिद्धांत. निष्कर्ष. 43

पमिडिगंथम श्री नरसिम्हा, जे. ए. परिचय

1. इस संविधान पीठ का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996,1 के तहत कार्यवाही के लिए 'कंपनी समूह सिद्धांत' की प्रयोज्यता के आधिकारिक निर्धारण के लिए है और यदि लागू और वैधानिक रूप से लंगर डाला गया है, तो इसकी सटीक रूपरेखा को चित्रित करने के लिए है।2. संदर्भ आदेश में, मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना ने इस सिद्धांत की व्याख्या और अनुप्रयोग में भिन्नताओं पर प्रकाश डाला क्योंकि यह भारत में विकसित हुआ है।उन्होंने "के माध्यम से या उसके तहत दावा" वाक्यांश में सिद्धांत के वैधानिक स्रोत पर सवाल उठाया, जो अधिनियम की धारा 8 और 45 में दिखाई देता है। उन्होंने यह भी आगाह किया कि कंपनियों के एक ही समूह के सदस्यों की अलग कानूनी पहचान बनाए रखना कॉर्पोरेट और अनुबंध कानून का एक मौलिक सिद्धांत है।इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना द्वारा इस संविधान पीठ को निर्दिष्ट और निर्दिष्ट किए गए विशिष्ट प्रश्न इस प्रकार हैं:"(क) क्या धारा 8 और 11 3 में "के माध्यम से या उसके तहत दावा" वाक्यांश की व्याख्या "कंपनियों के समूह" सिद्धांत को शामिल करने के लिए की जा सकती है?

1 इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया।

2 अपने लिए और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना के लिए।

3 वाक्यांश "माध्यम से या उसके तहत दावा करना" धारा 11 में दिखाई नहीं देता है।बल्कि, धारा 11 के संदर्भ को धारा 45 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें यह वाक्यांश शामिल है।

*एड। ध्यान दें:मूल निर्णय के अनुसार पृष्ठांकन।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 718

(ख) क्या क्लोरो कंट्रोल्स केस 4 और उसके बाद के निर्णयों द्वारा समझाया गया "कंपनियों का समूह" सिद्धांत कानून में मान्य है?" 5 3.न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्य न्यायाधीश रमन्ना के साथ सहमति व्यक्त की और संदर्भ के लिए उनके कारणों को पूरा किया।शुरुआत में, उन्होंने बहु-पक्षीय व्यावसायिक लेनदेन की जटिलता के साथ तालमेल रखने के लिए भारत में सिद्धांत को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां कुछ व्यक्ति औपचारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, लेकिन इसकी बातचीत और प्रदर्शन में शामिल होते हैं।विशेष रूप से भारत में, बड़ी संख्या में परिवार द्वारा संचालित व्यावसायिक समूहों के साथ, उन्होंने व्यक्त किया कि मध्यस्थता के माध्यम से प्रभावी और पूर्ण विवाद समाधान के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी का समावेश आवश्यक है। हालाँकि, उन्होंने सिद्धांत के निर्माण में विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता का भी संकेत दिया।उन्होंने गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्षकार निर्धारित करने के लिए समानता संबंधी विचारों और 'एकल आर्थिक वास्तविकता' पर निर्भरता पर सवाल उठाया, क्योंकि ये दल की स्वायत्तता और अलग कानूनी इकाई के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।इस संदर्भ में, सिद्धांत की रूपरेखा के आधिकारिक निर्धारण के लिए, उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

"(क) क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को अधिनियम की धारा 8 में पढ़ा जाना चाहिए या क्या यह किसी भी वैधानिक प्रावधान से स्वतंत्र भारतीय न्यायशास्त्र में मौजूद हो सकता है?

(ख) क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को "एकल आर्थिक वास्तविकता" के सिद्धांत के आधार पर लागू किया जाना चाहिए?

(ग) क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के निहित सहमति या इरादे की व्याख्या करने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए?

(घ) क्या अहंकार को बदलने और/या निगमित आवरण को भेदने के सिद्धांत ही निहित सहमति के अभाव में भी कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए दबाव डालने को उचित ठहरा सकते हैं?" 6

4 क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनामसेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफी कैशन इंक., (2013) 1 एससीसी

641 [2012 आईएनएससी 436]।

5 कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2022) 8 एससीसी 1, पैरा 54 [2022 आईएनएससी 523]।

6 आईबीआईडी, पैरा 104।

4. मुझे विद्वान मुख्य न्यायाधीश की विद्वतापूर्ण और व्यापक राय को पढ़ने का लाभ मिला है।जबकि मैं उनके तर्क और निष्कर्षों से सहमत हूं, मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने स्वयं के तर्क के साथ उन्हें पूरक करना आवश्यक मानता हूं।हमारे सामने व्यापक प्रश्न एक 'मध्यस्थता समझौते' के 'पक्षों' से संबंधित है।यह प्रश्न हमें अधिनियम की धारा 7 की ओर ले जाना चाहिए जो निम्नानुसार एक 'मध्यस्थता समझौते' की अवहेलना करता हैः

“7. मध्यस्थता समझौता।—(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह (ए) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में निहित है;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार शामिल है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।”

5. उपर्युक्त वैधानिक निर्देश से यह स्पष्ट है कि एक 'मध्यस्थता समझौते' को धारा 7 की उप-धारा (1) में "पक्षों द्वारा एक समझौते" के रूप में वर्णित किया गया है।ये दोनों अभिव्यक्तियाँ, 'समझौता' और 'पक्ष' हमारे विचार के लिए महत्वपूर्ण हैं।उचित समझ के लिए 719

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 720

इन अभिव्यक्तियों में से, नागरिक कानून में संस्थागत उपचारों के बड़े निकाय में एक विवाद निवारण तंत्र के रूप में मध्यस्थता के स्थान की जांच करना आवश्यक है।

B. सिविल उपचार और मध्यस्थता

6. हमारी कानूनी प्रणाली में, दीवानी अदालतों तक पहुंच एक मानक न्यायिक उपचार है।दीवानी अदालतों के पास सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, 7 और उपचार को प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी समझौते को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के

तहत अमान्य घोषित किया जाता है। 8 तथापि, धारा 28 के अपवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उत्पन्न या उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को "मध्यस्थता को संदर्भित करने के लिए अनुबंध" को छोड़ देते हैं।9 इस प्रकार, यदि मध्यस्थता करने का कोई अनुबंध है, तो अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के तहत नागरिक उपचार तक पहुँच पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

7 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 में कहा गया हैः

"9. अदालतें सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई तब तक करें जब तक कि वे प्रतिबंधित न हों।—न्यायालय (इसके अधीन रहते हुए)

इसमें निहित प्रावधानों) को उन मुकदमों को छोड़कर नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

स्पष्टीकरण I-एक मुकदमा जिसमें संपत्ति या किसी अधिकारी के अधिकार का विरोध किया जाता है, एक नागरिक प्रकृति का मुकदमा है, इसके बावजूद कि ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक संस्कारों या समारोहों के बारे में प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर हो सकता है।

स्पष्टीकरण II-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह मायने नहीं रखता कि स्पष्टीकरण I में निर्दिष्ट कार्यालय से कोई शुल्क संलग्न है या नहीं या ऐसा कार्यालय किसी विशेष स्थान से संलग्न है या नहीं।"

8 इसके बाद 'अनुबंध अधिनियम'।भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"28. कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए किए गए समझौते अमान्य हैं।—प्रत्येक समझौता, -

(क) जिसके द्वारा कोई भी पक्ष सामान्य न्यायाधिकरणों में सामान्य कानूनी कार्यवाही द्वारा किसी अनुबंध के तहत या उसके संबंध में अपने अधिकारों को लागू करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित है, या जो उस समय को सीमित करता है जिसके भीतर वह इस प्रकार अपने अधिकारों को लागू कर सकता है; या

(ख) जो किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है, या किसी विशिष्ट अनुबंध के तहत या उसके संबंध में किसी भी पक्ष को किसी भी दायित्व से मुक्त कर देता है, ताकि किसी भी पक्ष को अपने अधिकारों को लागू करने से रोका जा सके, उस हद तक शून्य है।" 9 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"अपवाद 1.— उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता विवाद को संदर्भित करने के लिए अनुबंध की बचत।

— यह धारा किसी ऐसे अनुबंध को अवैध नहीं बनाएगी जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत हों कि किसी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और इस तरह से निर्दिष्ट विवाद के संबंध में केवल ऐसी मध्यस्थता में दी गई राशि ही वसूली योग्य होगी।

अपवाद 2.— उन प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए अनुबंध की बचत जो पहले ही उत्पन्न हो चुके हैं।—

न ही यह धारा लिखित रूप में किसी भी अनुबंध को अवैध बनाएगी, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति मध्यस्थता के लिए किसी भी प्रश्न को संदर्भित करने के लिए सहमत होते हैं जो पहले से ही उत्पन्न हो चुका है, या मध्यस्थता के संदर्भों के बारे में कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून का कोई प्रावधान लागू करेगा।"

7. एक 'अनुबंध' को अनुबंध अधिनियम के तहत कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है।10 समझौता 11 का गठन तब किया जाता है जब किसी वादे या पारस्परिक वादों (धारा 2 (बी) में उल्लिखित) 12 को एक विचार के साथ आदान-प्रदान किया जाता है (धारा 2 (डी) 13 में निहित) और इन वादों को या तो व्यक्त किया जा सकता है (जब इसका प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में हो) या निहित किया जा सकता है (जब इसका प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों से भिन्न हो)।14 एक समझौता कानूनी रूप से एक अनुबंध के रूप में लागू करने योग्य है यदि यह एक वैध विचार और वैध उद्देश्य के लिए अनुबंध करने में सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से बनाया गया है।15

आई. मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध है

8. एक मध्यस्थता समझौता धारा 7 (1) में अधिक विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

1996 के अधिनियम के अनुसार "पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता के समक्ष उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं।" द.

वाक्यांश 'चाहे संविदात्मक हो या न हो' का उपयोग विवाद के लिए योग्य है, समझौते के लिए नहीं; एक मध्यस्थता समझौता हमेशा एक अनुबंध होना चाहिए, लेकिन जिस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है वह आवश्यक रूप से संविदात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक "अवज्ञाकारी कानूनी संबंध" से उत्पन्न होता है।16

10 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (एच) में कहा गया है:"(ज) कानून द्वारा प्रवर्तनीय समझौता एक अनुबंध है; "11 धारा 2 (ई), भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कहा गया है:"(ङ) प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक समूह, जो एक दूसरे के लिए विचार बनाता है, एक समझौता है।

12 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 (बी) में कहा गया है:

"(ख) जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है, उसकी सहमति हो जाती है, तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। एक प्रस्ताव, जब स्वीकार किया जाता है, तो एक वादा बन जाता है।

13 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 (डी) में कहा गया है:

"(घ) जब वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने से परहेज करता है, या करता है या करने से परहेज करता है, या कुछ करने या करने से परहेज करने का वादा करता है, तो ऐसा कार्य या संयम या वादा वादा के लिए एक विचार कहा जाता है।

14 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 9 में कहा गया है:

"9. वादे, व्यक्त और निहित।—जहाँ तक किसी वादे का प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में की जाती है, वचन को व्यक्त कहा जाता है।जहाँ तक ऐसा प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अलावा अन्य रूप में की जाती है, वचन को निहित कहा जाता है।"

15 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में कहा गया है:

"10. कौन से समझौते अनुबंध हैं?—सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किए जाते हैं।"

16 विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एससीसी 1, पैरा 24 [2020 आईएनएससी 721

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 722

9. मध्यस्थता समझौता मौखिक समझौते के विपरीत लिखित रूप में होना चाहिए।हालाँकि, इसे हस्ताक्षरित दस्तावेज़ होने की आवश्यकता नहीं है:भारत ने अपनाया है

UNCITRAL मॉडल 17 जो मध्यस्थता के लिए समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए एक समझौते के रूप के बजाय उसके सार पर जोर देता है।धारा 7 की उप-धारा (2) इस सिद्धांत को शामिल करती है और अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में एक समझौते को मान्यता देती है।

10. धारा 7 (3) आदेश देती है कि एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, जिसका अर्थ है कि मध्यस्थता समझौता स्पष्ट शर्तों में होना चाहिए।तत्पश्चात, धारा 7 (4) घोषणा करती है कि एक मध्यस्थता समझौता "लिखित रूप में" है यदि यह निम्नलिखित में निहित है:(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़; (ख) पत्राचार का आदान-प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करता है; और (ग) कार्यवाही में प्रवेश, अर्थात, दावा और बचाव का बयान।धारा 7 की सुविचारित भाषा से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, मौखिक समझौते के विपरीत, और साथ ही, यह आवश्यक नहीं है कि इसे पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।18 एक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ जिसमें मध्यस्थता समझौता होता है, केवल लिखित प्रपत्रों में से एक होता है, जहां पक्ष के हस्ताक्षर अनुबंध के अस्तित्व और गोपनीयता के लिए पूर्ण प्रमाण होते हैं।

11. इसलिए धारा 7 व्यापक रूप से यह बताती है कि मध्यस्थता समझौता क्या है और यह भी कि इसे कहाँ से पहचाना जाना है।अधिनियम की धारा 8,11 या 45 के तहत रेफरल अदालत, या मध्यस्थ न्यायाधिकरण, वह मंच है जो मध्यस्थता समझौते और उसके पक्षों के अस्तित्व की पहचान करता है और उसे समझता है।हालाँकि, असली सवाल यह है कि अदालत या न्यायाधिकरण को यह निर्धारण कैसे करना चाहिए, विशेष रूप से जब एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता शुरू करना चाहता है, या एक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पक्षकार बनाए जाने की मांग की जाती है।समझौते में नियोजित स्पष्ट भाषा की व्याख्या करके निष्कर्ष निकालने के मानक तरीकों के अलावा, मध्यस्थता के अस्तित्व के निर्माण में अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सहायता के लिए अन्य बाहरी सहायक क्या हैं?

697]; जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड, (2022) 1 एससीसी

753, पैरा 30 [2021 आई. एन. एस. सी. 392]

17 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून, 1985।

18 जुगल किशोर रामेश्वरदास बनाम गुलबाई होरमुसजी, (1955) 2 एससीआर 857, पैरा 7 [1955 आईएनएससी 22]; कारवेल शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम प्रीमियर सी फूड्स एक्जिम (पी) लिमिटेड,

(2019) 11 एससीसी 461, पैरा 8 [2018 आईएनएससी 1008]।

गैर-हस्ताक्षरकर्ता के साथ समझौता, वह प्रश्न है जिसका हमें उत्तर देने के लिए कहा जाता है।

ii.धारा **7 (4) (**बी**)**

12. गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ एक मध्यस्थता समझौते का अनुमान समझौते के रिकॉर्ड से लगाया जाना है जिसमें पत्र, टेलेक्स, तार और अन्य दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे पत्राचार का आदान-प्रदान शामिल है।

संचार, जिसमें यह "स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से सामने आता है कि पक्षकार समान थे"।19 री सी. सी. एम. आर. वेरवाल्टुंग जी. एम. बी. एच. बनाम इंडियन ऑयल

निगम लिमिटेड, 20 इस न्यायालय ने मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विचार करते हुए न्यायालयों की भूमिका को निम्नानुसार संदर्भित किया:

“12. ...लेकिन सवाल यह है:क्या तत्काल मामले में पक्षों के बीच पत्राचार से कोई समझौता किया जा सकता है?

13. इस संबंध में याद रखने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पत्राचार का अर्थ निकाले कि क्या पक्षों के बीच कोई मन की बैठक हुई थी, जो उनके बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बना सकती है, लेकिन अदालत को पत्राचार में उपयोग की जाने वाली स्पष्ट भाषा से बाहर जाकर पक्षों के लिए एक अनुबंध बनाने का अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि कानून के कुछ उचित निहितार्थ हैं।जब तक पत्राचार से, यह स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकता है कि पक्ष शर्तों के अनुरूप थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि पत्राचार के माध्यम से उनके बीच एक समझौता अस्तित्व में आया था।अदालत को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि पक्षों ने क्या लिखा और उन्होंने कैसे काम किया और उस सामग्री से यह अनुमान लगाने के लिए कि क्या पत्राचार में व्यक्त किया गया इरादा पारस्परिक रूप से बाध्यकारी अनुबंध को अस्तित्व में लाना था।पक्षों का इरादा केवल पत्राचार में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों और इसके अर्थ से एकत्र किया जाना है और यदि यह दर्शाता है कि पक्षों के बीच मन की बैठक हुई थी और वे वास्तव में सभी भौतिक शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गए थे, तो और फिर अकेले यह कहा जा सकता है कि एक बाध्यकारी अनुबंध पत्राचार से वर्तनी करने में सक्षम था।

19 रिकमर्स वेरवाल्टुंग जीएमबीएच बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (1999) 1 एससीसी 1, पैरा 13

[1998 आई. एन. एस. सी. 436]

20 आई. बी. आई. डी.; एम. टी. एन. एल बनाम केनरा बैंक, (2020) 12 एस. सी. सी. 767, पैरा 9.3 [2019 आई. एन. एस. सी. 881] भी देखें।

723

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 724

14. अभिलेख पर पूरे पत्राचार के सावधानीपूर्वक अवलोकन से, हमारी राय है कि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था क्योंकि स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट और प्रदर्शन गारंटी की शर्तों को संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।पक्षों द्वारा स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट और प्रदर्शन गारंटी की स्वीकृति के अभाव में, कोई लागू करने योग्य समझौता अस्तित्व में नहीं आया था।दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट रूप से कुछ भी सहमत नहीं है और उनके बीच कोई लागू करने योग्य और बाध्यकारी समझौता अस्तित्व में नहीं आया है।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए पत्राचार के अलावा, ऊपर उल्लिखित पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए फैक्स संदेशों से पता चलता है कि पक्ष केवल बातचीत कर रहे थे और किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचे थे।सौदे पर बातचीत करने और बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करने के बीच एक बड़ा अंतर है।वर्तमान मामले में सौदे की बातचीत के बाद, वह चरण कभी नहीं पहुंचा जब बातचीत पूरी हो गई

एक बाध्यकारी अनुबंध को बढ़ावा देना। "

आगे बाबनराव राजाराम पुंड बनाम समर्थ बिल्डर्स और

डेवलपर्स, 21 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

“29. इस प्रकार न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे खंड के सार पर अधिक जोर दें, जो पक्षकारों के स्पष्ट इरादे और उद्देश्यों पर आधारित है ताकि वे अपने बीच संघर्ष के प्रबंधन के लिए विवाद समाधान का एक विशिष्ट रूप चुन सकें।मध्यस्थता द्वारा अपने विवाद को हल करने के लिए समझौते के सार से संबंधित पक्षों के इरादे को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।यह हमारे लिए स्पष्ट है कि खंड 18, इस मामले में, पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक बाध्यकारी संदर्भ पर विचार करता है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए था।”

पक्षों को पारस्परिक रूप से मध्यस्थता के लिए अपने अलग-अलग संदर्भों को संदर्भित करने का इरादा रखना चाहिए क्योंकि सहमति उन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का स्रोत है। 22

21 (2022) 9 एससीसी 691 [2022 आईएनएससी 935]।

22 के. के. मोदी बनाम के. एन. मोदी, (1998) 3 एस. सी. सी. 573, पैरा 17 [1998 आई. एन. एस. सी. 63]; बिहार राज्य खनिज

विकास निगम बनाम एनकॉन बिल्डर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, (2003) 7 एससीसी 418, पैरा 13

[2003 आईएनएससी 409]।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

13. धारा 7 (4) (बी) के तहत तय न्यायशास्त्र यह है कि मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता की सहमति पत्रों, तारों और लिखित संचार के अन्य रूपों के आदान-प्रदान के माध्यम से उसके आचरण से बनाई जा सकती है।23 ये पत्राचार लिखित रूप में होते हैं

समझौते का अभिलेख।स्मिता कंडक्टर बनाम यूरो मिश्र धातु मामले में, 24 यह न्यायालय

यह निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था कि क्या उसमें अपीलार्थी द्वारा किए गए कुछ पत्राचार, जो प्रत्यर्थी को संबोधित नहीं थे, विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 के तहत न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II (2) के अनुसार मध्यस्थता के लिए अपीलार्थी की सहमति दर्शाते हैं।न्यायालय ने नोट किया कि मध्यस्थता खंड वाले अनुबंधों पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, न ही अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच कोई पत्र या तार थे जहां अपीलार्थी ने इन अनुबंधों को स्पष्ट रूप से सहमति दी थी।बल्कि, यह अपीलार्थी द्वारा एक बैंक को किए गए पत्राचार पर निर्भर था, जहां उसने मध्यस्थता समझौते का अभिलेख प्रदान करने के रूप में अनुबंध की शर्तों के अनुसरण में कार्य किया था।25 इसलिए, हस्ताक्षर के अभाव में भी, मध्यस्थता के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता की सहमति उसके लिखित पत्राचार (यहां तक कि तीसरे पक्ष के साथ भी) से ली जा सकती है जो मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध के अनुसार उसके आचरण को दर्शाता है।

14. इस सिद्धांत को न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए लगातार लागू किया गया है कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता धारा 7 (4) (बी) के अनुसार मध्यस्थता समझौते का पक्षकार है।26 हमारी अदालतों और न्यायाधिकरणों ने पत्राचार में स्पष्ट भाषा का अर्थ लगाते हुए मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने के लिए पक्षों के इरादे को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त रूप से व्याख्यात्मक उपकरण विकसित किए हैं।यह भी माना गया है कि एक बार अनुबंध की शर्तों से पता चलता है कि विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का इरादा है, तो पक्ष मध्यस्थता समझौते से "बाहर नहीं निकल सकते"।27

23 शक्ति भोग फूड्स बनाम कोला शिपिंग लिमिटेड (2009) 2 एस. सी. सी. 134, पैरा 17 [2008 आई. एन. एस. सी. 1081]।

24 (2001) 7 एससीसी 728 [2001 आईएनएससी 417]।

25 आई. बी. आई. डी., पैरा 6-7।

26 यूनिसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च,

(2009) 1 एससीसी 107 [2008 आईएनएससी 1111]; पावरटेक वर्ल्ड वाइड लिमिटेड बनाम डेल्विन इंटरनेशनल

जनरल ट्रेडिंग एल. एल. सी., (2012) 1 एस. सी. सी. 361 [2011 आई. एन. एस. सी. 799]; गोविंद रबर बनाम लूइड्स ड्रेफस कमोडिटीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड, (2015) 13 एस. सी. सी. 477 [2014 आई. एन. एस. सी. 1042]।

27 यूनिसी (भारत) (ऊपर), पैरा 16-19; गोविंद रबर (ऊपर), पैरा 21-22।

725

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 726

15. वैधानिक योजना और मध्यस्थता के अस्तित्व या इरादे की कमी की व्याख्या और व्याख्या करने में इस न्यायालय के सुसंगत दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित सिद्धांत को फिर से व्यक्त किया जा सकता हैः

आई. मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध है।इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत कानून द्वारा लागू किए जाने वाले समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

ii.मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 (2) एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को मान्यता देती है, न कि रूप में।29 समझौता किसी अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में हो सकता है या यह एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

iii.धारा 7 (3) में आदेश दिया गया है कि मध्यस्थता समझौता मौखिक समझौते के विपरीत लिखित रूप में होगा।हालाँकि, समझौते का प्रमाण देने वाले दस्तावेज़ के लिखित रूप पर पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।30

iv.'धारा 2 (1) (एच) में पक्षकार को "मध्यस्थता समझौते के पक्षकार" के रूप में परिभाषित किया गया है।मध्यस्थता समझौते और उसके पक्षों का निर्धारण एक दूसरे के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, उनका अस्तित्व लिखित समझौते पर आधारित है।

v. यदि मध्यस्थता समझौते का लिखित रूप में साक्ष्य दिया जाता है जैसा कि पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ (धारा 7 (4) (ए)) में निहित है, तो समझौते के पक्ष स्पष्ट रूप से वे हैं जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

vi.यदि मध्यस्थता समझौते का लिखित रूप में साक्ष्य दिया जाता है जैसा कि दावे और बचाव (धारा 7 (4) (सी)) के बयानों वाले अभिवचनों में प्रवेश के रूप में निहित है, तो इस समझौते के पक्षकार दावे और बचाव के बयानों और उसमें किए गए स्वीकारों से स्पष्ट होंगे।

28 विद्या द्रोलिया (ऊपर), पैरा 21।

29 निमेट रिसोर्सेज इंक बनाम एस्सार स्टील्स लिमिटेड, (2000) 7 एस. सी. सी. 497, पैरा 5; बाबनराव राजाराम

पुंड (ऊपर), पैरा 15 और 29।

30 जुगल किशोर रामेश्वरदास (ऊपर), पैरा 7; रिकमर्स वेरवाल्टुंग जीएमबीएच (ऊपर), पैरा 12; शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (ऊपर), पैरा 17; कारवेल शिपिंग सर्विसेज (पी) लिमिटेड

(ऊपर), पैरा 8।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

vii.मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में भी हो सकता है यदि यह समझौते के रिकॉर्ड में निहित है जिसमें पत्रों, टेलेक्स, तार या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (धारा 7 (4) (बी) के माध्यम से संचार सहित दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान शामिल है।इन उदाहरणों में, समझौते के पक्षकारों के साथ-साथ मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व रेफरल अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा व्याख्या और निर्माण का विषय है।धारा 7 (4) (बी) के तहत जांच यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए कोई समझौता मौजूद है, और ऐसे समझौते के पक्षकार कौन हैं।

viii.रेफरल अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण, संदर्भ के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के दावे पर विचार करते समय, या एक मध्यस्थता में शामिल करने के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की आपत्ति, मुख्य रूप से धारा 7 (4) (बी) के तहत समझौते के रिकॉर्ड की जांच करेगा और पक्षों द्वारा नियोजित स्पष्ट भाषा पर विचार करेगा।

ix.एक बार स्पष्ट शर्तों का पता चलने के बाद, 31 उनका अर्थ अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्माण का मामला है।इस तरह के निर्माण का उद्देश्य पक्षों के इरादे का पता लगाना है।32 वास्तव में उपयोग किए गए शब्दों के माध्यम से हमेशा इरादे का पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टियों द्वारा नियोजित भाषा से स्वतंत्र कोई इरादा नहीं है।

x. व्यक्त शब्दों के सही अर्थ का पता लगाने के उद्देश्य से, न्यायालय या न्यायाधिकरण अनुबंध की प्रकृति और उद्देश्य, 33 और अनुबंध के गठन, कार्यान्वयन और निर्वहन के दौरान पक्षों के आचरण जैसी आसपास की परिस्थितियों पर भी विचार कर सकता है।34 व्यापारिक प्रथाओं का भी महत्व है।

31 रिकमर्स वेरवाल्टुंग जीएमबीएच (ऊपर), पैरा 13; एमटीएनएल बनाम केनरा बैंक (ऊपर),

पैरा 9.3।

32 बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बीईएससीओएम) बनाम ई. एस. सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड (2021) 6 एससीसी 718, पैरा 16 और 17; भारतीय खाद्य निगम बनाम अभिजीत पॉल 2022

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1605, पैरा 27 [2022 आई. एन. एस. सी. 1216]; लेविसन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स (छठा संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल 2016) पैरा 2.01,27.

33 बैंक ऑफ इंडिया बनाम के. मोहनदास (2009) 5 एससीसी 313, पैरा 28 [2009 आईएनएससी 417]।

34 गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 199, पैरा 11,16 [1974 आई. एन. एस. सी. 174]; मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 181,

पैरा 112 [2006 आईएनएससी 326]।

727

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 728

पक्षों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा का अर्थ निर्धारित करने में।35 अनुबंध की व्याख्या करते समय, अदालतें या न्यायाधिकरण निर्माण के सुस्थापित सिद्धांतों को अपनाते हैं।ये सिद्धांत अदालत के लिए पक्षकारों के इरादे का अनुमान लगाने के लिए दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं।

xi.चूंकि मध्यस्थता समझौता धारा 7 (4) (बी) में विनिर्दिष्ट सामग्री में निहित एक लिखित दस्तावेज से जुड़ा हुआ है और व्याख्या और निर्माण इसके पाठ पर आधारित है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 91 और 92 मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने को अक्षम करती है।36 यह एक रेफरल कार्यवाही को पूर्ण-स्तरीय परीक्षण में परिवर्तित होने से रोकने के लिए आवश्यक है। यदि धारा 7 (4) (बी) में दिए गए समझौते के रिकॉर्ड से मध्यस्थता समझौते का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो जांच समाप्त होनी चाहिए।यह दृष्टिकोण एक लिखित समझौते की आवश्यकता के अनुरूप है और अधिनियम की धारा 5 में अनुमानित महत्वपूर्ण नीतिगत विचार को भी शामिल करता है।

16. यह उपरोक्त संदर्भित कानूनी व्यवस्था, वैधानिक और साथ ही पूर्ववर्ती के संदर्भ में है कि हमें इस संविधान पीठ को संदर्भित प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है-क्या कंपनी सिद्धांत समूह भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र का हिस्सा है और क्या इसका कोई वैधानिक आधार है।

ग. कंपनी समूह सिद्धांत **i.**अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

17. मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश की राय से पूरी तरह सहमत हूं, जिन्होंने अपनी विद्वतापूर्ण व्याख्या में इस मामले पर बहुत विस्तार से विचार किया है।उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस सिद्धांत की प्रयोज्यता पर उदाहरणों की जांच की है।

18. कंपनी समूह सिद्धांत तैयार किया गया था और शुरू में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा यह निर्धारित करने के लिए लागू किया गया था कि क्या एक व्यक्ति जिसने औपचारिक रूप से मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसे इसमें पक्षकार बनाया जा सकता है।यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कानूनी सिद्धांतों में से एक है कि क्या

35 ओ. एन. जी. सी बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705, पैरा 13 [2003 आई. एन. एस. सी. 241]।

36 रूप कुमार बनाम मोहन थेदानी (2003) 6 एस. सी. सी. 595, पैरा 13,16-18 [2003 आई. एन. एस. सी. 206] देखें।

गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है।इससे पहले कि हम स्वयं सिद्धांत पर आगे बढ़ें, हमारे लिए अन्य कानूनी आधारों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित करना प्रासंगिक हो सकता है, ताकि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के एक पक्ष होने पर व्यापक न्यायशास्त्र में सिद्धांत का पता लगाया जा सके।

19. गैर-हस्ताक्षरकर्ता को एक पक्ष बनाने के लिए कानूनी आधारों को सहमति और गैर-सहमति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।सहमति संबंधी सिद्धांत जो पक्षों के आपसी इरादे को निर्धारित करने पर केंद्रित हैं, उनमें एजेंसी, निहित सहमति, और संविदात्मक अधिकारों का असाइनमेंट और हस्तांतरण शामिल हैं, और गैर-सहमति वाले सिद्धांत जो इक्विटी विचारों पर आधारित हैं, उनमें अहंकार को बदलना/कॉर्पोरेट घूंघट को भेदना, अवरोध, उत्तराधिकार और स्पष्ट अधिकार शामिल हैं।37 इन सिद्धांतों का निर्माण, चाहे सहमति से हो या गैर-सहमति से, नया नहीं है।वे संविदात्मक कानून और निगमित कानून के सामान्य सिद्धांतों से प्राप्त होते हैं।38

20. कंपनियों के समूह के सिद्धांत को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में तैयार और सिद्धांतित किया गया था ताकि विशेष रूप से यह निर्धारित किया जा सके कि क्या एक कंपनी जो एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता है, मध्यस्थता समझौते का पक्ष है या नहीं।गैरी बोर्न ने स्पष्ट किया है कि यह सिद्धांत मध्यस्थता के संदर्भ से बाहर नहीं है।39

21. इस पृष्ठभूमि के साथ, मैं अब अन्य विचारों और कानूनी परीक्षणों के साथ सिद्धांत पर चर्चा करूंगा जो इसके अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं।

22. डॉव केमिकल बनाम इसोवर सेंट गोबेन में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक अंतरिम पुरस्कार में एक फ्रांसीसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा इस सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था।40 इस मामले में, डाउ केमिकल ए. जी. और डाउ केमिकल यूरोप (डाउ केमिकल कंपनी (यू. एस. ए.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां) ने इसोवर सेंट गोबेन के साथ मध्यस्थता खंडों वाले दो अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।डाउ केमिकल फ्रांस, इन समझौतों के गैर-हस्ताक्षरकर्ता लेकिन डाउ समूह के एक सदस्य, ने इन समझौतों के तहत वितरण को प्रभावी बनाया।जब विवाद उत्पन्न हुए और इसोवर ने सभी चार डाउ कंपनियों के खिलाफ फ्रांसीसी अदालतों में मुकदमा दायर किया, दोनों हस्ताक्षरकर्ता और

37 गैरी बॉर्न, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वॉल्यूम 1 (तीसरा संस्करण, क्लूवर लॉ)

अंतर्राष्ट्रीय 2021) 1531।

38 आईबीआईडी 1525।

39 आईबीआईडी 1559।

40 आईसीसी मामला संख्या 4,131,23 सितंबर 1982।

गैर-हस्ताक्षरकर्ता डाउ कंपनियों ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की।इसोवर ने डाउ केमिकल फ्रांस और डाउ केमिकल कंपनी (यू. एस. ए.) के संबंध में एक निर्णय देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई, क्योंकि वे गैर-हस्ताक्षरकर्ता थे।दूसरी ओर, गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों ने तर्क दिया कि वे इन अनुबंधों के निष्कर्ष और प्रदर्शन में अपनी भागीदारी के कारण और कंपनियों के एक ही समूह में होने के कारण मध्यस्थता का आह्वान कर सकते हैं।

23. मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने यह निर्धारित करने के लिए फ्रांसीसी कानून लागू किया कि क्या

गैर-हस्ताक्षरकर्ता "इन कार्यवाहियों के लिए पक्षों के सामान्य इरादे के संदर्भ में पक्षकार हैं, जैसे कि यह उन परिस्थितियों से प्रतीत होता है जो निष्कर्ष को घेरती हैं और प्रदर्शन और बाद में उन अनुबंधों की समाप्ति को दर्शाती हैं जिनमें वे दिखाई देते हैं।"यह माना गया कि डाउ केमिकल

फ्रांस और डाउ केमिकल कंपनी (यू. एस. ए.) दोनों अनुबंधों की बातचीत और निष्कर्ष के केंद्र में थे। इसके अलावा, वे अनुबंधों के प्रदर्शन और उनकी बाद की समाप्ति में भी शामिल थे क्योंकि डॉव केमिकल फ्रांस ने डिलीवरी को समाप्त कर दिया था और डॉव केमिकल कंपनी (यूएसए) के पास माल के लिए ट्रेडमार्क थे और अपनी सहायक कंपनियों पर भी पूर्ण नियंत्रण था।इन तथ्यों पर भरोसा करते हुए, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों कंपनियों ने अनुबंधों के निष्कर्ष, प्रदर्शन और समाप्ति में भाग लिया।इसमें कहा गयाः

“यह ध्यान में रखते हुए कि इसके प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट न्यायिक पहचान के बावजूद, कंपनियों का एक समूह एक ही आर्थिक वास्तविकता का गठन करता है, जिसमें से मध्यस्थ न्यायाधिकरण को आई. सी. सी. नियमों के अनुच्छेद 13 (1955 संस्करण) या अनुच्छेद 8 (1975 संस्करण) के अधीन अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए।विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि समूह की कुछ कंपनियों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किए गए मध्यस्थता खंड को अन्य कंपनियों को बाध्य करना चाहिए, जो उक्त खंडों वाले अनुबंधों के समापन, प्रदर्शन या समाप्ति में अपनी भूमिका के आधार पर और कार्यवाही के सभी पक्षों के आपसी इरादे के अनुसार, इन अनुबंधों के लिए वास्तविक पक्षकार प्रतीत होते हैं या मुख्य रूप से उनके द्वारा संबंधित थे और वे विवाद जिनसे वे उत्पन्न हो सकते हैं।” 41

41 आइबीआइडी।

24. उपरोक्त उद्धरणों से, यह स्पष्ट है कि कंपनियों के एक ही समूह में सदस्यता या "एक ही आर्थिक वास्तविकता" न तो एकमात्र और न ही यह मानने के लिए मार्गदर्शक कारक थे कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियां पक्षकार थीं।बल्कि, न्यायाधिकरण का जोर पक्षों के आपसी इरादे पर था, जो अनुबंधों के समापन, प्रदर्शन और समाप्ति में उनके आचरण से एकत्र हुए थे।42

25. फ्रांसीसी मध्यस्थता न्यायाधिकरणों और अदालतों द्वारा सिद्धांत की बाद की व्याख्या और अनुप्रयोग भी काफी हद तक एक ही समूह में केवल सदस्यता के बजाय आपसी इरादे पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे गैर-हस्ताक्षरकर्ता को एक पक्ष बनाने के लिए अपने आप में असंवेदनशील माना गया है।43 दल्ला रियल में

एस्टेट एंड टूरिज्म होल्डिंग कंपनी v.धार्मिक मामलों का मंत्रालय, सरकार

पाकिस्तान की, पेरिस अपील अदालत ने पाकिस्तान सरकार (गैर-हस्ताक्षरकर्ता) के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार को लागू किया क्योंकि बातचीत में भागीदारी और अनुबंध के प्रदर्शन के माध्यम से इसका आचरण मध्यस्थता के लिए एक पक्ष होने के लिए सामान्य इच्छा को प्रतिबिंबित करता है।44 सद्भावना (पक्षों को प्रतिबद्धताओं से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए) और प्रभावशीलता (जब पक्ष मध्यस्थता खंड डालते हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि उनका इरादा मध्यस्थता द्वारा नियंत्रित किया जाना है) के सिद्धांतों के अनुसार सामान्य इच्छा का निर्धारण किया जाना चाहिए।45

26. आपसी इरादे पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी समूह के सिद्धांत और 'घूंघट को भेदने' या अहंकार को बदलने के बीच एक मौलिक अंतर पैदा होता है।पर्दा-भेदन में, मूल और सहायक कंपनियों की अलग-अलग कानूनी पहचान की अवहेलना की जाती है या इक्विटी और निष्पक्षता के विचारों (जैसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए) पर रद्द कर दिया जाता है।कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने के परिणामस्वरूप निगमित पर्दा नहीं उठाया जाता है, बल्कि यह पक्षों के आपसी इरादे की पहचान करने पर आधारित है।46

27. इस सिद्धांत को दुनिया भर में समान रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

42 बोर्न (उपरोक्त) 1561; बर्नार्ड हनोटियाउ, 'अध्याय 14:लुकास ए. मिस्टेलिस और जूलियन डी. एम. ल्यू (संस्करण) में 'ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन', अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में व्यापक समस्याएं, खंड 15 (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2006), 286। 43 जन्म (ऊपर) 1562-1563।

44 मामला सं. 9-28533, दिनांक 17 फरवरी 2011 (पेरिस कोर्ट डी 'एप्पेल)।

45 मालाकॉफ कॉर्पोरेशन बरहाद और टी. एल. ई. एम. सी. ई. एन. विलवणीकरण निवेश कंपनी बनाम अल्जीरियाई ऊर्जा कंपनी एस. ए. और हाइफल यू. एक्स. लिमिटेड, मामला सं. 21-07296, दिनांक 13 जून

2023 (पेरिस कोर्ट डी 'ऐपल)।46 जन्म (ऊपर) 1563।

28. यू. के. में, पीटरसन फ़ार्म्स इंक बनाम सी. एंड एम फ़ार्मिंग लिमिटेड, 47 में न्यायालय ने

अंग्रेजी कानून में सिद्धांत की प्रयोज्यता को अस्वीकार कर दिया।मूल और सहायक कंपनियों की अलग-अलग कानूनी पहचान को एक मौलिक कानूनी सिद्धांत माना जाता है।48 डल्ला मामले में, यूके सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार (गैर-हस्ताक्षरकर्ता) के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार को

लागू करने पर पेरिस कोर्ट ऑफ अपील से अलग रुख अपनाया।यह निर्धारित करने के लिए फ्रांसीसी कानून लागू करने के बाद भी कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कब एक पक्ष है, उसके सामने की सामग्री के आधार पर, अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार बनाने का कोई आपसी इरादा नहीं था

पाकिस्तान की एक पार्टी।49 इसी तरह, कबाब-जी एस. ए. एल. (लेबनान) बनाम कोट फूड में

समूह (कुवैत), 50 यू. के. सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार को लागू नहीं किया क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि यह अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक पक्ष था।

29. इसी तरह, सिंगापुर की अदालतों ने भी अलग कानूनी पहचान के मौलिक कॉर्पोरेट कानून सिद्धांत पर जोर देकर कंपनी समूह के सिद्धांत की प्रयोज्यता को खारिज कर दिया है।51

30. दूसरी ओर, स्विस अदालतों ने गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को उनके आचरण के आधार पर मध्यस्थता समझौते में पक्ष बनाने की अनुमति दी है, जो निहित सहमति को प्रकट करता है।स्विस संघीय न्यायालय ने माना है कि एक मध्यस्थता समझौता स्वयं स्विस निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिनियम के अनुच्छेद 178 के अनुसार लिखित रूप में होना चाहिए। तथापि, यह प्रश्न कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता ऐसे लिखित मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है, मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध की तैयारी और निष्पादन में इसकी भागीदारी के संदर्भ से निर्धारित किया जा सकता है, जो इस तरह के मध्यस्थता समझौते में पक्ष होने के अपने इरादे को दर्शाता है।52

31. अमेरिकी अदालतें भी यह निर्धारित करने के लिए स्पष्ट रूप से कंपनी समूह के सिद्धांत पर भरोसा नहीं करती हैं कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक पक्ष है।बल्कि, वे न्यायसंगत अवरोध, धारणा, छेद जैसे सिद्धांतों का उपयोग करते हैं

47 [2004] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 121 (कम); मेयर और कॉमनलिटी एंड सिटीजन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन बनाम अशोक संचेती, [2008] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1283।

48 बैंक ऑफ टोक्यो लिमिटेड बनाम करूण, [1987] एसी 45।

49 [2010] यूकेएससी 46. 50 [2021] यूकेएससी 48.

51 मनुचर स्टील हांगकांग लिमिटेड बनाम स्टार पैसिफी सी लाइन पीटीई लिमिटेड [2014] एसजीएचसी 181।

52 X._____ और अन्य v. Z._____, 4A _ 115/2003; A._____, v. B._____ Ltd., 4A _ 376/2008; X._____ _ _ v. Y._____ इंजीनियरिंग और Y._____ S. p.A., 4A _ 450/2013।

निगमित पर्दा, अहंकार को बदलना, और छूट।53 जीई एनर्जी में हाल के निर्णय में

पावर कन्वर्जन बनाम आउटकुंपू स्टेनलेस, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया

न्यायसंगत अवरोध पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता को मजबूर कर सकता है जहां एक हस्ताक्षरकर्ता गैर-हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ अपना दावा करने के लिए अनुबंध की शर्तों पर भरोसा कर रहा है।54 अमेरिकी अदालतों ने यह मानने के लिए निहित सहमति, 55 तीसरे पक्ष के हितग्राही, 56 और सामान्य संविदात्मक और एजेंसी कानून सिद्धांतों पर भी भरोसा किया है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक पक्ष है।57

32. यह तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि एक मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों का निर्धारण जो आपसी इरादे पर आधारित है, इस संदर्भ के बिना हो सकता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों के समूह का हिस्सा है या नहीं।वास्तव में, एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विद्वान, बर्नार्ड हनोटियाउ का तर्क है कि डॉव केमिकल में पुरस्कार की गलत व्याख्या की गई है ताकि समूह की कंपनियों के सिद्धांत को जन्म दिया जा सके।बल्कि, वह इस बात पर जोर देते हैं कि डाउ का वास्तविक निहितार्थ यह है कि यह हमें यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता अपने आचरण के संदर्भ में एक पक्ष है जो अपनी सहमति देता है।इस संदर्भ में, उनका तर्क है कि कंपनियों के समूह का कोई भी संदर्भ अनावश्यक है क्योंकि एक ही समूह के भीतर सदस्यता इस बात की जांच में एक निर्धारक कारक नहीं है कि मध्यस्थता समझौते का पक्ष कौन है। 58

33. उपरोक्त विश्लेषण के निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

आई. विभिन्न क्षेत्राधिकार यह निर्धारित करने के लिए सहमति और गैर-सहमति दोनों कानूनी सिद्धांतों का उपयोग करते हैं कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है।59

ii.कंपनी समूह सिद्धांत को समूह के प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट न्यायिक पहचान की परवाह किए बिना लागू किया जाता है जब

53 जीई एनर्जी पावर कन्वर्जन फ्रांस एसएएस कॉर्प।, एफ. के. ए. कन्वर्टिम एस. ए. एस. बनाम आउटकुम्पू

स्टेइनलेस यूएसए, एल. एल. सी., आदि।, मामला सं. 18-1048 (1 जून 2020)।54 आइबीआइडी।

55 मैकब्रो प्लानिंग एंड देव। को. वी.त्रिभुज एलेक।कंस्ट्रक्टर।कं. इंक., 741 एफ. 2 डी 342 (11 वां सिर।

1984).

56 नौरू फॉस्फेट रॉयल्टीज, इंक. बनामड्रैगो डाइक इंटरेस्ट्स, इंक. 138 एफ. 3 डी 160 (5 वां सिर।

1998).

57 सरहंक ग्रुप बनाम ओरेकल कॉर्प, 404 एफ. 3 डी 657 (दूसरा सिर। 2005)।

58 बर्नार्ड हनोटियाउ, 'मध्यस्थता के लिए सहमतिःक्या हम एक समान दृष्टि साझा करते हैं?' (2011) 27(4) आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल 539।

59 जन्म (ऊपर), 1531।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 734

वे अनुबंध के गठन, प्रदर्शन और समाप्ति में अपनी भूमिका के आधार पर एक समान आर्थिक वास्तविकता साझा करते हैं।यह सिद्धांत मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए सभी पक्षों के आपसी इरादे पर आधारित है।60

iii.इस सिद्धांत की स्वीकृति का क्षेत्राधिकारों में अत्यधिक विरोध किया जाता है।यह सिद्धांत फ्रांस में विकसित किया गया था और हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों की आपसी सहमति पर जोर देकर इसे लागू किया जाता है।61

iv.दूसरी ओर, यूनाइटेड किंगडम 62 और सिंगापुर 63 जैसे देशों ने इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और एक ही समूह के सदस्यों के अलग-अलग कानूनी व्यक्तित्वों की मौलिकता पर जोर दिया है।

v. स्विट्जरलैंड 64 और यू. एस. ए. 65 जैसे कुछ क्षेत्राधिकारों ने उन शर्तों में कंपनी समूह के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है।हालांकि, वे अन्य कानूनी सिद्धांतों का आह्वान करते हैं ताकि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष माना जा सके (जैसे आचरण, निहित सहमति, संविदात्मक और एजेंसी सिद्धांत)।vi. अमेरिकी अदालतें भी एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को पक्षकार ठहराने के लिए पूरी तरह से समानता के विचारों (गैर-सहमति) पर भरोसा करती हैं, जैसे कि जब वे न्यायसंगत अवरोध और घूंघट भेदन/अहंकार को बदलते हैं।66

ii.कंपनियों के समूह के सिद्धांत पर भारतीय पूर्वाभास

34. अब मैं अपनी अदालतों द्वारा कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने पर विचार करूंगा और उन सिद्धांतों को तैयार करूंगा जो पूर्ववर्ती से उत्पन्न होते हैं।

60 डाउ केमिकल (ऊपर)।

61 डल्ला रियल एस्टेट (ऊपर) [पेरिस कोर्ट डी 'एप्पेल]; मालाकॉफ कॉर्पोरेशन (ऊपर)।

62 पीटरसन फ़ार्म्स (ऊपर)।63 मनुचर स्टील (ऊपर)।

64 X._____ और अन्य v. Z._____, 4A _ 115/2003; A._____, v. B._____ Ltd., 4A _ 376/2008; X._____ v. Y._____ इंजीनियरिंग और Y._____ S. p.A., 4A _ 450/2013।

65 जी. ई. ऊर्जा शक्ति रूपांतरण (ऊपर); मैकब्रो योजना और देव। कंपनी (ऊपर); नौरू फॉस्फेट रॉयल्टीज, इंक. (ऊपर); सरहंक समूह (ऊपर)।

66 जी. ई. ऊर्जा शक्ति रूपांतरण (ऊपर)।

35. मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस सिद्धांत पर भारतीय मामले-कानून के विस्तृत विश्लेषण से सहमत हूं।भारत में कानून की स्थिति को व्यापक रूप से विभाजित किया जा सकता है क्योंकि यह क्लोरो कंट्रोल्स (उपरोक्त) में निर्णय से पहले और बाद में मौजूद थी।मैं पहले ही अपनी राय के भाग बी (ii) में धारा 7 (4) (बी) की व्याख्या करने और उसे लागू करने के निर्णयों का उल्लेख कर चुका हूं। उसमें उद्धृत निर्णय एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के मध्यस्थता का एक पक्ष होने की संभावना को मान्यता देते हैं।मैंने उन निर्णयों में तर्क का भी उल्लेख किया है जहां न्यायालय ने समझौते के रिकॉर्ड की जांच की है और पक्षों की सहमति के साथ स्पष्ट भाषा के आधार पर एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का निर्माण किया है।

36. क्लोरो कंट्रोल्स से पहले इस न्यायालय के दो फैसले

(ऊपर), अर्थात्, सुकन्या होल्डिंग्स 67 और इंडोविंड एनर्जी 68 एक पर आधारित थे

धारा 7 की सख्त व्याख्या और यह माना जाता है कि किसी समझौते के पक्ष इसके हस्ताक्षरकर्ताओं तक ही सीमित हैं।

37. क्लोरो कंट्रोल्स बनाम सेवेरेन ट्रेंट (सुप्रा) के मामले से इस स्थिति में एक निश्चित बदलाव आया था।एक बहु-पक्षीय बहु-संविदात्मक विवाद के परिप्रेक्ष्य में, अनुबंधों के पक्षों और मध्यस्थता समझौते के पक्षों में विषमता के बावजूद, अधिनियम की धारा 45 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक याचिका का एक मुकदमे में नेतृत्व किया गया था।न्यायालय की धारा 45 में "किसी भी व्यक्ति", "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला" और "करेगा" शब्दों और वाक्यांशों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करने के लिए पहली बार संदर्भ का दायरा बढ़ाया।

38. इसने नोट किया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ या उसके द्वारा दावा किया जाता है जो मूल रूप से मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो कंपनी समूह का सिद्धांत "गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबंध या बहन या माता-पिता की चिंताओं" को मध्यस्थता के लिए बाध्य कर सकता है, यदि परिस्थितियाँ प्रदर्शित करती हैं कि सभी पक्षों का आपसी इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबंध दोनों को बाध्य करना था।" 69 न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया:

"72. यह इस सिद्धांत को विकसित करता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है बशर्ते कि ये लेनदेन कंपनियों के समूह के साथ हों और पार्टियों का बाध्य करने का स्पष्ट इरादा हो।

67 सुकनर्या होल्डिंग्स बनाम जायेश एच पांड्या (2003) 5 एससीसी 531 [2003 आईएनएससी 230]।68 इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम वेसकेयर (इंडिया) लिमिटेड (2010) 5 एस. सी. सी. 246 [2010 आई. एन. एस. सी. 246]।

69 क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर), पैरा 71।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 736

दोनों, हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष।दूसरे शब्दों में, "पक्षों का इरादा" एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे मध्यस्थता के दायरे में हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को शामिल करने से पहले स्थापित किया जाना चाहिए।

73. एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता या तीसरे पक्ष को उनकी पूर्व सहमति के बिना मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है, लेकिन यह केवल असाधारण मामलों में ही होगा।न्यायालय मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ प्रत्यक्ष संबंध की कसौटी, विषय-वस्तु की प्रत्यक्ष समानता और पक्षों के बीच एक समग्र लेनदेन होने के समझौते से इन अपवादों की जांच करेगा। लेन-देन एक मिश्रित प्रकृति का होना चाहिए जहां सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने और सामूहिक रूप से विवाद पर असर डालने के लिए पूरक या सहायक समझौतों की सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना मातृ समझौते का प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है।

(जोर दिया गया) 39।अपनी राय में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने उपरोक्त पैराग्राफ 72 और 73 के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास के बारे में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की चिंता पर विचार किया है, और दोनों पैराग्राफ का सही ढंग से मिलान किया है।मैं उसी बात से सहमत हूँ।

40. इस संदर्भ में, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि क्लोरो नियंत्रण न्यायालय अधिनियम के भाग II में धारा 45 की व्याख्या कर रहा था, विशेष रूप से, वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना"।मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल करने का निष्कर्ष मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष होने के उनके व्युत्पन्न दावे पर केंद्रित था।इस प्रकार कंपनी समूह के सिद्धांत को अधिनियम की धारा 45 के वाक्यांशों की व्याख्या में मान्यता मिली। इसके अलावा, व्युत्पन्न कार्रवाई को पारित करने के लिए, हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के "एक स्पष्ट इरादे" का पता लगाना था, अदालत द्वारा चित्रित परिस्थितियों के माध्यम से, अर्थात,i) समझौते के पक्षकार के साथ सीधा संबंध,(ii) विषय वस्तु की समानता,(ग) लेन-देन की समग्र प्रकृति और (घ) अनुबंध का परस्पर संबद्ध निष्पादन।41. 2015 में, भारत के विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट ने अधिनियम की धारा 45 की इस व्याख्या को स्वीकार किया। अनुवर्ती संशोधनों में, अधिनियम के भाग I में धारा 8 को धारा की भाषा को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया था

45; 70 इस प्रकार, घरेलू मध्यस्थता में पक्षकार भी व्युत्पन्न क्षमता में मध्यस्थता के संदर्भ के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

42. अब हम कंपनियों के समूह के आवेदन की जांच करेंगे।

बाद के मामलों में सिद्धांत।ड्यूरो फेलगुएरा में, एस. ए. बनाम.गंगावरम

पोर्ट लिमिटेड, 71 क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में मान्यता प्राप्त सिद्धांत का अनुप्रयोग उस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया गया था।

43. अब तक, उदाहरण उन स्थितियों से संबंधित थे जहां पक्षों ने अदालतों के पूर्व-संदर्भित क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था।चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तूरी एंड संस लिमिटेड, 72 के मामले में प्रवर्तन स्तर पर अदालत से संपर्क किया गया था।73 न्यायालय ने अधिनियम की धारा 35 के तहत शेयरों के बाद के खरीदार के खिलाफ एक मध्यस्थ निर्णय को लागू करने की अनुमति दी, जिसमें "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" वाक्यांश की व्याख्या की गई।हालांकि, अदालत के समक्ष पेश की गई कुछ दलीलों के जवाब में, फैसले में कंपनी समूह के सिद्धांत से संबंधित व्याख्याएं देखी गईं।उस संदर्भ में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"23. जैसे-जैसे कानून विकसित हुआ है, यह माना गया है कि आधुनिक व्यावसायिक लेनदेन अक्सर कई परतों और समझौतों के माध्यम से किए जाते हैं।कंपनियों के एक समूह के भीतर लेनदेन हो सकते हैं।

70 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की संशोधित धारा 8 (1) निम्नानुसार है:

"8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक मध्यस्थता समझौता है।—

(1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, विवाद के सार पर अपना पहला बयान जमा करने की तारीख के बाद लागू नहीं होता है, तो, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करता है जब तक कि वह यह नहीं मानता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।"

71 (2017) 9 एससीसी 729 [2017 आईएनएससी 1026]।72 (2018) 16 एससीसी 413 [2018 आईएनएससी 394]।

73 प्रत्यर्थी ने अपनी सहायक कंपनी के शेयर एक के. सी. पलानीसामी को बेच दिए, जिन्होंने इस कंपनी की बकाया देनदारियों का निर्वहन करने का बीड़ा उठाया।इस समझौते के खंड 14 ने के. सी. पलानीसामी के कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को अपनी पसंद के किसी अन्य व्यक्ति को बेचने या हस्तांतरित करने के अधिकार को मान्यता दी, बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता कंपनी के प्रबंधन और वित्तीय पहलुओं के संबंध में समझौते की शर्तों को स्वीकार करता हो।इस समझौते में एक मध्यस्थता खंड भी शामिल था।के. सी. पलानीस्वामी ने अपीलार्थी को 95 प्रतिशत शेयर प्राप्त करने के लिए नामित किया जो उसे हस्तांतरित किए जाने थे।इसके बाद, विवाद उत्पन्न हुए और एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उन्हें शेयर प्रमाण पत्र और स्वामित्व दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया।अपीलार्थी को मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने के लिए प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था।

जिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रवेश किया है, वे एक ही समूह के भीतर हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों संस्थाओं को बांधने के इरादे को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।एक मध्यस्थता समझौते द्वारा बाध्य एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को धारण करने में, अदालत लेनदेन को उस व्यावसायिक भावना के अनुरूप एक अर्थ प्रदान करके मामले का रुख करती है जिसका उन्हें

श्रेय दिया जाना था।इसलिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता का संबंध, विषय-वस्तु की समानता और लेन-देन की समग्र प्रकृति जैसे कारक संतुलन में वजन करते हैं।कंपनियों के समूह का सिद्धांत अनिवार्य रूप से पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से आयोजित इरादे की पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए है, जहां परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बांधना था।प्रभावी उद्देश्य व्यावसायिक व्यवस्था के वास्तविक सार को स्पष्ट करना और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की एक स्तरित संरचना से बाहर निकालना है, किसी ऐसे व्यक्ति को बांधने का इरादा जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन जिसने हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व ग्रहण किया है।" 74

44. न्यायालय ने कंपनी समूह के सिद्धांत पर भरोसा नहीं किया।फिर भी, चेरन (उपरोक्त) यह प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी को हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता के संबंध, विषय-वस्तु की समानता और लेन-देन की समग्र प्रकृति जैसे कारकों के आधार पर मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष होने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।अदालत के लिए ऐसे समझौते का निर्माण करना भी संभव है जहां एक व्यावसायिक व्यवस्था का इरादा स्पष्ट हो और गैर-हस्ताक्षरकर्ता इस तरह की व्यावसायिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए अपने आचरण से बंधे हों।

45. अमित लालचंद शाह बनाम ऋषभ में बाद का निर्णय

उद्यम 75 एक और उदाहरण है जहाँ इस न्यायालय ने एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को व्यावसायिक प्रभावशीलता के आधार पर संबंधित अनुबंधों में मध्यस्थता समझौते में पक्षकार बनने की अनुमति दी है, यह देखते हुए कि सभी समझौतों को एक ही वाणिज्यिक परियोजना के लिए निष्पादित किया गया था।डिस्कवरी एंटरप्राइजेज, 76 के बाद के निर्णय में इस दृष्टिकोण को नोट किया गया था, जहां विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने नोट किया है:

74 आईबीआईडी, पैरा 23।

75 (2018) 15 एससीसी 678 [2018 आईएनएससी 450]।

76 ओ. एन. जी. सी. बनाम डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (2022) 8 एस. सी. सी. 42 [2022 आई. एन. एस. सी. 483]।

" अमित लालचंद में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत का आह्वान नहीं किया, बल्कि यह क्लोरो कंट्रोल्स पर निर्भर था कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मातृ समझौते में मध्यस्थता खंड से बाध्य होगा, क्योंकि यह एक परस्पर

जुड़े समझौते का एक पक्ष है, जिसे एक सामान्य वाणिज्यिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाता है।" 77

(जोर दिया गया)

46. रेकिट बेंकिजर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम रेयंडर्स लेबल प्रिंटिंग

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 78 न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने न तो मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किए और न ही समझौते की बातचीत या निष्पादन के साथ कोई कारणात्मक संबंध था, इसलिए मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति देने के इरादे को समझा नहीं जा सका।इसलिए, गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते से बाध्य नहीं था।79 इस प्रकार, रेकिट में, न्यायालय ने सिद्धांत को लागू करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे का पता लगाने के दृष्टिकोण पर वापस लौट आया, हालांकि इसके परिणामस्वरूप गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता में एक पक्ष नहीं बनाया गया।

47. एम. टी. एन. एल. बनाम केनरा बैंक 80 वह निर्णय है जिसने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को स्वीकार किया, इसके सिद्धांतों को तैयार किया, और मध्यस्थता समझौते के पक्षकार के रूप में एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता, सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. को मान्यता देकर उन्हें कार्यवाही में लागू किया। न्यायालय ने कहाः

" 10.5.कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा मध्यस्थता में लागू किया गया है, जहां समूह की कंपनियों में से एक द्वारा एक मध्यस्थता समझौता किया जाता है; और गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबंध, या बहन, या मूल चिंता, मध्यस्थता समझौते से बाध्य माना जाता है, अगर मामले के तथ्य और परिस्थितियां प्रदर्शित करती हैं कि समूह में हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबंध दोनों को बांधना सभी पक्षों का आपसी इरादा था। सिद्धांत में प्रावधान है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है जहां मूल या धारक कंपनी, या कंपनियों के समूह का एक सदस्य मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है और समूह की गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई बातचीत या प्रदर्शन में लगी हुई है

77 आईबीआईडी, पैरा 28।

78 (2019) 7 एससीसी 62 [2019 आईएनएससी 700]।79 आईबीआईडी, पैरा 12।

80 (2020) 12 एससीसी 767 [2019 आईएनएससी 881]।

वाणिज्यिक अनुबंध, या अनुबंध द्वारा बाध्य होने के अपने इरादे का संकेत देने वाले बयान, गैर-हस्ताक्षरकर्ता भी संबंधित अनुबंधों से बाध्य और लाभान्वित होगा।

10.6.वे परिस्थितियाँ जिनमें "कंपनियों के समूह" सिद्धांत को मूल कंपनी के गैर-हस्ताक्षरकारी संबंध को बांधने के लिए लागू किया जा सकता है, या मध्यस्थता में किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जा सकता है, यदि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के बीच सीधा संबंध है; विषय-वस्तु की प्रत्यक्ष समानता; पक्षों के बीच लेनदेन की समग्र प्रकृति।एक "समग्र लेन-देन" एक ऐसे लेन-देन को संदर्भित करता है जो प्रकृति में परस्पर जुड़ा हुआ है; या, जहां समझौते का प्रदर्शन सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरक या सहायक समझौते की सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना संभव नहीं हो सकता है, और सामूहिक रूप से विवाद पर असर डालता है।

10.7.कंपनियों के समूह के सिद्धांत को उन मामलों में भी लागू किया गया है जहां मजबूत संगठनात्मक और वित्तीय संबंधों के साथ एक तंग समूह संरचना है, ताकि एक एकल आर्थिक इकाई, या एक एकल आर्थिक वास्तविकता का गठन किया जा सके।ऐसी स्थिति में मध्यस्थता समझौते के तहत हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक साथ बंधे हुए हैं।यह विशेष रूप से तब लागू होगा जब एक कंपनी के धन का उपयोग समूह के अन्य सदस्यों को वित्तीय रूप से समर्थन या पुनर्गठन के लिए किया जाता है।"

48. अंत में, ओ. एन. जी. सी. बनाम डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, 81 में निर्णय

इस बात पर कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक पक्षकार था, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया था, न्यायालय ने इस मुद्दे पर अकादमिक साहित्य और न्यायिक घोषणाओं की व्यापक समीक्षा की।न्यायालय ने संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

"40. यह तय करने में कि क्या कंपनियों के समूह के भीतर एक कंपनी जो मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी इसके द्वारा बाध्य होगी, कानून निम्नलिखित कारकों पर विचार करता हैः

((क) पक्षकारों का पारस्परिक आशय;

((ii) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध;

81 डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (ऊपर)।

((ग) विषय-वस्तु की समानता;

((iv) लेन-देन की समग्र प्रकृति और (v) अनुबंध का निष्पादन।

41. 1996 के अधिनियम की धारा 7 में सहमति और पार्टी की स्वायत्तता को रेखांकित किया गया है। हालांकि, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को एक सहमति के सिद्धांत पर बाध्य माना जा सकता

है, जो एजेंसी और असाइनमेंट पर या गैर-सहमति के आधार पर स्थापित किया गया है जैसे कि अवरोध या अहंकार को बदलना।

49. उपरोक्त उदाहरणों से जो सामने आता है वह यह है कि:

आई. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अपनाया गया और लागू किया गया, जहां न्यायालय ने इस सिद्धांत को धारा 45 में "दावे के माध्यम से या उसके तहत" वाक्यांश में पढ़ा।इसने अभिनिर्धारित किया कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबंध या बहन या मूल कंपनी एक मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष हो सकती है यदि इस आशय के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं का आपसी इरादा है।आपसी इरादे को निर्धारित करने के लिए, न्यायालय ने प्रत्यक्ष संबंध, विषय-वस्तु की प्रत्यक्ष समानता और एक समग्र लेनदेन जैसे कारकों को निर्धारित किया जहां कई समझौतों का प्रदर्शन अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।82

ii.धारा 8 के 2015 के संशोधन के अनुसार, न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए मध्यस्थता के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं का एक समग्र संदर्भ दिया कि सभी समझौतों को एक ही वाणिज्यिक परियोजना, 83 के लिए निष्पादित किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कंपनी समूह के सिद्धांत का उल्लेख किए बिना।84

iii.इसके बाद, इस न्यायालय ने सिद्धांत की परीक्षा के रूप में आपसी इरादे पर भरोसा किया। हालाँकि, यह मध्यस्थता के अपने आपसी इरादे को निर्धारित करने के लिए समझौते की बातचीत और निष्पादन के साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता के कारण संबंध को निर्धारित करके क्लोरो (सुप्रा) से विचलित हो गया।85

82 क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर), पैरा 72 और 73।इसके बाद चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर), पैरा 23 में इसका पालन किया गया।

83 ऋषभ एंटरप्राइजेज (ऊपर), पैरा 25। 84 डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (ऊपर), पैरा 28. 85 रेकिट बेंकिजर (ऊपर), पैरा 12।

iv.एम. टी. एन. एल. (ऊपर) में, न्यायालय ने इस सिद्धांत के तहत परीक्षण का सारांश दिया कि यह कंपनियों के समूह के हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों सदस्यों को बांधने के लिए पक्षों के सामान्य इरादे पर आधारित है।इस तरह के सामान्य इरादे का अनुमान बातचीत में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी और अनुबंध के प्रदर्शन (रेकिट बेंकिजर (सुप्रा) के समान), या उसके बयानों से लगाया जा सकता है जो एक पक्ष होने के उसके इरादे का संकेत देते हैं।86 साथ ही, न्यायालय ने आपसी इरादे को निर्धारित करने के लिए क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में परीक्षण का भी उल्लेख किया।87 अंत में, न्यायालय ने पक्षकारों के इरादे के किसी भी संदर्भ के बिना, एक तंग समूह संरचना या एकल आर्थिक वास्तविकता होने पर सिद्धांत को लागू करने का निर्णय लिया।88

हालांकि, अदालत ने अंततः गैर-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निहित या मौन सहमति पर भरोसा किया, जो उसके आचरण से प्रमाणित है, यह मानने के लिए कि वह एक पक्ष है।89

v. डिस्कवरी (ऊपर) में, न्यायालय ने उपरोक्त मामलों की व्यापक समीक्षा की और उनमें तैयार किए गए विभिन्न परीक्षणों को समाप्त कर दिया।इसने अभिनिर्धारित किया कि (ए) पक्षों का पारस्परिक आशय, (बी) हस्ताक्षरकर्ता के साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता का संबंध, (सी) विषय-वस्तु की समानता, (डी) लेन-देन की समग्र प्रकृति, और (ई) अनुबंध का प्रदर्शन, यह निर्धारित करने के लिए कारक हैं कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक पक्ष है या नहीं।90 ये कारक आपसी इरादे पर जोर देते हैं और क्लोरो कंट्रोल्स और रेकिट बेंकिजर में निर्धारित परीक्षणों से आकर्षित होते हैं, लेकिन एकल आर्थिक वास्तविकता के परीक्षण को एक निर्धारक कारक के रूप में शामिल नहीं करते हैं, जैसा कि एम. टी. एन. एल. (ऊपर) में आयोजित किया गया है।

50. इस मोड़ पर, हमारे विचार के लिए निर्दिष्ट एक सामान्य प्रश्न को स्पष्ट करना और उसका उत्तर देना आवश्यक है, अर्थात, क्या कंपनी समूह का सिद्धांत अधिनियम की धारा 8 और 45 में निहित है। धारा 8 और 45 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" उत्तराधिकार और व्युत्पन्न अधिकारों के उदाहरणों से संबंधित है।विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपनी राय के भाग एफ (1) और (2) में इस पहलू पर बहुत विस्तार से चर्चा की है।

86 एम. टी. एन. एल. (उपर्युक्त), पैरा 10.5।87 आई. बी. आई. डी., पैरा 10.

88 आईबीआईडी, पैरा 10.7।89 आईबीआईडी, पैरा 10.16।

90 डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (ऊपर), पैरा 40।

और यह अभिनिर्धारित किया कि इस सिद्धांत को धारा 8 और 45 में आधार नहीं बनाया जा सकता है और इस हद तक, क्लोरो नियंत्रण (ऊपर) गलत तरीके से तय किया गया है।मैं उनके कारणों और तर्कों से पूरी तरह सहमत हूं।

डी**.** धारा **7** के संदर्भ में कंपनियों के समूह का सिद्धांत

51. इस संदर्भ में, हमें यह निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है कि क्या कंपनी समूह का सिद्धांत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है, जो मध्यस्थता समझौते और उससे संबंधित पक्षों की अवहेलना करता है।इस सिद्धांत के अनुकूलन पर संदेह किया गया है, और यही इस संदर्भ का कारण है।मेरी राय के भाग सी (आई) में सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से निपटने के दौरान, यह देखा गया कि सिद्धांत किसी भी वैचारिक विलक्षणता को प्राप्त नहीं कर सका, और यह विवादित बना हुआ है।शायद, यह दो कारणों से है:सबसे पहले, डाउ (उपरोक्त) में प्रयुक्त 'एकल आर्थिक वास्तविकता' अभिव्यक्ति किसी कंपनी के अलग कानूनी व्यक्तित्व की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, और दूसरा, सिद्धांत को पक्षों के इरादे को निर्धारित

करने के लिए लागू किया जाता है, जो पूरी तरह से तथ्य-आधारित है।इन कारणों से, सिद्धांत गतिशील बना हुआ है, यदि अनिश्चित नहीं है, और कई योग्यताओं और अपवादों के अधीन है।साथ ही, आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करते हुए, इस सिद्धांत को अपनाने के कुछ फायदे हैं। मेरा मानना है कि इस सिद्धांत को अधिनियम की वैधानिक व्यवस्था के भीतर लाना आवश्यक है, ताकि अदालत या मध्यस्थता न्यायाधिकरण इसे पक्षों के इरादे को समझने के लिए एक सिद्धांत के रूप में लागू कर सके।धारा 7 (4) (बी) के तहत न्यायिक प्रक्रिया के भीतर कंपनियों के समूह के सिद्धांत को शामिल करना आवश्यक है, जहां एक अदालत या मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता समझौते और उसके पक्षों के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए कहा जाता है।

52. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का संयुक्त अध्ययन हमें सूचित करता है कि सामान्य दीवानी अदालतों को छोड़कर, पक्षों के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र उनके बीच मध्यस्थता करने के अनुबंध से उत्पन्न होना चाहिए।एक मध्यस्थता समझौता, एक अनुबंध होने के नाते, अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होना चाहिए, एक मौखिक समझौते के विपरीत, लेकिन पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है।लिखित मध्यस्थता समझौता पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ के रूप में हो सकता है, या समझौते के रिकॉर्ड में प्रमाणित किया जा सकता है।धारा 7 (4) (बी) लिखित सामग्री निर्धारित करती है जिससे एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की सहमति और इरादे को अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समझा जा सकता है।

743

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 744

53. एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के साथ एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व व्याख्या और निर्माण का विषय है।पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त स्पष्ट शब्द न्यायालय को पक्षकारों के इरादे और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए उनकी सहमति का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं।व्यक्त शब्दों के सही अर्थ का पता लगाने के लिए, न्यायालय या न्यायाधिकरण अनुबंध की प्रकृति और उद्देश्य और अनुबंध के गठन, प्रदर्शन और निर्वहन के दौरान पक्षों के आचरण जैसी आसपास की परिस्थितियों पर गौर कर सकता है।अनुबंध की व्याख्या और निर्माण करते समय, अदालतें या न्यायाधिकरण अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को अपना सकते हैं, जो उचित निर्णय और निर्धारण में सहायता और सहायता करते हैं।कंपनी समूह का सिद्धांत ऐसा ही एक सिद्धांत है।इसे अदालतों या मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा समझौते के रिकॉर्ड की व्याख्या करते समय यह निर्धारित करने के लिए अपनाया जा सकता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी इसमें एक पक्ष है या नहीं।

54. यद्यपि भारत में कंपनी समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग अब तक धारा 7 से स्वतंत्र रहा है, धारा 7 (4) (बी) मामले-कानून के साथ इसका संयोजन दर्शाता है कि दोनों के तहत जांच पक्षकारों के मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के आपसी इरादे को निर्धारित करने पर आधारित है।अनुबंध के निष्पादन में उनके आचरण से पक्षों की आपसी मंशा स्पष्ट है और यह जांच धारा 7 (4) (बी)

न्यायशास्त्र और कंपनी समूह के सिद्धांत के लिए समान है।यहां तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के उदाहरण भी कंपनियों के एक ही समूह में गैर-हस्ताक्षरकर्ता होने से परे अतिरिक्त कारकों को देखते हैं, जैसे कि विषय-वस्तु की समानता, लेन-देन की समग्र प्रकृति और पारस्परिक इरादे को निर्धारित करने के लिए अनुबंधों के प्रदर्शन की परस्पर निर्भरता।

55. चूँकि धारा 7 (4) (बी) और कंपनी समूह के सिद्धांत के तहत अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष मौलिक मुद्दा एक ही है, इसलिए सिद्धांत को धारा 7 (4) (बी) के भीतर शामिल किया जा सकता है।नतीजतन, समझौते का रिकॉर्ड जो अनुबंध के गठन, प्रदर्शन और समाप्ति में गैर-हस्ताक्षरकर्ता के आचरण और हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ इसके प्रत्यक्ष संबंध, विषय-वस्तु की समानता और लेनदेन की समग्र प्रकृति जैसी आसपास की परिस्थितियों का प्रमाण देता है, का व्यापक रूप से उपयोग गैर-हस्ताक्षरकर्ता के साथ मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए।इस जांच में, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के कंपनियों के एक ही समूह का हिस्सा होने का तथ्य इसके निष्कर्ष को मजबूत करेगा।इस दृष्टि से, कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 7 में वैधानिक रूप से निहित होगा।

ई. निष्कर्ष

56. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान मुख्य न्यायाधीश के फैसले से सहमत होते हुए, मेरे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

I. विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक समझौता मौखिक समझौते के विपरीत लिखित रूप में होना चाहिए, लेकिन पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है।धारा 7 (4) (बी) के तहत, एक अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण यह निर्धारित करेगा कि क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता समझौते के लिए एक पक्ष है, समझौते के रिकॉर्ड में पक्षों द्वारा नियोजित स्पष्ट भाषा की व्याख्या करके, अनुबंध के गठन, प्रदर्शन और निर्वहन की आसपास की परिस्थितियों के साथ। अनुबंध की व्याख्या और निर्माण करते समय, अदालतें या न्यायाधिकरण अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को अपना सकते हैं, जो उचित निर्णय और निर्धारण में सहायता और सहायता करते हैं। कंपनी समूह का सिद्धांत ऐसा ही एक सिद्धांत है।

II. ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिद्धांत 91 भी मध्यस्थता समझौते में पक्षकार बनने के गैर-हस्ताक्षरकर्ता के इरादे का पता लगाने पर आधारित है।इस सिद्धांत के लिए हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ प्रत्यक्ष संबंध, विषय-वस्तु की समानता, लेन-देन की समग्र प्रकृति और अनुबंध के प्रदर्शन जैसे अतिरिक्त कारकों से इरादे को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है।III. चूंकि धारा 7 (4) (बी) और कंपनी समूह के सिद्धांत के तहत अदालत या मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा जांच का उद्देश्य समान है, इसलिए इस सिद्धांत को धारा 7 (4) (बी) के तहत शामिल किया जा सकता है ताकि अदालत या मध्यस्थता न्यायाधिकरण मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के

सच्चे इरादे और सहमति का निर्धारण कर सके।इस सिद्धांत को निश्चितता और कानून के व्यवस्थित विकास के उद्देश्य से धारा 7 (4) (बी) की वैधानिक व्यवस्था के भीतर शामिल किया गया है।

IV. धारा 8 और 45 में "के माध्यम से या उसके तहत दावा" अभिव्यक्ति का उद्देश्य एक व्युत्पन्न अधिकार प्रदान करना है और यह एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता समझौते का पक्ष बनने में सक्षम नहीं बनाता है।क्लोरो कंट्रोल्स (सुप्रा) में समूह का पता लगाने का निर्णय

91 जैसा कि डिस्कवरी एंटरप्राइजेज (ऊपर) के पैरा 40 में वर्णित है।

745

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v.सैप इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर. [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

धारा 8 और 45 में "के माध्यम से या उसके तहत दावा" वाक्यांश के माध्यम से कंपनियों का सिद्धांत गलत है।धारा 2 (1) (एच) और धारा 7 में 'पक्ष' अभिव्यक्ति 'उनके माध्यम से या उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों' से अलग है।यह संविधान पीठ को भेजे गए शेष प्रश्नों का उत्तर देता है।

कानून के संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।